



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022025-261092
CG-DL-E-17022025-261092

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 12, 2025/माघ 23, 1946

No. 50]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 12, 2025/MAGHA 23, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम निष्कर्ष

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2025

मामला सं. एडी (एसएसआर) - 02/2024

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “सोडियम साइट्रेट” के आयातों पर पाटनरोधी शुल्कों के संबंध में दूसरी निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच – के संबंध में।

फा.सं. 7/08/2024-डीजीटीआर — समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (“पाटनरोधी नियमावली”) को ध्यान में रखते हुए।

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. मेसर्स डेफोडिल फामकिम प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे “आवेदक” कहा गया है) ने चीन जन.गण. (जिसे आगे यहां “संबद्ध देश” कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडियम साइट्रेट (जिसे आगे “संबद्ध सामान” अथवा “विचाराधीन उत्पाद” कहा गया है) के आयातों के संबंध में दूसरी निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने और उन पर पाटनरोधी शुल्क की मात्रा जारी रखने की मांग करते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे यहां “प्राधिकारी” कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन पत्र दायर किया है।
2. चीन जन.गण. से संबद्ध सामानों के आयात के संबंध में मूल पाटनरोधी जांच प्राधिकारी द्वारा 28.02.2014 को अधिसूचना संख्या 14/23/2013-डीजीएडी के तहत शुरू की गई थी। मूल जांच में अंतिम जांच परिणाम प्राधिकारी द्वारा 26.02.2015 को जारी किया गया था, जिसमें चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी। उक्त सिफारिश को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 19/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 20.05.2015 के तहत स्वीकार कर लिया गया था और चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों पर अंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए गए थे।
3. प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 7/21/2019-डीजीटीआर दिनांक 25.10.2019 के द्वारा पहली निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की। दिनांक 30.04.2020 के अपने अंतिम जांच परिणामों के माध्यम से, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. से संबद्ध सामानों के आयातों पर संशोधित पाटनरोधी शुल्क को 5 वर्षों की एक और अवधि के लिए जारी रखने की सिफारिश की, जिसे बाद में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया और शुल्कों को 5 वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 19.05.2020 की अधिसूचना संख्या 8/2020-सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से जारी रखा गया। दिनांक 19.05.2020 से 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाए गए शुल्क 18 मई, 2025 तक वैध हैं।
4. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत प्रमाणित आवेदन पत्र के आधार पर और घरेलू उद्योग को पाटन की संभावना तथा परिणामी क्षति सिद्ध करते हुए, आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं संतुष्ट होने पर तथा नियमावली के नियम 23(1ख) के अनुसार, संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के संबंध में लागू शुल्कों को लगाया जाना जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने और यह जांच करने के लिए 30 सितंबर, 2024 को अधिसूचना संख्या 7/08/2024-डीजीटीआर द्वारा जांच शुरू की थी कि क्या विद्यमान पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग में पाटन जारी रहने अथवा बार-बार होने तथा परिणामस्वरूप क्षति होने की संभावना है।

ख. प्रक्रिया

5. संबद्ध जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

- क. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरू करने की कार्यवाही से पूर्व वर्तमान पाटनरोधी आवेदन-पत्र की प्राप्ति के संबंध में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।
- ख. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में दूसरी निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित 30 सितंबर, 2024 को सार्वजनिक सूचना जारी की।
- ग. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों, आयातक/प्रयोक्ता, एसोसिएशनों, घरेलू उद्योग, अन्य ज्ञात भारतीय उत्पादकों और आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पत्तों/ईमेल के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 30 सितंबर, 2024 की जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भेजी। हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी गई थी कि वे निर्धारित स्वरूप और तरीके में संगत सूचना दें और नियमावली के नियम 6(2) और 6(4) के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने ज्ञात अनुरोध दें।

- घ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा संबद्ध देश की सरकार को भारत में उसके दूतावास के माध्यम से आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति उपलब्ध कराई।
- ड. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रति भी उन्हें संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पतों के साथ भेजी गई थी।
- च. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी:
- मेसर्स एएचए इंटरनेशनल कं, लिमिटेड
 - मेसर्स कॉग्रिस लिमिटेड
 - मेसर्स जियांग्सू गुओक्सिन यूनियन एनर्जी कं, लिमिटेड
 - मेसर्स शेडोंग एनसाइन इंडस्ट्री कं, लिमिटेड
 - मेसर्स शंघाई नुविट बायो-टेक कं, लिमिटेड
- छ. उत्तर में संबद्ध देश के निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर, निर्यातक प्रश्नावली – भाग II तथा आर्थिक हित प्रश्नावली भी दायर की:
- मेसर्स जियांग्सू गुओक्सिन यूनियन एनर्जी कं, लिमिटेड
 - मेसर्स शेडोंग एनसाइन इंडस्ट्री कं, लिमिटेड
- ज. संबद्ध देश के जिन उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है अथवा जांच में सहयोग नहीं किया है, उन्हें जांच में असहयोगी माना गया है।
- झ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाते हुए, भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावली भेजी:
- मेसर्स ऐमकेम इंग्रीडिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड
 - मेसर्स कोका-कोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 - मेसर्स गोपाल एंटरप्राइजेज
 - मेसर्स इशिता ड्रग्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - मेसर्स कियारा इंग्रीडिएंट्स आइएनसी.
 - मेसर्स एनडीसी ड्रग केमिकल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
 - मेसर्स पी डी नवकर बायो-केम प्राइवेट लिमिटेड
 - मेसर्स पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
 - मेसर्स प्रकाश केमिकल्स एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड
 - मेसर्स रतनचंद संस
- ञ. उत्तर में किसी आयातक/प्रयोक्ता ने निर्धारित समय के भीतर उत्तर नहीं दिया है और कोई आयातक/प्रयोक्ता ने प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है।

- ट. उपर्युक्त विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों के अलावा, मैसर्स वांग फार्मास्युटिकल्स एंड केमिकल्स ने 5 दिसंबर, 2024 को भारत में संबद्ध सामानों का उत्पादक होने का दावा करते हुए वर्तमान जांच का समर्थन व्यक्त किया। तथापि, उपर्युक्त उत्पादक द्वारा क्षति संबंधी कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है।
- ठ. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों और संबंधित मंत्रालय/विभाग को आर्थिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) जारी की। आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर घरेलू उद्योग और उत्तरदाता निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसी भी प्रयोक्ता/आयातक ने आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया।
- ड. सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी कि वे जांच दल के सहित अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर ईमेल करें।
- ढ. वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से पिछले तीन वर्षों और जांच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयातों के लेन-देनवार ब्यौरे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गए थे। सिस्टम एंड डाटा मैनेजमेंट महानिदेशालय (डीजी सिस्टम्स) से भी अनुरोध किया गया था कि वे क्षति की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयातों के लेन-देनवार ब्यौरे उपलब्ध कराएं और वे भी प्राधिकारी को प्राप्त हो गए थे। इस प्रकार प्राप्त सूचना की तुलना आवेदकों द्वारा दावे किए गए अनुसार डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रकाशित सार-सूचना के साथ की गई है और कोई अंतर नोट नहीं किया गया था। अतः, प्राधिकारी ने इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए भारत में संबद्ध सामानों के आयातों की मात्रा और मूल्य के परिकलन के लिए डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रकाशित आयात सूचना पर विश्वास किया है।
- ण. क्षति रहित कीमत (एनआईपी) सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत और निर्माण तथा बिक्री लागत के आधार पर निर्धारित की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- त. वर्तमान जांच के लिए प्राधिकारी के लिए अपनाई गई जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 (12 माह) है। क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च, 2023 और जांच की अवधि शामिल है।
- थ. आवेदक, उत्तरदाता उत्पादकों और संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा दी गई सूचना का सत्यापन/डिस्क जांच प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था। आवश्यक संशोधन/सुधार, जहां भी लागू था, के साथ उस सत्यापन सूचना पर ही वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए विश्वास किया गया है।
- द. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने 8 जनवरी, 2025 को हाइब्रिड मोड में आयोजित मौखिक सुनवाई में उनके विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को अवसर भी प्रदान किया। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में भाग लिया, उन्हें 13 जनवरी, 2025 तक लिखित अनुरोध और उसके बाद यदि कोई प्रत्युत्तर है तो 16 जनवरी, 2025 तक लिखित अनुरोध दायर करने का अवसर प्रदान किया गया था। हितबद्ध पक्षकारों को यह भी निर्देश दिया गया था कि उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर वे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा करें और हितबद्ध पक्षकारों की सूची प्राधिकारी द्वारा सभी पक्षकारों को भेजी गई है।
- ध. इस जांच प्रक्रिया के दौरान अब तक वर्तमान जांच में साक्ष्य के साथ तथा संगत मानी गई सीमा तक सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर उपयुक्त रूप से विचार किया गया है और इस अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा उन्हें हल किया गया है।
- न. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई है। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और वह सूचना गोपनीय मानी गई है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय

आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर दें।

प. जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने इससे इंकार किया है, अथवा अन्यथा वर्तमान जांच प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना नहीं दी है अथवा जांच में काफी बाधा डाली है वहां प्राधिकारी ने उन पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचार/टिप्पणियां रिकॉर्ड की हैं।

फ. प्राधिकारी ने वर्तमान अंतिम जांच परिणामों में सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा उठाए गए सभी तर्कों और उपलब्ध कराई गई सूचना पर इस सीमा तक विचार किया है कि वे साक्ष्यों द्वारा समर्थित हैं और वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक माने जाते हैं।

ब. नियम 16 के अनुसार, जांच के आवश्यक तथ्य ज्ञात इच्छुक पक्षों को 27 जनवरी, 2025 के प्रकटीकरण कथन के माध्यम से बताए गए थे और इच्छुक पक्षों को मूल रूप से उस पर टिप्पणी करने के लिए 3 फरवरी, 2025 तक का समय दिया गया था। कुछ इच्छुक पक्षों ने समय के और विस्तार की मांग की और ऐसे अनुरोधों पर विचार करने पर, प्रकटीकरण कथन पर टिप्पणी करने की समय सीमा 6 फरवरी, 2025 दोपहर 2 बजे तक बढ़ा दी गई। इच्छुक पक्षों से प्रकटीकरण कथन पर प्राप्त टिप्पणियों पर, इस अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना में, प्रासंगिक और गैर-दोहरावदार पाए जाने की सीमा तक विचार किया गया है।

भ. इस अंतिम निष्कर्ष में '****' गोपनीय आधार पर एक इच्छुक पार्टी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी का प्रतिनिधित्व करता है और नियमों के तहत प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार विचार किया जाता है।

म. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 यू.एस. डॉलर = 83.69 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

6. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- जांच में शामिल उत्पाद उत्तरदाता द्वारा उत्पादित और बेचा गया सोडियम साइट्रेट है। विनिर्देशन श्रेणी में 20-100 मेश और 12-40 मेश शामिल हैं; पैकेज किस्म में 25 किग्रा/बैग, 500 किग्रा/बैग और 1,000 किग्रा/बैग शामिल हैं। उत्पाद का उपयोग खाद्य योज्य, डिटर्जेंट और औद्योगिक उपयोग के रूप में किया जा सकता है।
- भारत को निर्यातित विचाराधीन उत्पाद और घरेलू बाजार में बेचे गए या अन्य देशों को निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद के बीच भौतिक/तकनीकी/रासायनिक विशेषताओं में कोई अंतर नहीं है।
- उत्तरदाता द्वारा उत्पादित उत्पाद और प्राधिकारी द्वारा परिभाषित उत्पाद के बीच कोई अंतर नहीं है।

ग. 2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

7. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) और समान वस्तु के संबंध में निम्नानुसार अनुरोध किए हैं:

- दूसरी निर्णायक समीक्षा (एसएसआर) आवेदन पत्र में विचाराधीन उत्पाद "सोडियम साइट्रेट" है।
- सोडियम साइट्रेट एक रासायनिक यौगिक है जो मोनो-सोडियम साइट्रेट, डिसोडियम साइट्रेट और ट्राई-सोडियम साइट्रेट के रूप में आता है। सोडियम साइट्रेट साइट्रिक एसिड का सोडियम नमक है। साइट्रिक एसिड की तरह इसका स्वाद खट्टा होता है। अन्य लवणों की तरह इसका स्वाद भी नमकीन होता है।
- सोडियम साइट्रेट का उपयोग मुख्य रूप से एक एक्सपैक्टोरेंट और यूरिन अल्कनाइजर के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग दवा सहायता के रूप में और डेयरी उद्योगों में खाद्य योज्य के रूप में भी किया जाता है जो पनीर निर्माण और पेय पदार्थों की पूर्ति करते हैं। यह एक जल उपचार रसायन और एक प्रयोगशाला अभिकर्मक भी है।

- iv. सोडियम साइट्रेट का लेनदेन निम्नलिखित नामों से किया गया है और ऐसे सभी नामों को कृपया पीयूसी की परिभाषा के भाग के रूप में माना जाना चाहिए जैसा कि पिछली जांचों में किया गया है:
- क) सोडियम साइट्रेट
 - ख) ट्राई सोडियम साइट्रेट
 - ग) ट्राई सोडियम साइट्रेट डाइहाइड्रेट
 - घ) सोडियम साइट्रेट डाइहाइड्रेट
 - ङ.) ट्राइबेसिक सोडियम साइट्रेट
 - च) सोडियम साइट्रेट ट्राइबेसिक डाइहाइड्रेट
 - छ) सोडियम साइट्रेट डिबेसिक सेक्विहाइड्रेट
 - ज) सोडियम साइट्रेट मोनोबेसिक बायोक्स्ट्रा
- v. विचाराधीन उत्पाद को अनुप्रयोगों के आधार पर अलग-अलग तरीके से वर्णित किया जा सकता है। अनुप्रयोगों के आधार पर, यह औद्योगिक, खाद्य सामग्री, फार्मा ग्रेड (आईपी/वीपी/यूएसपी), अभिकर्मक, मछली ग्रेड हो सकता है। वर्तमान याचिका में सोडियम साइट्रेट के सभी रूप, सभी प्रकार और सभी संभावित विवरण शामिल हैं। इसके अलावा, इसमें सोडियम साइट्रेट के सभी वैकल्पिक नाम शामिल हैं।
- vi. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क उप-शीर्ष 29181520 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के तहत आयात किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है क्योंकि अन्य शीर्षों में उत्पाद के आयात को भी पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है।
- vii. चीन जन.गण. से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद और भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। वर्तमान मामले में, दोनों उत्पाद तकनीकी विशेषताओं, समान अंतिम उपयोग, तकनीकी और वाणिज्यिक प्रतिस्थापन और टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।
- viii. चूंकि वर्तमान आवेदन पत्र चीन जन.गण. से सोडियम साइट्रेट के आयात पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की दूसरी निर्णायक समीक्षा के लिए है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के क्षेत्र पर विचार करें जैसा कि मूल जांच के बाद पूर्व में की गई पहली निर्णायक समीक्षा में पाया गया है।

ग. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

8. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. के मूल का अथवा वहां से निर्यातित "सोडियम साइट्रेट" है।
9. वर्तमान जांच एक दूसरी निर्णायक समीक्षा जांच होने के नाते, विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही रहता है जो पहली निर्णायक समीक्षा में है। पहली निर्णायक समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:
10. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद सोडियम साइट्रेट है। संबद्ध सामानों का उपयोग मुख्य रूप से एक एक्सपैक्टोरेट और यूरिन एल्कोनाइजर के रूप में किया जाता है। सोडियम साइट्रेट एक रासायनिक यौगिक है जो मोनो-सोडियम साइट्रेट, डिसेडियम साइट्रेट और ट्राई-सोडियम साइट्रेट के रूप में आता है।

11. संबद्ध सामान सीमा शुल्क उप-शीर्ष 29181520 के अंतर्गत आते हैं। हालाँकि, उक्त सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं, और जाँच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं हैं। शुल्क लगाने और संग्रह के लिए वस्तुओं का विवरण मान्य होगा।
 12. यह एक निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र मूल और बाद की समीक्षा जांच में समान ही है। मूल जांच में उल्लिखित विचाराधीन निम्नलिखित था:
 “वर्तमान जांच के उद्देश्य के लिए विचाराधीन उत्पाद “सोडियम साइट्रेट” है। यह एक रासायनिक यौगिक है जो मोनोसोडियम साइट्रेट, डिसोडियम साइट्रेट और ट्राई-सोडियम साइट्रेट के रूप में आता है। यह साइट्रिक एसिड का सोडियम साल्ट है और इसका स्वाद खट्टा और नमकीन होता है। सोडियम साइट्रेट का उपयोग मुख्य रूप से फार्मा उद्योगों में एक एक्सपेक्टोरेंट और यूरिन अल्केनाइज़र के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग दवा सहायता, डेयरी उद्योगों में खाद्य योज्य, जल उपचार में प्रयोगशाला अभिकर्मक, पेय पदार्थों में अम्लता नियामक, पनीर बनाते समय तेलों के लिए एक पायसीकारक और भोजन में एक एंटीऑक्सीडेंट आदि के रूप में भी किया जाता है।
 विचाराधीन उत्पाद का लेन-देन निम्नलिखित वैकल्पिक नामों से भी किया जा सकता है: - क. सोडियम साइट्रेट ख. ट्राई सोडियम साइट्रेट ग. ट्राई सोडियम साइट्रेट डाइहाइड्रेट घ. सोडियम साइट्रेट डाइहाइड्रेट ड. ट्राइबेसिक सोडियम साइट्रेट च. सोडियम साइट्रेट ट्राइबेसिक डाइहाइड्रेट छ. सोडियम साइट्रेट डाइबेसिक सेस्क्विहाइड्रेट ज. सोडियम साइट्रेट मोनोबेसिक बायोएक्सट्रा।
 सोडियम साइट्रेट को सीमा शुल्क उपशीर्षक 29181520 के तहत सीमा प्रशुल्क के अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह वर्तमान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।”
 13. "समान वस्तु" की परिभाषा से संबंधित नियम 2(घ) निर्दिष्ट करता है कि "समान वस्तु" का अर्थ ऐसी वस्तु है जो जांच के तहत वस्तु के सभी मामलों में समान या समान है, या ऐसी वस्तु की अनुपस्थिति में, जांच के तहत वस्तु के समान विशेषताओं वाली कोई अन्य वस्तु है।
 14. "समान वस्तु" शब्द की उपरोक्त परिभाषा से यह नोट किया जाता है कि समान वस्तु को जांच के तहत वस्तु के सभी मामलों में समान या समान होना चाहिए। समान वस्तु शब्द के क्षेत्र में वे वस्तुएं भी शामिल होंगी, जिनकी विशेषताएं जांच के अधीन वस्तुओं से काफी मिलती-जुलती हैं, बशर्ते कि सभी मामलों में समान या एक जैसी वस्तुएं न हों।
 15. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों और संबद्ध देश से आयातित सामानों में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों भौतिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता दोनों का परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग करते हैं। प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक द्वारा विनिर्मित उत्पाद संबद्ध देश से भारत में आयातित किए जा रहे संबद्ध सामानों की समान वस्तु है।
10. समान वस्तु के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में निम्नानुसार प्रवधान है:
- “समान वस्तु” से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;
11. "समान वस्तु" शब्द की उपरोक्त परिभाषा से यह नोट किया जाता है कि समान वस्तु को जांच के अधीन वस्तु के सभी पहलुओं में समान या एक जैसी होना चाहिए। समान वस्तु शब्द के क्षेत्र में वे वस्तुएं भी शामिल होंगी जिनकी विशेषताएं जांच के अधीन वस्तु से बहुत मिलती-जुलती हों, बशर्ते कि सभी पहलुओं में समान या एक जैसी वस्तुएं न हों।

12. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु और विचाराधीन उत्पाद के बीच समानता के बारे में कोई विवाद नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित सामान नियमावली के अनुसार समान वस्तु हैं। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। इस प्रकार, प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के क्षेत्र और अभिप्राय से संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु हैं।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

घ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

13. घरेलू उद्योग के पहलू और आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर अनुरोध निम्नलिखित हैं;
- अन्य उत्पादकों की गैर-भागीदारी की जांच प्राधिकारी द्वारा की जानी चाहिए।
 - भारत में पीयूसी के करीब एक दर्जन उत्पादक हैं और पीयूसी पर मूल जांच शुरू होने के बाद से समर्थकों की संख्या लगातार कम हो रही है (याचिका के अनुसार, प्रथम एसएसआर में चार से वर्तमान एसएसआर में मात्र दो रह गई है)।
 - अन्य उत्पादकों द्वारा गैर-भागीदारी अन्य गैर-भागीदारी उत्पादकों की लाभप्रदता और प्रदर्शन पर गंभीर संदेह पैदा करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य सभी उत्पादक बेहतर मीट्रिक दिखा रहे हैं और क्षति के कोई संकेत नहीं हैं और परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग की एक विषम छवि पेश करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा जानबूझकर उन्हें अलग रखा गया है।

घ. 2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

14. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- मेसर्स डेफोडिल फार्माकेम प्राइवेट लिमिटेड आवेदक है और भारत में सोडियम साइट्रेट का सबसे बड़ा उत्पादक है और उसका कुल भारतीय उत्पादन में 45-50% तक का प्रमुख अनुपात है। आवेदक मूल जांच में तथा पहली निर्णायक समीक्षा में भी घरेलू उद्योग था तथा आवेदक संबद्ध सामानों के किसी आयातक/निर्यातक से संबद्ध नहीं है, न ही उसने स्वयं संबद्ध सामानों का आयात किया है। इस प्रकार, आवेदक इस मामले में सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए घरेलू उद्योग है।
 - आवेदक के अलावा दो उत्पादकों अर्थात् मेसर्स इंडिया फॉस्फेट, मेसर्स सुनील केमिकल्स ने आवेदन का समर्थन किया है। एक अन्य उत्पादक अर्थात् मेसर्स वांग फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल्स ने जांच की शुरुआत के बाद आवेदन का समर्थन किया है। प्राधिकारी को मेसर्स वांग फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल्स को भी इस मामले में समर्थक के रूप में मानना चाहिए। आवेदक के पास मेसर्स इंडिया फॉस्फेट, मेसर्स सुनील केमिकल्स के साथ भारतीय उत्पादन में 60-65% हिस्सा है और मेसर्स वांग फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल्स के साथ यह हिस्सा 65-70% है।
 - मूल जांच के समय भारत में 6 उत्पादक थे, जो पहली निर्णायक समीक्षा और वर्तमान समीक्षा के दौरान 11 हो गए हैं। जबकि पहली निर्णायक समीक्षा में याचिकाकर्ता के पास कुल भारतीय उत्पादन में 32% हिस्सा और समर्थकों के साथ 61% हिस्सा था, वर्तमान आवेदन में आवेदक के पास अकेले कुल भारतीय उत्पादन में 45-50% हिस्सा है और समर्थकों के साथ आवेदक का हिस्सा 65-70% (मेसर्स वांग फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल्स के बिना 60-65%) की सीमा में है। इस प्रकार, आवेदन अब भारतीय उत्पादन की उच्च मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है और समर्थन सीमा के संदर्भ में निर्यातकों द्वारा आरोपित नहीं किया गया है जो आवेदन की प्रतिनिधि प्रकृति को देखते हुए अकेले प्रासंगिक है।

- iv. वर्तमान में भारत में 11 उत्पादक हैं और इन उत्पादकों में से आवेदक सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसकी कुल भारतीय उत्पादन में 45-50% हिस्सेदारी है। उत्पादक एक एमएसएमई इकाई है। पिछली जांच और वर्तमान आवेदन में आवेदक और समर्थकों का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका - 1

क्र. सं.	उत्पादक का नाम	स्थिति
मूल जांच		
1	मेसर्स पॉसी फामकिम प्राइवेट लिमिटेड (वर्तमान में मेसर्स डेफोडिल फामकिम प्राइवेट लिमिटेड)	आवेदक
2	मेसर्स सुनील केमिकल्स	समर्थक
3	मेसर्स अमिजल केमिकल्स (सूचना के अनुसार सृजित क्षमता)	तटस्थ
4	मेसर्स सुजाता केमिकल्स (सूचना के अनुसार सृजित क्षमता)	तटस्थ
5	मेसर्स वासा फामकिम प्राइवेट लिमिटेड (सूचना के अनुसार सृजित क्षमता)	तटस्थ
6	मेसर्स अडानी फामकिम प्राइवेट लिमिटेड (सूचना के अनुसार सृजित क्षमता)	तटस्थ
पहली निर्णायक समीक्षा जांच		
1	मेसर्स पॉसी फामकिम प्राइवेट लिमिटेड (वर्तमान में मेसर्स डेफोडिल फामकिम प्राइवेट लिमिटेड) (भारतीय उत्पादन में 32% हिस्सेदारी)	आवेदक
2	मेसर्स अडानी फामकिम प्राइवेट लिमिटेड	समर्थक
3	मेसर्स अल्पाइन लैब्स	समर्थक
4	मेसर्स इंडिया फॉस्फेट	समर्थक
5	मेसर्स सुनील केमिकल्स	समर्थक
6	मेसर्स अमीजल केमिकल्स	तटस्थ
7	मेसर्स सुजाता केमिकल्स	तटस्थ
8	मेसर्स वासा फामकिम प्राइवेट लिमिटेड	तटस्थ
9	मेसर्स देवेन्द्र कीर्ति फामकिम प्राइवेट लिमिटेड	तटस्थ
10	मेसर्स बांग फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल्स	तटस्थ
11	मेसर्स इशिता ड्रग्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	तटस्थ
दूसरी निर्णायक समीक्षा आवेदन पत्र (वर्तमान जांच)		
1	मेसर्स डेफोडिल फामकिम प्राइवेट लिमिटेड - (पूर्व में मेसर्स पॉसी फामकिम प्राइवेट लिमिटेड) (भारतीय उत्पादन में 45-50% हिस्सा)	आवेदक
2	मेसर्स इंडिया फॉस्फेट	समर्थक
3	मेसर्स सुनील केमिकल्स	समर्थक
4	मेसर्स बांग फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल्स (जांच शुरू होने के बाद जांच का समर्थन किया)	समर्थक
5	मेसर्स अडानी फामकिम प्राइवेट लिमिटेड	तटस्थ
6	मेसर्स अल्पाइन लैब्स	तटस्थ
7	मेसर्स अमीजल केमिकल्स	तटस्थ
8	मेसर्स सुजाता केमिकल्स	तटस्थ
9	मेसर्स वासा फामकिम प्राइवेट लिमिटेड	तटस्थ

क्र. सं.	उत्पादक का नाम	स्थिति
10	मेसर्स देवेन्द्र कीर्ति फार्माकिम प्राइवेट लिमिटेड	तटस्थ
11	मेसर्स इशिता ड्रग्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	तटस्थ

- v. व्यावहारिक रूप से, सबसे बड़ा उत्पादक आवेदक है तथा तीन अन्य सबसे बड़े उत्पादक आवेदन का समर्थन कर रहे हैं। जिन पक्षों ने समर्थन व्यक्त नहीं किया है, वे या तो बहुत छोटे उत्पादक हैं या संबद्ध सामान उनके कुल उत्पादन का केवल एक छोटा हिस्सा हैं। इस प्रकार, भारत में सोडियम साइट्रेट के घरेलू उद्योग का इस मामले में अच्छा प्रतिनिधित्व है।
- vi. समर्थक उत्पादकों से भी क्षति की जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए गए। तथापि, कठिनाई यह रही है कि समर्थक, जो छोटी इकाइयाँ हैं तथा अन्य रसायनों का उत्पादन भी करती हैं, संबद्ध सामानों के लिए पाटनरोधी आवेदन प्रारूपों द्वारा अपेक्षित क्षति डेटा तैयार नहीं कर सकीं। इकाइयों के पास वांछित व्यापक तथा तकनीकी डेटा को बनाए रखने तथा प्रस्तुत करने के लिए समर्थन प्रणाली नहीं है तथा इकाइयों की ऐसी चुनौतियों को याचिका में कम भागीदारी के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।
- vii. आवेदक तथा अन्य उत्पादकों के सामने आई पाटित आयातों से चुनौतियाँ समान हैं तथा आवेदक का निष्पादन ऐसे अन्य उत्पादकों की वास्तविक स्थिति का भी प्रतिनिधित्व करता है।

घ. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

15. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में “घरेलू उद्योग” निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

“(ख) “घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।”

16. चीन जन.गण. से संबद्ध सामानों पर विद्यमान पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखने तथा दूसरी निर्णायक समीक्षा की जांच की शुरुआत के लिए आवेदन पत्र मेसर्स डेफोडिल फार्माकिम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। यह नोट किया जाता है कि आवेदक ने जांच अवधि/क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया तथा वह संबद्ध देश से संबद्ध उत्पाद के किसी निर्यातक/आयातक से भी संबद्ध भी नहीं है।
17. इसके अतिरिक्त, आवेदन में दी गई जानकारी से पता चलता है कि आवेदक के अलावा भारत में संबद्ध सामानों के 10 अन्य उत्पादक हैं तथा आवेदक के पास कुल भारतीय उत्पादन में ***% (रेंज: 45-50%) हिस्सा है। ऐसे 10 अन्य उत्पादकों में से दो उत्पादकों अर्थात् मेसर्स इंडिया फॉस्फेट तथा मेसर्स सुनील केमिकल्स ने जांच आरंभ होने से पूर्व आवेदन का समर्थन किया है तथा एक अन्य उत्पादक अर्थात् मेसर्स वांग फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल्स ने अपने पत्र दिनांक 05.12.2024 के माध्यम से जांच का समर्थन किया है। आवेदक के पास मेसर्स इंडिया फॉस्फेट और मेसर्स सुनील केमिकल्स के साथ कुल भारतीय उत्पादन में ***% (रेंज: 60-65%) का हिस्सा है, जो मेसर्स वांग फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल्स के समर्थन के साथ ***% (रेंज: 65-70%) है।
18. आवेदक और उपरोक्त समर्थकों के अलावा, आवेदक ने मेसर्स अदानी फार्माकिम प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स अल्पाइन लैब्स, मेसर्स अमीजल केमिकल्स, मेसर्स सुजाता केमिकल्स मेसर्स वासा फार्माकिम प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स देवेन्द्र कीर्ति फार्माकिम प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स इशिता ड्रग्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी कंपनियों को भारत में संबद्ध सामानों के उत्पादकों के रूप में पहचाना है, लेकिन ऐसे उत्पादकों ने न तो वर्तमान जांच का समर्थन किया है और न ही विरोध किया है।

19. अतः, रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करते हुए, प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से आवेदक/याचिकाकर्ता को पात्र घरेलू उद्योग मानते हैं।
20. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि अन्य उत्पादकों की गैर-भागीदारी की जांच प्राधिकारी द्वारा की जानी चाहिए तथा समर्थकों की संख्या में लगातार कमी आ रही है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसे सभी ज्ञात अन्य उत्पादकों को वर्तमान जांच की शुरुआत के बारे में सूचित किया गया था, लेकिन ऐसे अन्य पक्षकारों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यह भी नोट किया जाता है कि नियम 2(ख) के तहत पात्रता शर्तों की जांच चल रही जांच के संदर्भ में की जानी चाहिए, और संतुष्ट किया जाना चाहिए न कि विरोधी पक्षकारों द्वारा अतीत में संपन्न किसी अन्य जांच के समर्थन या विरोध की तुलना में की जानी चाहिए। जहां तक वर्तमान जांच के तथ्यों का संबंध है, आवेदन पत्र नियम 2(ख) के मानदंडों को पूरा करता है। आवेदक का अकेले कुल भारतीय उत्पादन में ***% (रेंज: 45-50%) हिस्सा है और समर्थकों के साथ यह हिस्सा ***% (रेंज: 65-70%) है।
21. इस तर्क के संबंध में कि अन्य उत्पादकों द्वारा भाग न लेने से अन्य गैर-भागीदारी उत्पादकों की लाभप्रदता और निष्पादन पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि निर्यातकों ने ऐसे तर्क उठाए हैं, लेकिन ऐसे तर्कों का समर्थन करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। वर्तमान जांच में विचार की गई क्षति संबंधी सूचना पाटनरोधी नियमावली के तहत अपेक्षित "घरेलू उद्योग" से संबंधित है और अन्य इच्छुक पक्षकारों द्वारा उठाए गए संदेहों पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि वे किसी भी विपरीत तथ्य द्वारा समर्थित नहीं हैं।

ड. गोपनीयता संबंधी मुद्दे

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

22. गोपनीयता के मुद्दे के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - i. दिनांक 7 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना संख्या 10/2018 के अनुलग्नक I में समर्थकों के लिए प्रकटीकरण का एक विशिष्ट मानक का प्रावधान है। हालाँकि, याचिकाकर्ता व्यापार सूचना की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है।
 - ii. याचिका के अनुलग्नक 2.3 में, दायर समर्थन पत्रों में क्षमता, उत्पादन और बिक्री के लिए सूचीबद्ध संख्याएँ शामिल नहीं हैं। यह प्राधिकारी की व्यापार सूचना का स्पष्ट उल्लंघन है। घरेलू उद्योग ने भी इस तरह की अत्यधिक गोपनीयता के लिए कोई उचित कारण नहीं दर्शाया है।

ड. 2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

23. गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - i. उत्तरदत्ता निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में और भाग II के उत्तर में अत्यधिक गोपनीयता अपनाई है और सीमित स्थानों पर सूचीकरण भी दिया है, जिससे निर्यातकों के दावों को किसी भी निष्पक्ष तरीके से समझना मुश्किल हो गया है।
 - ii. ऐसी जानकारी के बारे में कोई सूचीकरण या सीमा प्रदान नहीं की जाती है जो संभावना पहलुओं के मूल्यांकन में प्रासंगिक है और गोपनीयता के ऐसे अत्यधिक उपयोग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
 - iii. यहां तक कि बुनियादी जानकारी जैसे कि विश्वव्यापी कारपोरेट संरचना चार्ट, संबंधित कंपनियों की सूची, भारत को निर्यात प्रवाह चार्ट और घरेलू प्रवाह चार्ट को बिना किसी ठोस कारण के गोपनीय रखा जाता है।

- iv. प्राधिकारी यह जांच करें है कि क्या उत्तरदाता निर्यातकों के मामले में निर्यात श्रृंखला पूरी हो गई है क्योंकि इस संबंध में बुनियादी जानकारी प्रतिक्रियाओं के एनसीवी संस्करण में प्रकट नहीं की गई है।

ड. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

24. सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

“गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।”

25. नियम 6(7) की अपेक्षानुसार प्राधिकारी ने एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा उन्हें प्रस्तुत साक्ष्य जांच में प्रतिभागी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया। यह सूचना जांच में प्रतिभागी अन्य हितबद्ध पक्षकारों में उस साक्ष्य का आदान प्रदान करने के निर्देशों के साथ प्रतिभागी हितबद्ध पक्षकारों में परिचालित की गई थी।
26. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच उन दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी, संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक था गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और वह सूचना गोपनीय मानी गई है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहां कहीं संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर दें। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी व्यापार संबंधी संवेदी सूचना को गोपनीय होने का दावा किया है।
27. इस तर्क के संबंध में कि आवेदक ने सूचीबद्ध रूप में समर्थक उत्पादकों से संबंधित सूचना नहीं दी है, यह नोट किया जाता है कि आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर में समर्थकों सहित संबद्ध सामानों के कुल भारतीय उत्पादन में आवेदक का हिस्सा निहित है।

च. बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी) सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

28. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
- i. याचिकाकर्ता ने निर्मित सामान्य मूल्य (सीएनवी) की गणना के लिए दो तरीके सुझाए हैं, जिनमें से एक याचिकाकर्ता की उत्पादन लागत (सीओपी) का उपयोग करना है या तीसरे देश, इस मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात कीमतों का उपयोग करना है। सभी जांचों में प्राधिकारी की सुसंगत प्रथा के अनुसार और

- विचाराधीन उत्पाद की पिछली दो जांचों में भी, प्राधिकारी को याचिकाकर्ता के सीओपी डेटा का उपयोग करके सीएनवी निर्धारित करना चाहिए।
- ii. प्राधिकारी सीएनवी गणना में याचिकाकर्ता द्वारा विचार किए गए कच्चे माल की कीमतों को सत्यापित करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डेटा में कोई त्रुटि नहीं है।
 - iii. चूंकि इस जांच में उत्तरदाता निर्यातकों ने समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर दाखिल किया है, इसलिए निवल निर्यात कीमत (एनईपी) के निर्धारण के लिए उस पर विचार किया जाए।

च. 2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

29. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. वर्तमान याचिका के प्रयोजन के लिए चीन जन.गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था (एनएमई) देश माना जाना चाहिए तथा चीनी उत्पादकों के मामले में सामान्य मूल्य अनुबंध I के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।
- ii. प्राधिकारी संयुक्त राज्य अमेरिका में संबद्ध सामानों की कीमत चीन जन. गण. के संबंध में संबद्ध सामानों के लिए सामान्य मूल्य के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में पहुंच स्तरों पर भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका को संबद्ध सामानों की निर्यात कीमत के आधार पर मानें।
- iii. संयुक्त राज्य अमेरिका में कीमत के आधार पर दावा किए गए सामान्य मूल्य के विकल्प के रूप में, आवेदक भारत में वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का प्रस्ताव करता है, जिसे उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित किया गया है।
- iv. संबद्ध वस्तुओं के आयात की मात्रा और मूल्य डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त सूचना के अनुसार निर्धारित किया जाए, जो याचिका में निर्यात कीमत का आधार भी बनता है।
- v. याचिका में दी गई सूचना से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि संबद्ध सामानों का पाटन जारी रहा और यह पाटन दावा किए गए अनुसार जांच की अवधि में काफी सकारात्मक रहा है। पाटनरोधी शुल्क जारी रहने की स्थिति में जांच अवधि के दौरान यह पाटन इस तथ्य को दर्शाता है कि ऐसे पाटन केवल तभी जारी रहेंगे जब पाटनरोधी शुल्क को इस मोड़ पर समाप्त होने दिया जाएगा।
- vi. जांच अवधि के दौरान पाटन मार्जिन वर्तमान शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में भी संभावित पाटन को सिद्ध करता है।
- vii. सुनवाई के दौरान विरोधी पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदन के एनसीवी के अनुसार कास्टिक सोडा की दर ₹73.43/- प्रति किलोग्राम मानी गई है जो गलत प्रतीत होती है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि सीएनवी के कार्यकरण के लिए वास्तव में विचार की गई दर केवल ₹43.22/- प्रति किलोग्राम है जिसका खुलासा एनसीवी आवेदन के साथ कार्यकारी दस्तावेजों में किया गया था।
- viii. इस मामले में दो निर्यातकों ने जवाब दाखिल किए हैं। तथापि, पक्षकारों ने लागू उत्तर प्रस्तुत करके चीन जन.गण. के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के स्तर की अवधारणा का खंडन नहीं किया है।
- ix. उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों में से एक मेसर्स जियांगसू गुओक्सिन यूनियन एनर्जी कंपनी लिमिटेड पर पहले से ही अलग शुल्क लागू है और इस मामले में पाटन और क्षति की संभावना को देखते हुए किसी कीमत की पेशकश के बजाए उपर्युक्त उत्पादक पर ऐसे शुल्क जारी रखने की आवश्यकता है। वास्तव में, मेसर्स जियांगसू गुओक्सिन यूनियन एनर्जी कंपनी लिमिटेड यूरोपीय संघ पर संबद्ध सामानों के निर्यात में 32.6% का पाटनरोधी शुल्क लगता है, जो दर्शाता है कि उक्त उत्पादक न केवल भारत में पाटन कर रहा है, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी पाटन में लगा हुआ है और ऐसे निर्यातकों पर पाटनरोधी शुल्क की कोई समाप्ति या कमी ऐसे निर्यातक से केवल पाटित किए गए निर्यात में वृद्धि करेगी।

- x. साथ ही, उत्तरदाता निर्यातकों को निम्नलिखित जानकारी विशेष रूप से प्रदान करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए यदि पहले से प्रदान नहीं की गई है ताकि प्राधिकारी संभावना जांच कर सकें:
- क) जांच की अवधि के दौरान और जांच की अवधि के बाद (अधिमानत: अप्रैल-सितंबर 2024) संबद्ध सामानों के उत्पादन की क्षमता।
 - ख) जांच की अवधि और जांच की अवधि के बाद (अधिमानत: अप्रैल-सितंबर 2024) के दौरान संबद्ध सामानों का क्षमता उपयोग।
 - ग) जांच की अवधि और जांच की अवधि के बाद (अधिमानत: अप्रैल-सितंबर 2024) के दौरान संबद्ध सामानों का मालसूची स्तर।
 - घ) जांच की अवधि और जांच की अवधि के बाद (अधिमानत: अप्रैल-सितंबर 2024) के दौरान संबद्ध सामानों के लिए लेनदेन से लेनदेन (टी/टी) के आधार पर तीसरे देशों को निर्यात कीमत।
 - ङ) जांच की अवधि के बाद (अधिमानत: अप्रैल-सितंबर 2024) के दौरान संबद्ध सामानों के लिए लेनदेन से लेनदेन के आधार पर भारत को निर्यात कीमत।
- xi. चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य के आधार के संबंध में, आवेदक ने बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में सामान्य मूल्य के रूप में यूएसए में पहुंच स्तरों पर भारत से यूएसए को संबद्ध सामानों की निर्यात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। वैकल्पिक रूप से, प्रमुख कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत (डीजीसीआईएंडएस आयात मूल्य के अनुसार साइट्रिक एसिड और कास्टिक सोडा की कीमत) पर विचार करके निर्मित आधार पर सामान्य मूल्य भी प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकारी सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए ऐसे दावों पर विचार कर सकते हैं और किसी भी विरोधी पक्षकार द्वारा यह नहीं दर्शाया गया है कि भारत से अमेरिका को निर्यात कीमत पर आधारित सामान्य मूल्य इस मामले में उपयुक्त आधार नहीं है।
- xii. यह एक निर्धारित परिपाटी है कि पाटन और क्षति की संभावना को संबद्ध देश के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, न कि केवल उत्तरदाता निर्यातकों के संदर्भ में। इस प्रकार, भले ही उत्तरदाता निर्यातक अपने निर्यात के संबंध में पाटन और क्षति की संभावना का अभाव दर्शाते हों, फिर भी अकेले संभावना का देशव्यापी निर्धारण प्रासंगिक है। किसी भी मामले में, उत्तरदाता निर्यातकों ने पाटन और क्षति की संभावना का अभाव नहीं दर्शाया है और चीन जन.गण. से भारत को संबद्ध सामानों के निर्यात के संबंध में संभावना का निर्धारण करने के लिए आवश्यक संगत सूचना के संदर्भ में प्रतिक्रिया अपर्याप्त है।
- xiii. उत्तरदाता निर्यातकों ने संभावना विश्लेषण के लिए प्रासंगिक ईक्यूआर (ईक्यूआर के अनुलग्नक III) में निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलुओं पर मांगी गई सूचना को खाली छोड़ दिया है, यह कहते हुए कि यह सूचना उत्तरदाता पक्षकारों पर लागू नहीं होती है:
- क) देश का उत्पादन
 - ख) घरेलू बाजार में अन्य उत्पादकों की बिक्री
 - ग) घरेलू बाजार में कुल बिक्री
 - घ) आपके देश में आयात
 - ङ.) आपके देश में कुल मांग
 - च) अन्य उत्पादकों का भारत को निर्यात
 - छ) भारत को छोड़कर अन्य देशों को अन्य उत्पादकों का निर्यात
- xiv. चूंकि उत्तरदाता निर्यातक आवेदक द्वारा उठाए गए संभावना के दावों का खंडन करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं, अतः अनुरोध है कि वर्तमान मामले में संभावना जांच आवेदन में प्रस्तुत सूचना के आधार पर की जाए।
- xv. साथ ही, उत्तरदाता निर्यातक अर्थात् मेसर्स जियांग्सू गुओक्सिन यूनियन एनर्जी कंपनी लिमिटेड ने दावा किया है कि उन्होंने अपने निर्यात में नकारात्मक मार्जिन का संकेत देते हुए उच्च दर पर संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। तथापि, जांच की अवधि में नकारात्मक मार्जिन पाटनरोधी शुल्क के जारी रहने या न रहने का निर्धारण करने वाला कारक नहीं है और जो संगत है वह संभावना की जांच है। इस प्रकार, जब तक भारत को संबद्ध सामानों के

निर्यात से पाटन और क्षति की संभावना है, तब तक उत्तरदाता उत्पादक अर्थात् मेसर्स जियांगसू गुओक्सिन यूनियन एनर्जी कंपनी लिमिटेड पर पाटनरोधी शुल्क जारी रहने योग्य है। प्राधिकारी द्वारा अतीत में भी ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाया गया है और क्लियर फ्लोट ग्लास से संबंधित निर्णायक समीक्षा इसका ज्वलंत उदाहरण है, जिसमें पाटनरोधी शुल्क जारी रहा, जबकि जांच की अवधि के दौरान निर्यातक के पास सकारात्मक पाटन मार्जिन और नकारात्मक क्षति मार्जिन था।

- xvi. पाटन और क्षति की संभावना अलग अलग उत्तरदाता निर्यातकों के मामले में भी निर्धारक कारक है और कोई भी नकारात्मक पाटन या क्षति मार्जिन उन्हें किसी भी शून्य शुल्क का हकदार नहीं बनाता है, जैसा कि नियमावली और प्राधिकारी की विगत परिपाटियों में भी सिद्ध है।

च. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

सामान्य मूल्य

30. धारा 9क(1)(ग) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-
- (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा
- (ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

चीन जन.गण. के उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था का स्तर

31. डब्ल्यूटीओ में चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है: "जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद VI, टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार एक डब्ल्यूटीओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों की संलिप्तता की कार्यवाहियों में लागू होंगे जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- (क) "जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद- VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों

अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ क (II) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

32. यह नोट किया जाता है कि अनुच्छेद 15(क)(ii) में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि एक्सेसन प्रोटोकॉल के 15(क)(i) के अधीन दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधानों में भारत की नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मापदंड को बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के दावे संबंधी पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के ज़रिए पूरा करना अपेक्षित है।

33. जांच की शुरुआत के स्तर पर, प्राधिकारी ने एसजीए और लाभ जोड़कर भारत में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार सामान्य मूल्य निर्मित कार्यवाही की। जांच शुरू करने पर प्राधिकारी ने चीन जन.गण. में उत्पादकों/निर्यातकों को सलाह दी कि वे जांच की शुरुआत की सूचना का उत्तर दें और अपनी बाजार अर्थव्यवस्था के स्तर के निर्धारण के लिए संगत सूचना दें। प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(3) में निर्धारित मानदंडों के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की अवधारणा का खंडन करने और संगत विस्तृत सूचना देने के लिए सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को पूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजी। प्राधिकारी ने चीन जन.गण. की सरकार से यह भी अनुरोध किया कि वे चीन में उत्पादकों/निर्यातकों को संगत सूचना देने की सलाह दें।

34. किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने चीन जन.गण. के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की अवधारणा का विरोध नहीं किया। इस प्रकार, उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर और किसी भी चीनी निर्यातक कंपनी द्वारा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की अवधारणा का खंडन किए जाने के अभाव में, प्राधिकारी चीन जन.गण. को वर्तमान जांच में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मानना उपयुक्त समझते हैं और चीन जन.गण. के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार कार्यवाही करते हैं।
35. तदनुसार, चीन जन.गण. से सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य निम्नलिखितानुसार निर्धारित किया गया है:

चीन जन.गण. में सभी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य

36. नियमावली का अनुबंध 1 निम्नलिखित रूप में पठित है:

गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य, अथवा भारत या जहां यह संभव नहीं है, वहां सहित तीसरे देश से अन्य देशों से कीमत अथवा अन्य किसी उपयुक्त आधार, जिसमें आवश्यक होने पर विधिवत समायोजित समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त अथवा देय कीमत शामिल है, उपयुक्त लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए, के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाला तीसरा देश संबंधित देश के विकास और प्रगतिगत उत्पाद के मद्देनजर उपयुक्त तरीके में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा चुना जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर उचित ध्यान दिया जाएगा। किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में किसी समान मामले में की गई जांच की समय सीमाओं, जहां लागू हो, के भीतर भी ध्यान दिया जाएगा। जांच से संबंधित पक्षकारों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त चयन से किसी अपर्याप्त विलंब के बिना सूचित किया जाएगा और उनकी टिप्पणियां देने के लिए उपयुक्त समायावधि दी जाएगी।

37. अनुबंध- 1 के पैरा 7 में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए एक अनुक्रम निर्धारित है और यह प्रावधान है कि सामान्य मूल्य किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य, अथवा तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों में कीमत के आधार पर अथवा जहां यह संभव नहीं है, वहां उपयुक्त लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए आवश्यक होने पर विधिवत समायोजित समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त अथवा देय कीमत सहित किसी अन्य उपयुक्त आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
38. जांच शुरू होने के समय, हितबद्ध पक्षकारों को आवेदक द्वारा चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य पर विचार करने के लिए बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत पर विचार करने के प्रस्ताव पर टिप्पणी करने के लिए सूचित किया गया था और यूएसए में कीमत का दावा भारत से यूएसए को संयुक्त राज्य अमेरिका में पहुंच स्तरों पर भारत से यूएसए को संबद्ध सामानों की निर्यात कीमत के आधार पर किया गया है। आवेदक द्वारा दावों की पुष्टि नहीं की गई है और न ही निर्यातकों द्वारा ऐसे प्रस्ताव पर कोई ठोस टिप्पणी की गई है, सिवाय ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकार करने के अनुरोध के। किसी भी हितबद्ध पक्षकार से इस संबंध में कोई और सूचना न मिलने पर, इस आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण पर विचार नहीं किया जाता है।
39. चूंकि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत तथा निर्मित मूल्य, अथवा ऐसे तीसरे देश से अन्य देशों को कीमत आवेदक सहित किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए भारत को रिकॉर्ड में कोई दावा नहीं है, अतः सामान्य मूल्य इस आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता। अतः, प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 में निर्धारित किए गए अनुसार भारत में वास्तव में देय कीमत के रूप में चीन जन.गण. से संबद्ध

सामानों के लिए सामान्य मूल्य निर्मित किया है। इसका परिकलन बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय और लाभ के लिए उपयुक्त अभिवृद्धि कर घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है। इस प्रकार निर्धारित निर्मित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण

i. निर्यात कीमत

क) मेसर्स शांगडोंग एनसाइन इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड

40. मेसर्स शांगडोंग एनसाइन इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड, जो कि विषयगत वस्तुओं का उत्पादक सह निर्यातक है, के निर्यातकों के प्रश्नावली के उत्तर से यह पता चलता है कि जांच अवधि के दौरान कंपनी ने भारत को *** मीट्रिक टन विषयगत वस्तुओं का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने डेस्क सत्यापन और अन्य सहायक दस्तावेजों के माध्यम से डेटा का सत्यापन किया है। उत्पादक/निर्यातक ने समुद्री माल, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय माल, बंदरगाह व्यय और ऋण लागत के कारण समायोजन का दावा किया है, और उन्हें अनुमति दी गई है। तदनुसार, निर्धारित निर्यात मूल्य डंपिंग मार्जिन तालिका में प्रदान किया गया है।

ख) मेसर्स जियांगसू गुओक्सिन यूनियन एनर्जी कंपनी लिमिटेड

41. मेसर्स जियांगसू गुओक्सिन यूनियन एनर्जी कंपनी लिमिटेड, जो विषयगत वस्तुओं का उत्पादक सह निर्यातक है, के निर्यातकों के प्रश्नावली के उत्तर से यह पता चलता है कि जांच अवधि के दौरान कंपनी ने भारत को *** मीट्रिक टन विषयगत वस्तुओं का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने डेस्क सत्यापन और अन्य सहायक दस्तावेजों के माध्यम से डेटा को सत्यापित किया है। उत्पादक/निर्यातक ने समुद्री माल, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय माल, बंदरगाह व्यय के कारण समायोजन का दावा किया है, और उसे अनुमति दी गई है। निर्यातक द्वारा क्रेडिट लागत का दावा नहीं किया गया था और इसकी गणना अन्य सहयोगी निर्यातकों के आधार पर की गई है। तदनुसार, निर्धारित निर्यात मूल्य डंपिंग मार्जिन तालिका में दिया गया है।

चीन जन.गण. में सभी असहयोगी उत्पादकों तथा निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत का निर्धारण

42. चीन जन.गण. के अन्य असहयोगी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित की गई है तथा उसका उल्लेख डंपिंग मार्जिन तालिका में किया गया है।

पाटन मार्जिन

43. विषयगत वस्तुओं के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, विषयगत देश से विषयगत वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

तालिका – 2
पाटन मार्जिन तालिका

क्र. सं.	देश	उत्पादक	सामान्य मूल्य यू.एस. डॉलर/ मी.टन	निवल निर्यात कीमत यू.एस. डॉलर/ मी.टन	पाटन मार्जिन		
					यू.एस. डॉलर/ मी.टन	(%)	(रेंज %)
1	चीन जन.गण.	मेसर्स शेडोंग एनसाइन इंडस्ट्री कं, लिमिटेड	***	***	***	***	10-20
2	चीन जन.गण.	मेसर्स जिआंगसु गुओक्सिन यूनियन एनर्जी कं, लिमिटेड	***	***	***	***	65-75
3	चीन जन.गण.	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	90-100

छ. क्षति आकलन और कारणात्मक संपर्क की जांच

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

44. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. आवेदन इस तथ्य के आधार पर दायर किया गया है कि क्षति जारी है। हालांकि, यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग को वर्तमान में कोई क्षति नहीं हो रही है। परिणामस्वरूप, आवेदन दायर करने का आधार ही खराब है और जांच को समाप्त किया जाना चाहिए।
- ii. कुल आयात में वृद्धि को घरेलू मांग और याचिकाकर्ता के उत्पादन और बिक्री वृद्धि में भारी वृद्धि के आलोक में देखा जाना चाहिए।
- iii. यदि संबद्ध आयात वास्तव में क्षति पैदा कर रहे थे अथवा क्षति का खतरा कर रहे थे, तो इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन और बिक्री कैसे बढ़ी है।
- iv. चीन जन.गण. से आयातों के लिए कीमत कटौती नकारात्मक है। इसका मतलब है कि जिस कीमत पर याचिकाकर्ता बिक्री कर रहा है वह आयात की पहुंच कीमत से कम है। यह सिद्ध करता है कि याचिकाकर्ता को हुई क्षति पाटित आयातों को छोड़कर किसी अन्य कारण से है।
- v. याचिकाकर्ता बिक्री की लागत में वृद्धि होने पर बिक्री मूल्य बढ़ाने/बनाए रखने में सक्षम रहा है। इसके अतिरिक्त, कीमत न्यूनीकरण का कोई मामला नहीं हो सकता है क्योंकि घरेलू उद्योग के बिक्री कीमत में निरंतर वृद्धि हुई है। इसलिए, वर्तमान जांच में कीमत न्यूनीकरण अथवा ह्रास की मौजूदगी का कोई मामला नहीं बनता।
- vi. घरेलू उद्योग को अपनी क्षमता उपयोग, उत्पादन और बिक्री में भारी वृद्धि हुई है। आधार वर्ष की तुलना में क्षमता उपयोग में 150% से अधिक की वृद्धि हुई है। उत्पादन और बिक्री में भी वृद्धि हुई है।
- vii. कर्मचारियों की संख्या के संदर्भ में घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। चूंकि क्षति अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है, इसलिए उत्पादकता में हानि को उत्पादन गतिविधियों में तेजी से विस्तार के कारण आंतरिक अक्षमताओं के लिए स्पष्ट रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
- viii. याचिकाकर्ता की मालसूची क्षति अवधि के दौरान बढ़ी हुई प्रतीत होती है। यद्यपि क्षति जांच अवधि (आईआईपी) के दौरान प्रारंभिक मालसूची में वृद्धि हुई है, तथापि, अंतिम मालसूची उस सीमा तक नहीं बढ़ती रही है।

- ix. उत्पादन और बिक्री के रूप में मालसूची घट रही है जो यह भी स्पष्ट करती है कि यह पाटन या आयात से संबंधित नहीं है।
- x. ऐसा प्रतीत होता है कि नकारात्मक लाभप्रदता अन्य कारकों जैसे आंतरिक अक्षमताओं आदि के कारण है।
- xi. पूरी क्षति जांच अवधि में उद्योग के निर्यात निष्पादन में लगातार सुधार हुआ है। याचिकाकर्ता निर्यात बाजार पर अत्यधिक केंद्रित है और घरेलू मोर्चे पर पर्याप्त रूप से ध्यान केंद्रित करने में सक्षम नहीं है।
- xii. याचिकाकर्ता की लाभप्रदता में कमी के कारण नियोजित पूंजी पर आय नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है। लाभप्रदता में कमी निर्यात निष्पादन में गिरावट और अधिक मूल्यहास के कारण है।
- xiii. ब्याज लागत जांच की अवधि में 100 सूचकांक बिंदुओं से घटकर 23 आधार अंक हो गई है, औसत नियोजित पूंजी 100 से बढ़कर 791 सूचकांक बिंदुओं पर पहुंच गई है। याचिकाकर्ता ने कठोर नियामक गुणवत्ता जांच के कारण अतिरिक्त अनुपालन लागतों को नियोजित औसत पूंजी में इस वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया। हालांकि, दावों को प्राधिकारी द्वारा मान्य किया जाना चाहिए, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि केवल घरेलू बाजार से संबंधित अनुपालन लागतों पर विचार किया गया है।
- xiv. प्राधिकारी को निर्यात बिक्री बाजार को ध्यान में रखते हुए खर्च की गई किसी भी राशि को अस्वीकार करना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक ने सभी लागतों को शामिल करके नियोजित औसत पूंजी में वृद्धि की है, ताकि अंततः कृत्रिम रूप से एनआईपी का निर्धारण बढ़ाया जा सके।
- xv. याचिका से ही यह सत्यापित किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता का पहुंच मूल्य और बिक्री कीमत कच्ची सामग्री की लागत के साथ-साथ बढ़ रहे हैं। बिक्री कीमत में गिरावट आयात का कारण नहीं है।
- xvi. घरेलू उद्योग को क्षति का निर्धारण करने के लिए, घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति की जांच की जानी चाहिए। थाईलैंड में डब्ल्यूटीओ पैनल का निर्णय - एच-बीम्स (डब्ल्यूटी/डीएस/122/आर) प्रासंगिक है। चीन जन.गण. से डाइसियांडियामाइड के आयात के संबंध में 11 फरवरी, 2014 के काउंसिल इम्प्लीमेंटिंग रेगुलेशन (ईयू) संख्या 135/2014 पर भी भरोसा किया गया था, ताकि यह सुझाव दिया जा सके कि वर्तमान मामले में भी, याचिकाकर्ता के प्रदर्शन में क्षति अवधि के दौरान सुधार हुआ है। क्षति, यदि कोई हो, आयात के अलावा अन्य कारकों के कारण है। उपरोक्त निर्णय को वर्तमान मामले में लागू करने पर यह स्पष्ट है कि क्षति की कोई संभावना नहीं है।
- xvii. घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति अच्छी है। सभी आर्थिक मापदंड, परिचालनात्मक और वित्तीय, सुधर रहे हैं। अतः, पाटन और क्षति निरंतर नहीं है जिससे कि यह कहा जाए कि घरेलू उद्योग को आयातों के कारण क्षति हो रही है और उन पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता है।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

45. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. आवेदन पत्र में वर्तमान पाटन और क्षति को दर्शाया गया है, जिसे मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन और क्षति की संभावना के हमारे दावों को पुष्ट करने वाले एक प्रमुख कारक के रूप में माना जाना चाहिए और वर्तमान पाटन और क्षति के अलावा अन्य कारक भी हैं, जो मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में वर्तमान मामले में पाटन और क्षति की बहुत मजबूत संभावना को दर्शाते हैं।
- ii. घरेलू उद्योग को हानियां हुई और उसे जो हानियां हुई, वह लागत कटौती स्तरों पर चीन जन.गण. से आयातों की पहुंच कीमत से अनुचित प्रतिस्पर्धा के कारण सीधी गिरावट है और वर्तमान पाटन के अभाव में स्थिति और भी गंभीर हुई है।

- iii. आधार वर्ष और जांच की अवधि के बीच चीन जन.गण. से आयात में पूर्ण रूप से वृद्धि हुई है। आधार वर्ष में आयात जो 1,137 मीट्रिक टन था, वह पूर्ण रूप से वृद्धि दर्शाता हुआ 2,025 मीट्रिक टन हो गया।
- iv. उत्पादन के संबंध में पाटित किए गए आयातों में जांच अवधि और आधार वर्ष के बीच गिरावट आई है, जो इस मापदंड के संबंध में लागू पाटनरोधी शुल्क के सकारात्मक प्रभाव के रूप में क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि के अनुरूप है। हालांकि, जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास काफी अप्रयुक्त क्षमता बची हुई थी।
- v. मांग के संबंध में आधार वर्ष और जांच अवधि के बीच पाटित आयातों में वृद्धि हुई। यह दर्शाता है कि भारतीय बाजार में आयात जारी हैं और भारत में उत्पाद की मांग में वृद्धि के साथ वृद्धि जारी है। पाटित आयातों के लिए ऐसी प्राथमिकता वर्तमान शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में और बढ़ेगी।
- vi. भारतीय मांग में पाटित आयातों का हिस्सा तब बढ़ा जब भारतीय उत्पादकों के पास संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता थी। भारत के उत्पाद पर आत्मनिर्भर होने पर भी पाटित सामान का महत्वपूर्ण हिस्सा इस संभावना को दर्शाता है कि ऐसा हिस्सा काफी बढ़ जाएगा जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होगी यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त हो जाएं।
- vii. चीन जन. से संबद्ध सामानों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क 20 मई, 2015 को लागू हुआ। इस प्रकार के शुल्क के बाद से लेकर वर्तमान जांच अवधि तक आयात संबंधी जानकारी से पता चलता है कि पाटित आयात भारतीय बाजार में बहुत ही लगातार प्रकृति के रहे हैं, तब भी जब पाटनरोधी शुल्क उपाय लागू थे। आयात इस प्रकार रहा है:

तालिका - 3

वर्ष	सोडियम साइट्रेट चीन जन.गण. से आयात (एमटी में मूल्य)
2015-16	843
2016-17	1,168
2017-18	975
2018-19	736
2019-20	960
2020-21	1,137
2021-22	1,418
2022-23	2,123
2023-24	2,025
अप्रैल-सित. 2024 (वार्षिकीकृत)	966

- viii. चीन जन.गण. से पाटित आयातों का बाजार हिस्सा आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि तक बढ़ा है और पूरी क्षति अवधि के दौरान पूर्ण दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण स्तर पर रहा है।

- ix. पाटित आयातों का बाजार हिस्सा आधार वर्ष के बाद और जांच अवधि में 10% से अधिक रहा है, जिसे बाजार समीकरणों को विकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में नोट किया जाना चाहिए।
- x. अन्य देशों का बाजार हिस्सा आधार वर्ष और जांच अवधि के बीच घटा है और बाजार हिस्सेदारी के मामले में बहुत कम स्तर पर रहा है। ऐसे अन्य आयात भी उच्च कीमतों पर थे और स्पष्ट रूप से, चीन जन.गण. से आयातों को इसकी पाटित कीमतों के लिए प्राथमिकता दी जाती है।
- xi. यद्यपि जांच अवधि तक पाटित आयातों की तुलना में भारतीय मांग में बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई, घरेलू उद्योग की मांग में बाजार हिस्सेदारी उसी अवधि में घट गई। बाजार हिस्सेदारी में गिरावट निरपेक्ष रूप से लगभग 1.70% थी जो लगभग 7% की गिरावट है और इसे बाजार हिस्सेदारी के पर्याप्त नुकसान के रूप में नोट किया जाना चाहिए।
- xii. यद्यपि जांच अवधि और आधार वर्ष के बीच अन्य भारतीय उत्पादकों की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई, लेकिन मांग में उल्लेखनीय वृद्धि का लाभ अन्य भारतीय उत्पादकों को पूरी तरह से नहीं मिला। जबकि आधार वर्ष और जांच अवधि के बीच मांग में वृद्धि लगभग 66% थी, अन्य उत्पादकों की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि केवल 6% रही है।
- xiii. याचिका से पता चलता है कि घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध क्षमता पिछले वर्षों में अपरिवर्तित रही है। हालांकि, अकेले आवेदक के पास उपलब्ध क्षमता भारतीय मांग के 85-95% को पूरा करने के लिए पर्याप्त है और देश में 19,000-20,000 मीट्रिक टन की मांग के मुकाबले 30,000-35,000 मीट्रिक टन की क्षमता है।
- xiv. जांच अवधि तक घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई, भले ही जांच अवधि के दौरान क्षमता 30-40% की सीमा में महत्वपूर्ण स्तर पर अप्रयुक्त रही।
- xv. जांच अवधि और तत्काल पिछले वर्ष के बीच घरेलू बिक्री में वृद्धि 2% पर बहुत कम रही है जबकि इसी अवधि के दौरान भारतीय मांग में 17% की वृद्धि हुई। बिक्री में इतनी कम वृद्धि इसी अवधि में पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 2% की गिरावट का परिणाम है।
- xvi. घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई, लेकिन निर्यात में सकारात्मक वृद्धि के परिणामस्वरूप और उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि भी कम होती यदि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निर्यात में वृद्धि नहीं हुई होती।
- xvii. घरेलू उद्योग के मालसूची स्तर में पर्याप्त वृद्धि हुई है, हालांकि क्षमता उपयोग और उत्पादन में वृद्धि हुई है। यह इस तथ्य को दर्शाता है कि उत्पादन में वृद्धि पूरी तरह से बिक्री में परिवर्तित नहीं हो सकी और पाटित आयातों के अभाव में निर्मित मालसूची से बचा जा सकता था।
- xviii. मात्रात्मक मापदंडों की स्थिति यह दर्शाती है कि पाटनरोधी शुल्क ने मात्रात्मक निष्पादन में कुछ गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह भी स्पष्ट है कि वर्तमान शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में पाटित आयातों में किसी भी वृद्धि के लिए मात्रा निष्पादन अत्यधिक सुभेद्य है।
- xix. उत्पादन में वृद्धि के अनुरूप रोजगार के स्तर में जांच की अवधि तक थोड़ी वृद्धि हुई। यदि क्षमता का कम उपयोग न होता तो घरेलू उद्योग अधिक लोगों को रोजगार दे सकता था।
- xx. घरेलू उद्योग देश के कानूनों के अनुसार समय पर मजदूरी और वेतन बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और पिछले कुछ वर्षों में कुल मजदूरी में कुछ वृद्धि हुई है। हालांकि, उत्पादन की प्रति इकाई मजदूरी में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई और यह नहीं कहा जा सकता कि दावा की गई क्षति किसी मजदूरी वृद्धि के कारण है।

- xxi. प्रति कर्मचारी उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और संख्याएं मजबूत रही हैं, जो घरेलू उद्योग के कार्यबल के बहुत कुशल उपयोग को दर्शाती हैं। इसलिए, उत्पादकता में कोई भी गिरावट घरेलू उद्योग के लिए क्षति का कारण नहीं है।
- xxii. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता जो क्षति अवधि के शुरुआती दो वर्षों में पीबीआईटी और पीबीडीआईटी के संदर्भ में सकारात्मक थी, एक बार फिर जांच की अवधि के दौरान काफी नकारात्मक हो गई। ऐसे मापदंडों पर नुकसान जांच की अवधि के तत्काल पिछले वर्ष के दौरान भी स्पष्ट है। यहां तक कि वर्ष 2021-22 के दौरान पीबीटी भी सकारात्मक थी, जो जांच की अवधि और तत्काल पिछले वर्ष के दौरान भी काफी नकारात्मक हो गई।
- xxiii. घरेलू उद्योग जांच की अवधि तक ब्याज लागत आदि को काफी कम करके अपनी दक्षता में सुधार करने में सक्षम रहा है, हालांकि, जांच की अवधि के दौरान वसूल की गई कीमत अलाभकारी रही है और घरेलू उद्योग अपनी लागत भी वसूल नहीं कर सका क्योंकि पाटित आयातों ने ऐसे प्रयासों को कमजोर कर दिया। इस प्रकार, घरेलू उद्योग जांच अवधि के दौरान एक बार फिर घाटे में रहा है और यह घाटा घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से भी कम दर पर पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण हुआ है।
- xxiv. क्षति अवधि के प्रारंभिक दो वर्षों के दौरान नकद लाभ सकारात्मक थे और यहां तक कि जांच अवधि के दौरान ऐसे नकद लाभ काफी नकारात्मक हो गए। पाटित आयातों से अनुचित मूल्य प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग लाभदायक स्तरों पर प्रचालन नहीं कर सका, जो नकद लाभ की स्थिति में भी परिलक्षित होता है।
- xxv. क्षति अवधि के प्रारंभिक दो वर्षों के दौरान निवेश पर प्रतिफल (आरओआई) सकारात्मक रहा है, जो जांच अवधि के दौरान और तत्काल पिछले वर्ष के दौरान काफी नकारात्मक हो गया। निवेश पर नकारात्मक प्रतिफल की स्थिति घरेलू उद्योग के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है, वह भी तब जब उत्पाद ने मांग में कुछ मजबूत वृद्धि दिखाई है और ऐसी स्थिति में नकारात्मक आरओआई घरेलू उद्योग के अस्तित्व के उद्देश्य पर ही प्रश्नचिह्न लगाता है।
- xxvi. यद्यपि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा और मालसूची स्तर नकारात्मक रूप से बढ़ा है, हालांकि उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री जैसे कुछ अन्य मात्रा मापदंडों ने सकारात्मक प्रवृत्ति दिखाई है। हालांकि, बिक्री मूल्य, लाभ, नकद लाभ और आरओआई जैसे सभी मूल्य मापदंडों ने महत्वपूर्ण नकारात्मक वृद्धि दिखाई है। यदि कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं होता तो स्थिति और भी गंभीर होती और स्थिति यह भी दर्शाती है कि घरेलू उद्योग की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना बहुत आवश्यक है।
- xxvii. घरेलू उद्योग अभी भी अपने द्वारा पहले से किए गए निवेशों पर उचित स्तर का रिटर्न हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा है। पाटित आयात पहले से किए गए ऐसे निवेशों पर किसी भी विवेकपूर्ण स्तर की आय को प्राप्त करने में बाधा बन रहे हैं और क्षमता आदि का महत्वपूर्ण रूप से विस्तार करने के लिए कोई और पूंजी जुटाना भारतीय बाजार में समान अवसर की निरंतरता पर निर्भर करेगा।
- xxviii. घरेलू उद्योग को 2022-23 और 2023-24 के दौरान मौजूदा सुविधा में और अधिक और पर्याप्त निवेश करना होगा, विशेष रूप से सबसे आधुनिक बुनियादी ढांचे और संयंत्र और मशीनरी में नए परिवर्तन के साथ सुविधा को नया रूप देने के लिए ताकि 28 दिसंबर, 2023 की अनुसूची एम अधिसूचना के अनुरूप सुविधा में सर्वोत्तम विनिर्माण प्रथाओं को अपनाया जा सके।
- xxix. चीन जन.गण. से आयात की पहुंच कीमत में जांच अवधि के दौरान तत्काल पिछले वर्ष की तुलना में तेजी से गिरावट आई, हालांकि जांच अवधि के दौरान कीमत कटौती नकारात्मक रही है। वास्तविक मूल्य प्रभाव को इस तथ्य में देखा जाना चाहिए कि चीन जन.गण. से आयात की पहुंच कीमत ने मूल्य वृद्धि को रोका जो अन्यथा काफी हद तक होती और आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से कम रही है।

- xxx. जांच अवधि के दौरान नकारात्मक कटौती इस कारण से महत्वहीन है कि आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से कम रही है और घरेलू उद्योग को अपनी लागत से कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- xxxi. यह एक निर्धारित सिद्धांत है कि नकारात्मक कीमत कटौती का मतलब क्षति की अनुपस्थिति नहीं है और न ही कीमत कटौती कीमत की क्षति को मापने का एकमात्र मापदंड है। बहुत से मामलों में, प्राधिकारी ने तब भी क्षति पाई जब कीमत कटौती नकारात्मक रही (टीडीआई, पीटीए आदि जैसे मामले इसके उदाहरण हैं)।
- xxxii. आवेदन पत्र में दिए गए अनुसार पाटित आयातों से कम कीमत पर बिक्री काफी है। आवेदक की उत्पादन लागत और उचित मूल्य (एनआईपी) से कम कीमत पर पाटित आयातों को घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति दिखाने वाले एक प्रमुख कारक के रूप में नोट किया जाना चाहिए।
- xxxiii. यद्यपि घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, बिक्री कीमत तथा आयातों की पहुंच कीमत में तत्काल पिछले वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान गिरावट आई, फिर भी आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत की तुलना में काफी कम रही। इससे पता चलता है कि पाटित आयातों की पहुंच कीमत के कारण घरेलू उद्योग की कीमत का ह्रास हुआ।
- xxxiv. निर्यातकों ने जांच अवधि के दौरान प्रमुख कच्चे माल अर्थात् साइट्रिक एसिड की कीमत में आई गिरावट की तुलना में बहुत अधिक दर पर संबद्ध सामानों की कीमत में कमी की। कीमत में 29% की अस्पष्टीकृत अतिरिक्त गिरावट उन तथ्यों में से एक है जो चीन जन.गण. से संबद्ध सामानों के उत्पादकों द्वारा अपनाई जा रही निर्यात कीमत निर्धारण नीति में पाटन के तत्व को प्रदर्शित करता है।
- xxxv. उपरोक्त चर्चाओं से यह तथ्य पता चलता है कि घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटे तथा मात्रा मापदंडों के संदर्भ में औसत से कम प्रदर्शन के रूप में क्षति का सामना करना पड़ रहा है तथा ऐसे प्रमुख क्षति मापदंडों के संदर्भ में वृद्धि भी नकारात्मक रही है। वर्तमान पाटनरोधी शुल्क के अभाव में उपरोक्त मापदंडों पर क्षति अधिक होती।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

46. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में, “... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए” घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करने में, यह जांच करना आवश्यक माना जाता है कि क्या भारत वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों का काफी मात्रा में ह्रास करना अथवा कीमत वृद्धि रोकना है जो अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन आदि की मात्रा और मार्जिन पर नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।
47. इस नियमावली के नियम 23 में प्रावधान है कि नियम 6,7,8,9,10,11,16,18,19 और 20 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित समीक्षा के मामले में लागू होंगे। यदि घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन यह दर्शाता हो कि इसे क्षति की वर्तमान अवधि के दौरान क्षति नहीं हुई है तब प्राधिकारी इस तथ्य का निर्धारण करेंगे कि क्या वर्तमान शुल्क को समाप्त किए जाने के कारण घरेलू उद्योग को क्षति संभवतः बार बार होगी।
48. जांच प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में किए गए अनुरोधों की, जिन्हें प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक माना गया है, जांच की गई है और संगत मापदंडों के तहत उन्हें नीचे हल किया गया है।

49. इस तर्क के संबंध में कि अनुपालन लागत के कारण नियोजित औसत पूंजी में वृद्धि का दावा किया जाना चाहिए और एनआईपी के लिए केवल घरेलू बाजार से संबंधित अनुपालन लागतों पर विचार किए जाने की आवश्यकता है, प्राधिकारी ने निर्यातकों के तर्कों के मद्देनजर आवेदक के दावों को विस्तृत सत्यापन के अधीन किया है। सत्यापन के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा सहायक दस्तावेजों के साथ यह स्पष्ट किया गया है कि मौजूदा सुविधा में निवेश किया गया था और 2022-23 और 2023-24 के दौरान पूंजीकृत किया गया था ताकि उत्पादन सुविधा को वर्ष 2018 में प्रस्तावित औषधि नियम, 1945 में नई अनुसूची एम के अनुरूप बनाया जा सके। कंपनी ने विशेषज्ञ की सिफारिश के आधार पर अपना निवेश निर्णय लिया और नई अनुसूची एम, जिसमें फार्मास्युटिकल उत्पादों के लिए अच्छे विनिर्माण अभ्यास और परिसर, संयंत्र और उपकरणों की आवश्यकताएं शामिल हैं, को भारत सरकार के अधीन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 28 दिसंबर, 2023 को अधिसूचना संख्या जीएसआर 922 (ई) द्वारा अधिसूचित और कार्यान्वित किया गया है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग नोडल मंत्रालय द्वारा नई अनुसूची एम को लागू किए जाने तक नियोजित कैपेक्स की मदद से अपने संयंत्र को अपग्रेड कर सकता है। यह नोट किया जाता है कि कैपेक्स समग्र रूप से उत्पादन के लिए किया गया है न कि केवल निर्यात के लिए जैसा कि तर्क दिया गया है। फिर भी, मुख्य रूप से निर्यात के लिए लागू कुछ निवेशों की पहचान की गई है और जहां भी लागू हो, नियोजित पूंजी की गणना करते समय उन्हें बाहर रखा गया है।
50. विभिन्न क्षति मापदंडों से संबंधित क्षति के तर्क के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी मापदंड गिरावट दर्शाएं। कुछ मापदंड गिरावट दर्शा सकते हैं, जबकि कुछ अन्य नहीं दर्शा सकते हैं। प्राधिकारी घरेलू उद्योग के वित्तीय मापदंडों का आकलन करने के लिए सभी क्षति मापदंडों पर विचार करते हैं। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों पर विचार करते हुए क्षति मापदंडों की निष्पक्ष रूप से जांच की है।
- i. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव
- क. मांग / स्पष्ट खपत का आकलन
51. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में भारत में पीयूसी की मांग या स्पष्ट खपत को परिभाषित किया है। इस प्रकार, आकलित मांग नीचे तालिका में दी गई है।

तालिका - 4

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
चीन जन. गण. से आयात (संबद्ध देश)	एमटी	1,137	1,418	2,123	2,025
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	125	187	178
अन्य देशों से आयात	एमटी	585	309	252	384
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	53	43	66
देश में कुल आयात	एमटी	1,722	1,727	2,375	2,409
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	138	140
याचिकाकर्ता की घरेलू बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	73	152	154
समर्थकों की घरेलू बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	146	127	150
अन्य उत्पादकों की घरेलू बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	172	201

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
मांग	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	149	166

52. यह देखा गया है कि उत्पाद की मांग में आधार वर्ष और पीओआई के बीच 66 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है।

ख. संबद्ध देश से आयात मात्राएं

53. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में, समग्र रूप से या भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष, भारी वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के अनुसार आयात पर भरोसा किया है। क्षति जांच अवधि के दौरान भारत में कुल आयात में संबद्ध वस्तुओं की आयात मात्रा और उसका हिस्सा इस प्रकार है:

तालिका – 5

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
देश में कुल आयात	एमटी	1,722	1,727	2,375	2,409
चीन जन. गण. से आयात (संबद्ध देश)	एमटी	1,137	1,418	2,123	2,025
अन्य देशों से आयात	एमटी	585	309	252	384
कुल आयातों में संबद्ध देश का हिस्सा	%	66	82	89	84
कुल आयातों में अन्य देशों का हिस्सा	%	34	18	11	16
कुल	%	100	100	100	100

54. यह देखा गया है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का पाटित आयात आधार वर्ष में 1,137 एमटी से बढ़कर जांच अवधि में 2,025 एमटी हो गया है, जो आयात में समग्र वृद्धि दर्शाता है। प्रतिशत के संदर्भ में, भारत में समग्र आयात में संबद्ध देश से पाटित आयातों का हिस्सा जो आधार वर्ष में 66% था, जांच अवधि में बढ़कर 84% हो गया, जबकि अन्य देशों से आयातों का हिस्सा आधार वर्ष में 34% से घटकर जांच अवधि तक 16% रह गया। उपरोक्त जानकारी यह भी दर्शाती है कि संबद्ध देश भारत में सोडियम साइट्रेट के आयात का मुख्य स्रोत बना हुआ है।

ग. सापेक्ष रूप में संबद्ध देश से आयात

तालिका – 6

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
चीन जन. गण. से आयात (संबद्ध देश)	एमटी	1,137	1,418	2,123	2,025
मांग	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	149	166
घरेलू उद्योग का उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	144	191	265
भारतीय खपत से संबंधित संबद्ध देश से आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	125	107

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
घरेलू उद्योग के उत्पादन से संबंधित संबद्ध देश से आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	71	98	67

55. यह नोट किया गया है कि खपत के सापेक्ष पाटित आयातों का हिस्सा जांच अवधि और आधार वर्ष के बीच 7% बढ़ा है। तथापि, भारत में उत्पादन के संबंध में पाटित आयातों में जांच अवधि और आधार वर्ष के बीच 33% की गिरावट आई है, जो इसी अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि के अनुरूप है।

ii. घरेलू उद्योग पर आयातों का कीमत प्रभाव

56. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत कटौती की गई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में बढ़ गई होती। संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) और क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों की पहुंच कीमत के साथ की गई है।

क) कीमत कटौती

57. कीमत कटौती विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देश से आयात के पहुंच मूल्य के साथ की गई है। घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत की गणना करते समय सभी करों, रिबेट, छूटों और कमीशनों को घटा दिया गया है तथा पाटित आयातों के पहुंच मूल्य के साथ तुलना के लिए कारखानाद्वारा स्तर पर बिक्री प्राप्ति का निर्धारण किया गया है। तदनुसार, संबद्ध देश से पाटित आयातों के कटौती प्रभाव निम्नानुसार निर्धारित किए गए हैं:

तालिका - 7

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
निवल बिक्री प्राप्ति	रु/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	300	188	118
लैंडेड मूल्य (एलवी)	रु/एमटी	57,319	96,155	1,29,945	91,014
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	168	227	159
मूल्य में कटौती	रु/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	949	-2	-82
मूल्य में कटौती	एलवी का %	***	***	***	***
मूल्य में कटौती	रेंज	15-25	110-120	ऋणात्मक	ऋणात्मक

58. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया गया है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से अधिक कीमत पर प्रवेश कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप जांच अवधि के दौरान ऋणात्मक कीमत कटौती हुई है। घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया है कि ऋणात्मक कीमत कटौती का अर्थ यह नहीं है कि क्षति नहीं हुई है, जैसा कि कई जांचों में कहा गया है और घरेलू उद्योग की वास्तविक चिंता यह है कि

आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से भी कम है, जिसके कारण कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हो पाई है, जो पाटित आयातों की अनुपस्थिति में हो गई होती।

59. घरेलू उद्योग द्वारा यह भी कहा गया है कि भले ही आयात की औसत कीमत पर कीमत कटौती नकारात्मक रही हो, लेकिन पेय पदार्थ उत्पादकों जैसे पेप्सिको इंडिया/कोको कोला इंडिया द्वारा किए गए आयातों को देखते हुए कीमत कटौती सकारात्मक होगी, जिन्होंने उच्च कीमतों पर आयात करने का दावा किया है। इस संबंध में, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम के आंकड़ों से प्राप्त जानकारी के आधार पर पेप्सिको इंडिया/कोको कोला इंडिया और अन्य आयातकों के लिए अलग से कीमत कटौती की भी जांच की है और यह नोट किया गया है कि पेप्सिको इंडिया और कोका कोला इंडिया के अलावा अन्य पक्षों द्वारा किए गए आयातों के मामले में कीमत कटौती सकारात्मक रही है।

तालिका – 8

विवरण	एमटी	पहुंच मूल्य	एनएसआर	कटौती	कटौती(%)	रेंज
पेप्सिको इंडिया एवं कोका कोला इंडिया	***	***	***	***	***	ऋणात्मक
अन्य	***	***	***	***	***	15-25
कुल	***	***	***	***	***	ऋणात्मक

60. उपर्युक्त जानकारी से पता चलता है कि पेप्सिको इंडिया और कोका कोला इंडिया के अलावा अन्य पक्षकारों द्वारा किए गए आयातों के मामले में कीमत कटौती सकारात्मक रही है।

ख) कीमत ह्रास / न्यूनीकरण

61. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयातों का प्रभाव कीमतों में भारी कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में काफी बढ़ गई होती। प्राधिकारी ने पाटित आयातों की पहुंच कीमत के आलोक में क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लागतों और कीमतों में परिवर्तनों की जांच निम्नानुसार की है:

तालिका – 9

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
बिक्रियों की लागत	रु/एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	191	233	157
घरेलू बिक्री कीमत	रु/एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	300	188	118
लैंडेड मूल्य (संबद्ध देश)	रु/एमटी	57,319	96,155	1,29,945	91,014
	सूचीबद्ध	100	168	227	159

62. उपर्युक्त तालिका के अनुसार सूचना यह दर्शाती है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में 57% की वृद्धि हुई, जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में उसी अवधि में केवल 18% की वृद्धि हुई, जो कीमत न्यूनीकरण को दर्शाता है।

iii. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

63. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-11 में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों की घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी नियमावली में यह भी उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक मापदंडों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा।
64. क्षति और कारणात्मक संबंध पर अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन करते हुए, प्राधिकारी ने इस जांच में अब तक सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए क्षति मापदंडों की भी वस्तुनिष्ठ रूप से जांच की है, ताकि सभी अनुरोधों का उनके तथ्यों के आधार पर समाधान किया जा सके।

क) उत्पादन, क्षमता, बिक्री और क्षमता उपयोग

65. उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार रहा:

तालिका – 10

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
संस्थापित क्षमता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	176	191	265
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	176	191	265
घरेलू बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	73	152	154

66. यह नोट किया गया है कि यद्यपि संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध क्षमता क्षति अवधि के दौरान समान रही, फिर भी आधार वर्ष और जांच अवधि के बीच घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री में वृद्धि हुई।

ख) मालसूची

67. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका – 11

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
प्रारंभिक मालसूची	एमटी	***	***	***	***
अंतिम मालसूची	एमटी	***	***	***	***
औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	एमटी	100	571	1,335	1,719

68. यह नोट किया गया है कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हुई है। जांच अवधि के अंत में मालसूची, जांच अवधि के दौरान मालसूची में वृद्धि को दर्शाते हुए, इस अवधि के लिए प्रारंभिक मालसूची स्तर से अधिक रही है। जांच अवधि के दौरान मालसूची का स्तर घरेलू बिक्री की मात्रा की तुलना में काफी अधिक रहा है।

ग. मांग में बाजार हिस्सा

69. आयातों और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से की निम्नानुसार जांच की गई है:

तालिका – 12

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
चीन जन. गण. से आयात (संबद्ध देश)	एमटी	1,137	1,418	2,123	2,025
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	125	187	178
अन्य देशों से आयात	एमटी	585	309	252	384
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	53	43	66
देश में कुल आयात	एमटी	1,722	1,727	2,375	2,409
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	138	140
याचिकाकर्ता की घरेलू बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	73	152	154
समर्थकों की घरेलू बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	146	127	150
अन्य उत्पादकों की घरेलू बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	172	201
मांग	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	110	149	166
निम्नलिखित में भारतीय मांग का हिस्सा:					

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
चीन जन. गण. से आयात (संबद्ध देश)	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	125	107
अन्य देशों से कुल आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	48	29	40
देश में कुल आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	93	84
याचिकाकर्ता की घरेलू बिक्रियां	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	66	102	92
समर्थकों की घरेलू बिक्रियां	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	132	85	90
अन्य उत्पादकों की घरेलू बिक्रियां	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	116	121
भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियां	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	101	103

70. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया गया है कि यद्यपि भारत में संबद्ध वस्तु की मांग में पाटित आयातों के बाजार हिस्से में आधार वर्ष और पीओआई के बीच 7% की वृद्धि हुई। तथापि, भारतीय मांग में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में उसी अवधि में 8% तक की गिरावट आई। तथापि, भारतीय मांग में अन्य स्रोतों से आयातों का बाजार हिस्सा आधार वर्ष और जांच अवधि के बीच 60% घटा। यह स्पष्ट है कि क्षति अवधि और जांच अवधि में पाटित आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि जारी रही।

घ) लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ

71. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका – 13

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
लाभ/हानि(पीबीटी)	रु/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	3,619	-1,800	-1,513
लाभ/(हानि) व्याज और कर पूर्व (पीबीआईटी)	रु/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	4,828	-2,336	-1,989

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
नकद लाभ	रु/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	5,139	-2,139	-1,957
औसत नियोजित पूंजी	रु लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	297	492	791
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	1,194	-721	-387

72. उपरोक्त तालिका से यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग के प्रमुख लाभप्रदता मापदंडों ने वर्ष 2020-21 और 2021-22 के बीच सकारात्मक वृद्धि दर्शाई और उसके बाद 2022-23 और जांच अवधि के दौरान लाभप्रदता में काफी गिरावट आई। परिणामस्वरूप, प्रति इकाई कर पूर्व लाभ, ब्याज और कर पूर्व लाभ और नियोजित पूंजी पर आय जैसे सभी प्रमुख मापदंडों के संदर्भ में लाभप्रदता जांच अवधि के दौरान नकारात्मक रही है। घरेलू उद्योग द्वारा यह कहा गया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से कम कीमतों पर किए गए पाटित आयात ऐसे घाटे का कारण रहे हैं और वर्तमान पाटनरोधी शुल्क की अनुपस्थिति में घाटे में वृद्धि होगी।

ड.) रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

73. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी नीचे तालिका में दिए गए हैं:

तालिका – 14

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
रोजगार	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	170	198	273
मजदूरी	रु लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	131	166	267
कर्मचारी प्रति उत्पादकता	एमटी/व्यक्ति	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	96	97
मजदूरी	रु/एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	75	87	101

74. यह नोट किया गया है कि रोजगार के स्तर में सकारात्मक वृद्धि हुई है। साथ ही, उत्पादन की प्रति इकाई मजदूरी में भी जांच अवधि तक केवल मामूली वृद्धि हुई है।

च) पाटन मार्जिन की मात्रा

75. पाटन की मात्रा इस बात का एक संकेतक है कि भारत में आयात कितनी मात्रा में पाटित किया जा रहा है। जांच से पता चला है कि जांच अवधि में पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक है।

छ) वृद्धि

76. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि मालसूची के स्तर को छोड़कर प्रमुख मात्रा मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि जांच अवधि के दौरान सकारात्मक रही है, तथापि लाभप्रदता मापदंडों में नकारात्मक वृद्धि देखी गई है, जैसा कि नीचे तालिका से देखा जा सकता है:

तालिका – 15

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	पीओआई
उत्पादन	%	75.90	8.45	38.90
घरेलू बिक्री मात्रा	%	-26.63	106.86	1.16
क्षमता उपयोग	%	75.90	8.45	38.90
मालसूची	%	471.03	133.76	28.79
रोजगार	%	69.91	16.67	37.50
बिक्री कीमत प्रति कि.ग्रा.	%	199.89	-37.29	-37.23
बिक्रियों की लागत प्रति कि.ग्रा.	%	90.56	-22.29	-32.65
नियोजित पूंजी पर आय	%	1,293.54	-160.44	-46.42
लाभ प्रति यूनिट	%	3,713.37	-149.74	-15.94
पीवीआईटी प्रति यूनिट	%	4,930.17	-148.38	-14.84

77. घरेलू उद्योग ने दावा किया कि लाभप्रदता मापदंडों में नकारात्मक वृद्धि घरेलू उद्योग की लागत से कम कीमतों पर पाटित आयातों का परिणाम है।

ज) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

78. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान मौजूदा संयंत्र के उन्नयन के लिए अतिरिक्त पूंजी निवेश किया है, ताकि संबद्ध वस्तु का उत्पादन किया जा सके, जो 28 दिसंबर, 2023 से यथा संशोधित और यथा लागू औषधि नियम, 1945 के अंतर्गत नई अनुसूची-एम अपेक्षाओं के समकक्ष हो सके। यह भी नोट किया गया है कि संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए पहले से किए गए ऐसे निवेशों से आरओसीई जांच अवधि सहित पूरी क्षति अवधि में एक वर्ष को छोड़कर नकारात्मक रहा। घाटे के जारी रहने से आगे पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

झ) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

79. संबद्ध देश से आयात कीमतों, लागत संरचना में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, पाटित आयातों के अलावा अन्य कारक जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, आदि की जांच से पता चलता है कि संबद्ध देश से आयातित सामग्री का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है, जिससे कीमत ह्रासकारी प्रभाव पड़ रहा है। यह भी नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में काफी वृद्धि देखी गई थी और इसलिए यह घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला कारक नहीं हो सकता था। इस प्रकार,

यह नोट किया जा सकता है कि घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का पाटित आयात है।

ज) गैर-आरोपण विश्लेषण

80. पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी के लिए अन्य बातों के साथ-साथ पाटित आयातों से इतर किसी ज्ञात कारक की जांच करना अपेक्षित है जिससे उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति हो रही हो ताकि इन अन्य कारकों की वजह से किसी क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार न ठहराया जा सके। इस संबंध में, संगत कारकों में अन्य के साथ-साथ पाटित कीमत पर नहीं बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमत, मांग में संकुचन या खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास, घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन और उत्पादकता शामिल हैं।

81. चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा है और मूल जांच में कारणात्मक संबंध की जांच पहले ही की जा चुकी है, इसलिए प्राधिकारी ने जांच की कि क्या अन्य ज्ञात सूचीबद्ध कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई है या उनसे क्षति होने की संभावना है। विशेष रूप से, प्राधिकारी ने यह भी जांच की है कि क्या शुल्कों को हटाने से इस अधिसूचना में उचित खंड में घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने/उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

82. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश के अलावा अन्य देशों से आयात नगण्य है या आयात उच्च कीमतों पर किया गया है। इसलिए तीसरे देशों से आयात घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं हो सकता है। चूंकि यह एक निर्णायक समीक्षा है, इसलिए इस जांच के लिए केवल संबद्ध देश से आयात ही प्रासंगिक है।

ख) निर्यात निष्पादन

83. प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के लिए केवल घरेलू परिचालनों के आंकड़ों पर विचार किया है। किसी भी मामले में, जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निर्यात में वृद्धि हुई है, जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका – 16

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
निर्यात बिक्री	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	276	211	439

ग) मांग में संकुचन/खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन

84. यह नोट किया गया है कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है। इस प्रकार, यह नोट किया जा सकता है कि घरेलू उद्योग को क्षति मांग में काफी संकुचन के कारण नहीं हुई है।

घ) व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और प्रतिस्पर्धा की स्थिति

85. संबद्ध वस्तु के आयात पर किसी भी तरह से प्रतिबंध नहीं है और देश में इनका मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह पता चले कि विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों में कोई बदलाव आया है।

ड.) प्रौद्योगिकी में विकास

86. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रौद्योगिकी में ऐसे किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रदर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकता हो। घरेलू उद्योग ने हाल ही में भेषज उत्पादों के लिए उत्तम विनिर्माण प्रथाओं और परिसर, संयंत्र और उपकरणों की आवश्यकताओं को अपनाने के लिए काफी निवेश किया है।

च) खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन

87. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और भारत में आयातित वस्तु तुलनीय हैं और अंतिम प्रयोक्ता इन वस्तुओं को परस्पर विनिमय योग्य पाते हैं। खपत की प्रवृत्ति में संभावित परिवर्तन ऐसा कारक नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति होने का दावा किया जा सकता हो।

छ) अन्य उत्पादों के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन

88. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों के निष्पादन ने संबद्ध वस्तुओं के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पाद के प्राधिकारी द्वारा किए गए आकलन को प्रभावित नहीं किया है। प्राधिकारी द्वारा विचारित सूचना केवल पीयूसी के संबंध में है।

ज) घरेलू उद्योग की उत्पादकता

89. आकलन के अनुसार, क्षति अवधि के दौरान प्रति कर्मचारी उत्पादकता में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादकता में गिरावट घरेलू उद्योग के लिए क्षति का कोई कारण नहीं रही है।

झ. क्षति मार्जिन / कम कीमत पर बिक्री की मात्रा

90. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की क्षतिरहित कीमत को घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित किया गया है। क्षतिरहित कीमत पर क्षति मार्जिन की गणना हेतु संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना के लिए विचार किया गया है। क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यही व्यवहार सुविधाओं के साथ भी किया गया है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी असाधारण या गैर आवर्ती व्यय को उत्पादन लागत पर प्रभावित नहीं किया जाए। विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निवल स्थिर परिसंपत्ति जमा औसत कार्यशील पूंजी) पर नियमावली के अनुबंध-III में यथा विहित क्षतिरहित कीमत ज्ञात करने के लिए एक तर्कसंगत आय (कर पूर्व 22 प्रतिशत की दर से) के कर पूर्व लाभ की अनुमति दी गई थी और उसे अपनाया जा रहा है।
91. संबद्ध देश के सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच कीमत निर्धारित की है।
92. ऊपर यथा निर्धारित पहुंच कीमत और क्षतिरहित कीमत के आधार उत्पादकों / निर्यातकों के लिए प्राधिकारी द्वारा क्षति मार्जिन निर्धारित किया गया है।

तालिका - 17**क्षति मार्जिन तालिका**

क्र. सं.	देश	उत्पादक	एनआईपी यूएस डॉलर/एमटी	पहुंच मूल्य यूएस डॉलर/एमटी	क्षति मार्जिन यूएस डॉलर/एमटी	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन (रेंज %)
1	चीन जन. गण.	मेसर्स शेडोंग एनसाइन इंडस्ट्री कं, लिमिटेड	***	***	***	***	ऋणात्मक
2	चीन जन. गण.	मेसर्स जिआंगसु गुओक्सिन यूनियन एनर्जी कं, लिमिटेड	***	***	***	***	40-50

3	चीन जन. गण.	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	60-70
---	----------------	---------------------	-----	-----	-----	-----	-------

ज. पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

93. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. 5 वर्ष की अवधि के बाद पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करना मानक है। शुल्क को जारी रखना इस मानक का अपवाद है। वर्तमान समीक्षा में पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने के लिए नियम 23(1ख) के अंतर्गत अपवाद को लागू करने के लिए कोई भी परिस्थिति मौजूद नहीं है।
- ii. वर्तमान मामले में, पाटनरोधी शुल्क लगभग दस वर्षों से लागू है। तब से घरेलू उद्योग की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। साथ ही, याचिकाकर्ता ने अपनी क्षमता उपयोग में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि की है (100 से 265 सूचीबद्ध अंक)। अकेले यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि संबद्ध आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है।
- iii. वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका वर्तमान निर्णायक समीक्षा की शुरुआत का समर्थन करने के लिए कोई सकारात्मक साक्ष्य दर्शाने में विफल रही। वर्तमान याचिका समीक्षा की शुरुआत की आवश्यकता को प्रमाणित नहीं करती है क्योंकि घरेलू उद्योग पहले से ही लागू शुल्कों के कारण हुई पिछली क्षति से उबर चुका है।
- iv. आवेदन इस तथ्य के आधार पर दायर किया गया है कि क्षति जारी है। घरेलू उद्योग को वर्तमान में कोई क्षति नहीं हो रही है। परिणामस्वरूप, आवेदन दायर करने का आधार ही गलत है और जांच को समाप्त किया जाना चाहिए।
- v. याचिकाकर्ता ने पाटन और क्षति की संभावना को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं दिए हैं। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद आयात की मात्रा में केवल वृद्धि, पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने के बाद पाटन और क्षति की संभावना को स्थापित करने के लिए अपर्याप्त है, खासकर तब जब आयात में वृद्धि के साथ-साथ आवेदक की सीमित क्षमता के साथ-साथ घरेलू मांग में भी वृद्धि हुई हो।
- vi. याचिकाकर्ता को यह दर्शाने के लिए सकारात्मक साक्ष्य देने की आवश्यकता है कि पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है। जापान से जंग-रोधी कार्बन स्टील फ्लैट उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क की संयुक्त राज्य अमेरिका-निर्णायक समीक्षा (डब्ल्यूटी/डीएस244/एबी/आर) के मामले में डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय के निर्णय और मेक्सिको से ऑयल कंट्री ट्यूबलर गुड्स पर संयुक्त राज्य अमेरिका – पाटनरोधी उपाय के डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय के निर्णय (डब्ल्यूटी/डीएस282/एबी/आर) का संदर्भ दिया जा सकता है।
- vii. व्यापार उपचार महानिदेशक द्वारा जारी 'व्यापार उपचार जांच के लिए परिचालन प्रथाओं के मैनुअल' में निर्धारित प्रक्रियाओं को घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- viii. प्राधिकारी से यह भी अनुरोध है कि वे प्रचालन प्रथाओं के व्यापार उपचार मैनुअल के पैराग्राफ 17.30 के अनुसार जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान आयात की मात्रा और मूल्य के आंकड़ों की समीक्षा करें।
- ix. पीवीसी फ्लेक्स फिल्म के लिए द्वितीय एसएसआर के मामले में, सेस्टेट ने माना था कि जांच के दौरान पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्य रिकॉर्ड पर रखने का दायित्व याचिकाकर्ता का है ताकि एडीडी के समाप्त होने पर पाटन और क्षति जारी रहने की संभावना को उचित ठहराया जा सके। सेस्टेट ने माना कि निर्धारण अनुमान या मात्र धारणा पर या पूर्व धारणा पर आधारित नहीं हो सकता, बल्कि उसे किसी ठोस और सकारात्मक साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए।

- x. केवल इसलिए कि संबद्ध देश में उच्च निर्यात क्षमता है, इसका यह अर्थ नहीं है कि इन देशों के पास विशेष रूप से भारत के लिए पीयूसी के उपयोग और निर्यात के लिए कोई अतिरिक्त या निष्क्रिय क्षमता उपलब्ध है।
- xi. याचिकाकर्ता ने बाजार आसूचना या अन्य स्रोतों के माध्यम से ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया है, जिससे यह पता चले कि एक बार पाटनरोधी शुल्क समाप्त हो जाने पर संबद्ध देश के उत्पादक तुरंत ही भारत को पाटित कीमतों पर पीयूसी का निर्यात करना शुरू कर देंगे।
- xii. प्राधिकारी इस जांच में प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर उत्पादकों के पास उपलब्ध क्षमताओं का सत्यापन कर सकते हैं ताकि यह स्थापित किया जा सके कि संबद्ध देश से भारत में निर्यात की कोई संभावना नहीं है और इस प्रकार, पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति की कोई संभावना नहीं है।
- xiii. संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा एडीडी जांच से संबंधित याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत मामलों के संबंध में, उन मामलों में पीयूसी का दायरा बहुत व्यापक था और संबद्ध जांच में पीयूसी को शामिल किया गया था। परिणामस्वरूप, उन मामलों में उद्धृत क्षमताओं में न केवल पीयूसी बल्कि अन्य साइट्रेट्स के एक बड़े उत्पाद समूह की क्षमताएं भी शामिल हैं। इसलिए, उन जांचों में उद्धृत क्षमताएं संबद्ध जांच के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।
- xiv. अधिशेष क्षमताओं की केवल मौजूदगी क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना को स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- xv. भारत में निर्यात शिफ्ट करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है और इस बात से इंकार किया जाता है कि भारतीय बाजार आकर्षक बना हुआ है। चूंकि पाटनरोधी शुल्क लगभग दस साल से लागू रहा है, इसलिए याचिकाकर्ता ने आयात से प्रभावी प्रतिस्पर्धा के अभाव में अपनी बाजार स्थिति को पहले ही मजबूत और सुदृढ़ कर लिया है।
- xvi. भारत में 20,000-22,000 एमटी की सीमित मांग और एक सुस्थापित घरेलू उद्योग को देखते हुए भारतीय बाजार कोई आकर्षक प्रतीत नहीं होता है। यदि चीन जन.गण. के उत्पादक भारत की ओर अपने उत्पादन का रुख करते भी हैं तो भी इससे उनके क्षमता उपयोग में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

94. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. संबद्ध देश से पाटित कीमतों पर भारत को पीयूसी का निर्यात जारी है और ऐसे पर्याप्त आधार हैं जो संकेत करते हैं कि वर्तमान शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में ऐसा पाटन जारी रहेगा।
- ii. यद्यपि उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग जैसे क्षति के मात्रात्मक मापदंडों में क्षति अवधि और जांच की अवधि में सकारात्मक विकास हुआ है। तथापि, मालसूची के स्तर में वृद्धि हुई है और क्षमता स्थिर और अल्प प्रयुक्त रही है। आधार वर्ष और जांच की अवधि के बीच पाटित आयातों का बाजार हिस्सा बढ़ा है, जो वर्तमान शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में ऐसे बाजार हिस्से में उछाल दर्ज करने की संभावना को दर्शाता है।
- iii. लाभ, आरओआई और नकद लाभ जैसे कीमत मापदंड जांच की अवधि के दौरान नकारात्मक रहे हैं और कीमत ह्रास और लागत में कटौती बिल्कुल स्पष्ट है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को लगातार क्षति हो रही है और इस तरह की क्षति का कारण कीमत ह्रास के स्तर पर और घरेलू उद्योग की लागत और एनआईपी से कम कीमत पर पाटित आयातों का जारी रहना है। वर्तमान एडीडी की समाप्ति की दशा में यह स्थिति और खराब हो जाएगी।

- iv. जैसा कि वर्तमान जांच में स्पष्ट है कि संबद्ध देश से पाटन और परिणामी क्षति में वृद्धि होने की बहुत अधिक संभावना है तथा मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।
- v. चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के निर्यात पर द्वितीय निर्णायक समीक्षा के पश्चात यूरोपीय संघ (एडीडी) और यूएसए (एडीडी और सीवीडी) जैसे अन्य प्रमुख बाजारों में पाटनरोधी और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए गए हैं तथा यह बहुत अधिक संभावना है कि ऐसी स्थिति में भारत में वर्तमान एडीडी की समाप्ति केवल चीन जन. गण. के निर्यातकों के लिए ही शुभ संकेत होगी। ब्राजील, थाईलैंड, रूस आदि द्वारा भी एडीडी लगाया गया है। प्राधिकारी ने प्रथम एसएसआर के समय भी ऐसे शुल्कों का संज्ञान लिया था। यूरोपीय संघ और यूएसए जैसे क्षेत्राधिकारों में पीयूसी का दायरा सोडियम साइट्रेट को कवर करता है, यद्यपि उनके पास उत्पाद का दायरा व्यापक है।
- vi. उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि चीन जन. गण. के उत्पादकों के पास 6-7 लाख एमटी के बराबर पर्याप्त मुख्य रूप से निपटान योग्य क्षमता है, जो कुल भारतीय मांग का 30-35 गुना है। यदि एडीडी समाप्त हो जाता है तो ऐसी अतिरिक्त सामग्री भारत में भेज दी जाएगी। आवेदक द्वारा प्रस्तुत चीन जन. गण. में अतिरिक्त क्षमता पर दावों को गलत साबित करने के लिए किसी भी पक्ष द्वारा कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है और आवेदक के अतिरिक्त क्षमता आदि के दावे साक्ष्यों द्वारा समर्थित हैं।
- vii. ऐसी परिस्थिति में एडीडी की समाप्ति से लगभग 19,000-20,000 एमटी मांग वाला मजबूत भारतीय बाजार चीन जन. गण. के उत्पादकों को सौंपे जाने की तरह होगा, जो वास्तव में अतिरिक्त और अप्रयुक्त क्षमताओं और यूरोपीय संघ, यूएसए आदि में भारी एडीडी/सीवीडी के साथ-साथ यूएसए में अन्य टैरिफ बाधाओं के मद्देनजर बाजार के अवसरों के लिए जुद्ध रहे हैं। ऐसे बाजार में एडीडी/सीवीडी जनवरी (यूएसए) और अप्रैल 2021 (ईयू) से अगले पांच वर्षों के लिए पिछले समय-विस्तार के बाद से अभी भी लागू हैं।
- viii. शुल्कों की राशि में आवश्यक वृद्धि के साथ चीन जन. गण. पर पाटनरोधी शुल्क को पांच वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ाने की आवश्यकता है। वर्तमान राशि पाटन का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रतिवादी उत्पादकों को कोई शून्य शुल्क नहीं मिलना चाहिए, भले ही वे नकारात्मक मार्जिन दिखाएं, जब तक कि पाटन और क्षति की संभावना है और ध्यान समग्र रूप से चीन जन. गण. के लिए संभावना विश्लेषण पर होना चाहिए जो प्राधिकारी द्वारा कानून और प्रथाओं की एक स्थापित स्थिति है।
- ix. जांच की अवधि के बाद की जानकारी भी महत्वपूर्ण रूप से सकारात्मक स्तरों पर निरंतर पाटन और क्षति मार्जिन का जारी रहना दर्शाती है जो वर्तमान शुल्कों की समाप्ति के मामले में संभावित स्थिति का संकेतक है। जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान आयात की कीमत में गिरावट प्रमुख कच्चे माल की कीमत में गिरावट से काफी अधिक रही है जो चीन जन. गण. के उत्पादकों द्वारा भारत को संबद्ध वस्तुओं के निर्यात में अभी भी चल रहे पाटन का एक मजबूत संकेतक है।
- x. मेसर्स डेफोडिल फार्माकेम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर आवेदन चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क को अगले 5 वर्षों के लिए जारी रखने की आवश्यकता को दर्शाता है क्योंकि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में ऐसे आयातों से पाटन और क्षति की संभावना बिल्कुल स्पष्ट है।
- xi. बोरेक्स मोरारजी लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में नियम 23 (1ख) के तहत समीक्षा को शासित करने वाले नियमों के साथ पठित सीटीए, 1975 की धारा 9क (5) की आवश्यकताओं की व्याख्या माननीय सेस्टेट द्वारा की गई है, जिसमें यह देखा गया था कि अभिव्यक्ति "पुनरावृत्ति की ओर जाने की संभावना" उस स्थिति को अपने दायरे में लेगी, जहां पाटन और क्षति समीक्षा के समय मौजूद नहीं हो, क्योंकि पाटनरोधी शुल्क लागू है और जारी है, जिसे यदि पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने पर हटा दिया जाता है, तो पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इस प्रकार, यदि वर्तमान में कोई पाटन

- और क्षति नहीं है, तो भी एडीडी जारी रहने योग्य है और आवश्यकता पाटन और क्षति की संभावना दर्शाने वाले कारकों की है।
- xii. चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "फ्लैट बेस स्टील व्हील्स" के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की तीसरी निर्णायक समीक्षा जांच और 12 जून 2023 के अंतिम जांच परिणाम जैसे मामलों में जहां संबद्ध देश से कोई आयात नहीं हुआ है और पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है, वहां शुल्क जारी रखा गया।
- xiii. साइट्रिक एसिड संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए मुख्य कच्ची सामग्री है। अब तक भारत साइट्रिक एसिड का आयात करता है क्योंकि वर्ष 2005 में भारत में साइट्रिक एसिड के पाटित आयातों पर एडीडी लगवाने में बिल्कुल विफल रहने के बाद भारत में साइट्रिक एसिड का उत्पादन बंद हो गया था। 2005 के जांच परिणाम से पता चलता है कि प्राधिकारी ने उक्त जांच की जांच अवधि तक निष्पादन में सुधार का उल्लेख करते हुए एडीडी की सिफारिश नहीं की, भले ही उद्योग घाटे में था। भारत अब साइट्रिक एसिड का निवल आयातक है और हमें आशंका है कि यदि चीन जन. गण. में अतिरिक्त संबंधित क्षमता को देखते हुए भी एडीडी को समाप्त किया जाता है तो संबद्ध वस्तु के उत्पादकों के साथ भी यही हो सकता है।
- xiv. पाटन और क्षति की संभावना को संबद्ध देश के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, न कि केवल प्रतिवादी निर्यातकों के संदर्भ में। इस प्रकार, भले ही प्रतिवादी निर्यातक अपने निर्यात के संबंध में पाटन और क्षति की संभावना का अभाव दर्शाते हों, फिर भी केवल संभावना का देशव्यापी निर्धारण प्रासंगिक है।
- xv. प्रतिवादी निर्यातकों ने पाटन और क्षति की संभावना का अभाव नहीं दर्शाया है और चीन जन. गण. से भारत को संबद्ध वस्तु के निर्यात के संबंध में संभावना का निर्धारण करने के लिए अनिवार्य प्रासंगिक जानकारी के संदर्भ में यह उत्तर अपर्याप्त है। प्रतिवादी निर्यातकों ने यह कहते हुए संभावना विश्लेषण के लिए प्रासंगिक ईक्यूआर में महत्वपूर्ण पहलुओं पर मांगी गई जानकारी को खाली छोड़ दिया है कि ऐसी सूचना लागू नहीं होती है।
- xvi. पीओआई में कोई भी नकारात्मक मार्जिन एसएसआर में एडीडी को समाप्त करने का कारक नहीं है और जो प्रासंगिक है वह संभावना की जांच है। इस प्रकार, जब तक भारत को संबद्ध वस्तुओं के निर्यात से पाटन और क्षति की संभावना है, तब तक प्रतिवादी उत्पादक अर्थात् मेसर्स जियांगसू गुओक्सिन यूनियन एनर्जी कंपनी लिमिटेड पर एडीडी जारी रखा जाना चाहिए। क्लियर फ्लोट ग्लास से संबंधित एसएसआर जैसे मामलों में प्राधिकारी द्वारा अतीत में यही दृष्टिकोण अपनाया गया है।
- xvii. मूल जांच में तथा प्रथम निर्णायक समीक्षा में और वर्तमान आवेदन में भी संबद्ध देश के संबंध में निर्धारित पाटन मार्जिन यह दर्शाता है कि पहले पाया गया पाटन अभी भी जारी है और चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के उत्पादकों/निर्यातकों ने भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं के पाटन की प्रक्रिया बंद नहीं की है।
- xviii. चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु की क्षमताएं स्पष्ट रूप से निर्यात उद्देश्यों के लिए स्थापित की गई हैं क्योंकि चीन जन. गण. में घरेलू मांग चीन जन. गण. में कुल उपलब्ध क्षमता का 24% भी नहीं है, जैसा कि यूरोपीय संघ के प्राधिकारी ने पाया है। यह इस तथ्य को इंगित करता है कि वर्तमान शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं का निर्यात जारी रहेगा और लागू एडीडी की समाप्ति पर पाटित दरों पर निर्यात में वृद्धि की संभावना है। निर्यात उन्मुख होना स्पष्ट है।
- xix. भारत द्वारा ऐसे समय में मौजूदा एडीडी की समाप्ति की अनुमति देना जबकि अन्य देशों द्वारा अभी भी ऐसे उपाय लागू हैं, से भारत को पाटित दरों पर निर्यात में और वृद्धि होगी, जो वर्तमान शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में पाटन को पूरी संभावना को भी दर्शाता है।

- xx. प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा दिए गए उत्तर से पता चलता है कि उन्हें आने वाले समय में अपने निर्यात में वृद्धि की उम्मीद है और उत्तर के अनुलग्नक III के अनुसार अनुमान से पता चलता है कि मेसर्स शैंडोंग एनसाइन इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड के मामले में उनके द्वारा भारत को निर्यात वर्ष 2021 में 100 सूचीबद्ध बिंदुओं से बढ़कर वर्ष 2025 में 300 अंक होने की उम्मीद है। मेसर्स जियांग्सू गुओक्सिन यूनियन एनर्जी कंपनी लिमिटेड के मामले में अनुमान जांच की अवधि में 100 सूचीबद्ध बिंदुओं से 69 बिंदु है और इसके 2025 तक 90 सूचीबद्ध बिंदु तक होने का अनुमान है। इस प्रकार, निर्यातक भारत को अधिक निर्यात करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और एडीडी की कोई भी समाप्ति उनके लिए एक अप्रत्याशित अवसर होगी।
- xxi. चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के पाटित आयात पूरी क्षति अवधि और जांच की अवधि के दौरान जारी रहा और वास्तव में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि तक आयात लगभग दोगुना हो गया। भारतीय मांग में ऐसे पाटित आयातों के हिस्से में भी जांच अवधि तक वृद्धि हुई है, जो यह दर्शाती है कि यदि एडीडी समाप्त हो जाता है तो ऐसे आयातों में काफी वृद्धि होगी।
- xxii. सहयोगी निर्यातक द्वारा साझा की गई सूचना के आधार पर प्रथम निर्णायक समीक्षा में संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु की मालसूची काफी उच्च स्तर पर पाई गई है और चीन जन. गण. के पास उत्पाद के लिए बड़ी सरलता से उपलब्ध मालसूची है जिसे वर्तमान शुल्क की समाप्ति की स्थिति में आसानी से भारत में भेजा जा सकता है। यह अनुमान लगाया गया है कि चीन जन. गण. के पास चालू मालसूची के रूप में अपने उत्पादन के बराबर न्यूनतम 5-10% है जो पूर्ण रूप से 70,000 एमटी से 1,40,000 एमटी की रेंज में होगा।

ब.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

95. वर्तमान समीक्षा चीन जन. गण. से पीयूसी के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की एक निर्णायक समीक्षा है। एडी नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी के लिए यह निर्धारित करना अपेक्षित है कि क्या मौजूदा शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
96. प्राधिकारी ने धारा 9क (5), नियम 23 और नियम के अनुबंध-II (vii) के अनुसार वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मापदंडों और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड में लाए गए अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करते हुए क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना की जांच की है।
97. ऐसा कोई संभावना विश्लेषण करने के लिए कोई विशिष्ट पद्धति उपलब्ध नहीं है। तथापि, नियमावली के अनुबंध II के खंड (vii) में, अन्य बातों के साथ-साथ उन कारकों के बारे में प्रावधान है जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है, अर्थात् -
- क) भारत में पाटित आयातों की वृद्धि की काफी अधिक दर, जो आयात में पर्याप्त वृद्धि की संभावना को दर्शाती हो।
- ख) निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य, या आसन्न, पर्याप्त वृद्धि, जो किसी भी अतिरिक्त निर्यात खपत के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजारों में पाटित निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना को दर्शाती है।
- ग) क्या आयात ऐसी कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं, जिनका घरेलू कीमत पर काफी अधिक ह्रासकारी या न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा और आगे के आयातों की मांग में वृद्धि होने की संभावना होगी; और
- घ) वस्तु की मालसूची की जांच की जा रही है।
98. प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करने के लिए उपर्युक्त आवश्यकताओं और निम्नलिखित मापदंडों पर विचार किया है कि क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना है और यदि हां, तो क्या इससे घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड में लाई गई समस्त संगत सूचना की जांच की है।

क) पाटित किए गए आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि दर

99. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि तक संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात में वृद्धि हुई है। इस जांच में नोट किए गए अनुसार संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात नीचे तालिका में दर्शाए गए हैं:

तालिका – 18

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
चीन जन. गण. से आयात (संबद्ध आयात)	एमटी	1,137	1,418	2,123	2,025
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	125	187	178

100. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी आयात जारी रहे हैं और आयात में लगातार वृद्धि हो रही है। परिणामस्वरूप, यदि इन शुल्कों को समाप्त होने दिया जाता है, तो संबद्ध देश से आयात में वृद्धि होने की संभावना है।

ख) निरंतर पाटन और क्षति

101. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की वर्तमान अवधि में पीयूसी का आयात पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद पाटित कीमतों पर किया हुआ है। यह भी नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग का निष्पादन में लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में काफी गिरावट आई है।
102. आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, प्राधिकारी ने नोट करते हैं कि संबद्ध देश में पीयूसी के उत्पादन के लिए पर्याप्त अतिरिक्त और अप्रयुक्त क्षमताएं हैं। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि चीन जन. गण. में कुल स्थापित क्षमताएं 6-7 लाख एमटी से अधिक हैं, जबकि देश में संबद्ध वस्तु की कुल मांग केवल 19,000-20,000 एमटी होने का अनुमान है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत विवरण को निम्नानुसार नोट किया गया है:

तालिका – 19

विवरण	मात्रा
यूएसआईटीसी/यूएसडीओसी ¹ तथा ईयू/ईसी ² के जांच परिणाम के अनुसार चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के लिए क्षमता	19.40 लाख एमटी से 21.88 लाख एमटी
ईसी जांच परिणाम के अनुसार चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तुओं की घरेलू मांग	4.65 लाख एमटी
निर्यात के लिए उपलब्ध क्षमता (चीन जन.गण. में क्षमता ऋण घरेलू मांग)	14.75 लाख एमटी से 17.23 लाख एमटी
चीन जन.गण. से निर्यात (68.75 प्रतिशत उपयोग की दर पर उत्पादन ऋण घरेलू मांग के बीच अंतर)	8.69 लाख एमटी से 10.39 लाख एमटी

¹ यूएसआईटीसी ने जांच परिणाम में साइट्रिक एसिड, सोडियम साइट्रेट और पोटेशियम साइट्रेट के सभी ग्रेड और दाने के आकार उनके अमिश्रित रूपों में, चाहे सूखे या घोल में और पैकेजिंग प्रकार पर विचार किए बिना - जांच संख्या 701-टीए-456 और 731-टीए-1152 (दूसरी समीक्षा) 4 जनवरी, 2020 से प्रभावी, शामिल है।

² यूरोपीय संघ का जांच परिणाम साइट्रिक एसिड और ट्राइसोडियम साइट्रेट डाइहाइड्रेट - आयोग कार्यान्वयन विनियमन (ईयू) 2021/607 दिनांक 14 अप्रैल 2021 को कवर करता है।

विवरण	मात्रा
अतिरिक्त/अप्रयुक्त क्षमता (क्षमता ऋण घरेलू जमा निर्यात बिक्रियां)	6.06 लाख एमटी से 6.84 लाख एमटी

103. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि भारतीय जांच तथा आवेदक द्वारा भरोसा किए गए यूरोपीय संघ और यूएसए पाटनरोधी शुल्क / प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच परिणाम में पीयूसी की परिभाषा के बीच पीयूसी के दायरे में अंतर है। इस संबंध में, यह नोट किया गया है कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पहली निर्णायक समीक्षा जांच में भी इसी प्रकार के तर्क दिए गए थे। यह नोट किया गया है कि ऐसे क्षेत्राधिकार में पीयूसी की परिभाषा भारत द्वारा जांच में यथा परिभाषित संबद्ध वस्तु को कवर करती है और ऐसे विदेशी प्राधिकारियों द्वारा दिए गए निष्कर्ष से यह स्पष्ट है कि ऐसे प्राधिकारियों ने सोडियम साइट्रेट को कवर करने वाली अपनी एडीडी/सीवीडी निर्णायक समीक्षा जांच के संचालन में संभावना पहलू की जांच करते समय भारत द्वारा की गई जांच का भी संज्ञान लिया था। यह तर्क देने वाले निर्यातकों द्वारा यह नहीं दर्शाया गया है कि चीन जन. गण. में क्षमता पर ऐसे निष्कर्ष भारतीय पाटनरोधी जांच में यथा परिभाषित सोडियम साइट्रेट पर कैसे लागू नहीं होते हैं और न ही यह दर्शाने के लिए कोई जानकारी प्रस्तुत की गई है कि ऐसा आधार मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स में उपयुक्त नहीं है।

104. इसके अलावा, संबद्ध देश से प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर का विश्लेषण निम्नानुसार है:

तालिका – 20

विवरण	यूनिट	शेडोंग एनसाइन	जियांगसू गुओक्सिन	सहकारी निर्यातकों की कुल संख्या
संस्थापित क्षमता	एमटी	***	***	***
उत्पादन	एमटी	***	***	***
क्षमता उपयोग	%	***	***	***
घरेलू बिक्रियां	एमटी	***	***	***
भारत में निर्यात बिक्रियां	एमटी	***	***	***
अन्य देशों में निर्यात बिक्रियां	एमटी	***	***	***
कुल निर्यात (भारत + अन्य)	एमटी	***	***	***
कुल बिक्रियां (घरेलू + निर्यात)	एमटी	***	***	***
अधिशेष/अप्रयुक्त क्षमताएं	एमटी	***	***	***
निर्यात उन्मुखन – कुल बिक्रियों से निर्यात बिक्री का अनुपात	%	***	***	***
निर्यात उन्मुखन – कुल बिक्रियों से निर्यात बिक्री का अनुपात	% रेंज	50-60	45-55	45-55
मालसूची	एमटी	***	***	***
अप्रयुक्त क्षमता प्रतिशत में	%	***	***	***
उत्पादन के प्रतिशत के रूप में मालसूची	%	***	***	***

105. उपर्युक्त जानकारी से यह नाट किया जाता है कि प्रतिवादी निर्यातकों के पास भी काफी अप्रयुक्त क्षमताएं और उनकी मालसूची में सामग्री उपलब्ध है। ऐसे उत्पादकों का निर्यात उन्मुखीकरण भी स्पष्ट है, क्योंकि कुल बिक्री का आधे से अधिक हिस्सा निर्यात बाजारों को जाता है।

ग) विभिन्न देशों द्वारा शुल्क लगाया जाना

106. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के निर्यात पर दूसरी निर्णायक समीक्षा के बाद यूरोपीय संघ में पाटनरोधी उपाय लागू रहना जारी है और इसी तरह, चीन जन. गण. से अमेरिका को संबद्ध वस्तु के निर्यात पर पाटनरोधी और प्रतिसंतुलनकारी दोनों उपाय लागू हैं और ऐसे शुल्क दूसरी निर्णायक समीक्षा के बाद भी जारी रहे हैं। प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा दिए गए उत्तर में यह भी कहा गया है कि यूरोपीय संघ, अमेरिका, ब्राजील में पीयूसी पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है और अमेरिका में विशेष टैरिफ भी लगाया गया है।
107. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर ऐसे शुल्कों का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका - 21

देश/ उपाय	5 वर्षों के लिए अंतिम लेवी/विस्तार की प्रभावी तिथि	उत्पाद का विवरण	शुल्क की राशि
ईयू/एडीडी	14 अप्रैल, 2021- आयोग कार्यान्वयन विनियमन (ईयू) 2021/607 दिनांक 14 अप्रैल 2021	साइट्रिक एसिड और ट्राइसोडियम साइट्रेट डाइहाइड्रेट	15.3% से 42.7%
यूएसए/सीवीडी	4 जनवरी, 2021- [ए-570-937, सी-570-938] चीन जन. गण. से साइट्रिक एसिड और कतिपय साइट्रेट साल्ट: पाटनरोधी शुल्क और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जारी रखने के आदेश -फेडरल रजिस्टर/वॉल्यूम 86, नंबर 1/सोमवार, 4 जनवरी, 2021	साइट्रिक एसिड, सोडियम साइट्रेट और पोटेशियम साइट्रेट के सभी ग्रेड और दाने के आकार, उनके अमिश्रित रूपों में, चाहे सूखे हों या घोल में, और पैकेजिंग के प्रकार पर विचार किए बिना।	52.22% से 166.34%
यूएसए/एडीडी	4 जनवरी, 2021- [ए-570-937, सी-570-938] चीन जन. गण. से साइट्रिक एसिड और कतिपय साइट्रेट साल्ट: पाटनरोधी शुल्क और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जारी रखने के आदेश -फेडरल रजिस्टर/वॉल्यूम 86, नंबर 1/सोमवार, 4 जनवरी, 2021	साइट्रिक एसिड, सोडियम साइट्रेट और पोटेशियम साइट्रेट के सभी ग्रेड और दाने के आकार, उनके अमिश्रित रूपों में, चाहे सूखे हों या घोल में, और पैकेजिंग के प्रकार पर विचार किए बिना।	156.87%

108. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश के निर्यातक और उत्पादक पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद भारत में पीयूसी का पाटन कर रहे हैं। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि पाटन व्यवहार से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में, संबद्ध देश के उत्पादक/निर्यातक भारत में उत्पाद का पाटन बड़ी हुई मात्रा के स्तर पर जारी रखेंगे। यह भी नोट किया गया है कि यूरोपीय संघ और यूएसए जैसे अन्य क्षेत्राधिकार में पीयूसी का दायरा वर्तमान समीक्षा में संबद्ध वस्तुओं को कवर करता है।

घ) पीओआई के बाद की सूचना

109. चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा है, इसलिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया गया है कि प्राधिकारी इस जांच में जांच की अवधि के बाद की सूचना पर भी विचार कर सकते हैं और हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया गया है कि वे किए जाने वाले संभावना विश्लेषण के मद्देनजर जांच की अवधि के बाद की सूचना, यदि कोई हो, प्रस्तुत करें, जिस पर घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत की है:

i. जांच अवधि के बाद संबद्ध वस्तु का आयात (डीजीसीआई एंड एस के अनुसार)

तालिका – 22

मात्रा (एमटी में)					
देश	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	अप्रैल से सितंबर (2024-25)
चीन जन. गण.	1,137	1,418	2,123	2,025	483
कुल	1,722	1,727	2,375	2,409	572

तालिका – 23

कीमत सीआईएफ (रु/ कि.ग्रा.)					
देश	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	अप्रैल से सितंबर (2024-25)
चीन जन. गण.	53	89	120	84	58
कुल	164	132	163	140	148

ii. जांच की अवधि के बाद साइट्रिक एसिड का आयात - (डीजीसीआई एंड एस के अनुसार) (संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री)

तालिका – 24

मात्रा (एमटी में)					
देश	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	अप्रैल से सितंबर (2024-25)
चीन जन. गण.	92,387	98,703	1,30,156	1,12,096	61,428
कुल	94,966	1,00,029	1,31,440	1,17,653	66,302

तालिका – 25

कीमत सीआईएफ (रु/ कि.ग्रा.)					
देश	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	अप्रैल से सितंबर (2024-25)
चीन जन. गण.	48.37	100.08	106.38	61.75	60.49
कुल	50.07	100.66	107.05	67.83	65.40

110. आवेदक ने जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों के आधार पर दावा किया है कि जांच की अवधि के बाद की अवधि में चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के आयात की कीमत में और कटौती हुई है तथा कीमत में गिरावट जांच की अवधि की तुलना में लगभग 31% है। इसके अलावा, जांच की अवधि की तुलना में जांच की अवधि के बाद की अवधि में संबद्ध वस्तु की आयात कीमत में 31% की कमी आई है, परंतु प्रमुख कच्ची सामग्री अर्थात् साइट्रिक एसिड की कीमत में केवल लगभग 4% की गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि कीमत में इतनी अधिक गिरावट यह दर्शाती है कि चीन जन. गण. द्वारा अभी भी पाटन किया जा रहा है।

iii. पीओआई के बाद की अवधि में पाटन और क्षति मार्जिन

111. आवेदक ने मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की अनुपस्थिति में संभावित स्थिति को इंगित करने के लिए जांच की अवधि के बाद की अवधि में सकारात्मक पाटन और क्षति मार्जिन का दावा किया।

ड.) भारतीय बाजार की आकर्षकता

112. आवेदकों ने दावा किया है कि भारतीय बाजार आकर्षक है क्योंकि भारत में संबद्ध वस्तु की मांग में लगातार वृद्धि हुई है। आधार वर्ष और जांच अवधि के बीच उत्पाद की मांग में 66% की वृद्धि हुई है जो भारत को चीनी के उत्पादकों के लिए एक आकर्षक बाजार बनाती है।

113. आवेदक ने यह भी अनुरोध किया है कि भारत चीन से निर्यात की एक महत्वपूर्ण मात्रा के लिए एक कीमत आकर्षक बाजार भी है।

114. इस संबंध में, चीन जन. गण. के सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के उत्तरों के आधार पर मामले की जांच की गई है। चीन के उत्पादकों को भारत में बेहतर कीमत मिलने की संभावना है और अन्य देशों की तुलना में भारत में उच्च निर्यात कीमतों के कारण चीन के उत्पादकों द्वारा अपने तीसरे देशों के निर्यात को भारतीय बाजार में स्थानांतरित करने की संभावना है। रिकॉर्ड में जानकारी की जांच से निम्नानुसार पता चलता है:

तालिका – 26

विवरण	शेडोंग एनसाइन	जियांगसु गुओक्सिन
चीन से शेष विश्व को भारतीय कीमतों से कम कीमतों पर निर्यात - प्रतिक्रियाओं के आधार पर।	***	***
भारतीय मांग	***	***
भारतीय मांग के संबंध में कम कीमत वाले तीसरे देशों के निर्यात	***	***
भारतीय मांग के संबंध में कम कीमत वाले तीसरे देशों के निर्यात - % रेंज	290-300	25-35

च) आयात ऐसी कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं जिनसे घरेलू उद्योग की कीमतों में काफी अधिक ह्रास या न्यूनीकरण होने की संभावना है।

115. संबद्ध आयात पहले से ही ऐसी कीमत पर प्रवेश कर रहे हैं जो घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है। आवेदन में यह भी तर्क दिया गया है कि चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं की कीमत में लगभग 28 रूपए प्रति किलोग्राम की गिरावट साइट्रिक एसिड की कीमत में गिरावट के कारण थी, जबकि चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं की कीमत में वास्तविक गिरावट 36 रूपए प्रति किलोग्राम रही है जो कच्ची सामग्री की कीमत में गिरावट के अनुपात में लगभग 8 रूपए प्रति किलोग्राम की अधिक गिरावट दर्शाती है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वृद्धि, बिक्री की लागत में वृद्धि के समान दर से नहीं बढ़ी, जो क्षति अवधि के दौरान कीमत ह्रास दर्शाता है। यह भी नोट किया गया है कि आयातों की पहुंच कीमत पूरी क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम रही है। पाटनरोधी शुल्क की अनुपस्थिति में संबद्ध आयातों से ऐसे कीमत प्रभाव के जारी रहने की संभावना है।
116. इस तर्क के संबंध में कि 5 वर्ष की अवधि के बाद पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करना मानक है और शुल्क को जारी रखना मानक का अपवाद है, यह नोट किया जाता है कि नियम 23(1ख) में उल्लेख है कि "उप-नियम (1) या 1(क) में निहित किसी भी बात के बावजूद, अधिनियम के तहत लगाया गया कोई भी निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क उसके लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि के लिए प्रभावी होगा, जब तक कि निर्दिष्ट प्राधिकारी उस अवधि से पहले अपनी पहल पर या घरेलू उद्योग की ओर से या उसके द्वारा किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित अनुरोध पर, उस अवधि की समाप्ति से पहले तर्कसंगत अवधि के भीतर शुरू की गई समीक्षा के आधार पर इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं कि उक्त पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग के लिए पाटन और क्षति जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।" इस प्रकार, लागू शुल्क 5 वर्ष की अवधि बीतने पर ऐसी स्थिति में समाप्त होता है, जहां नियम के अंतर्गत परिकल्पित कोई समीक्षा शुरू नहीं की जाती है और उस अवधि की समाप्ति से पहले तर्कसंगत अवधि के भीतर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाता है। वर्तमान मामले में, नियम 23 (1ख) के तहत परिकल्पित समीक्षा समय पर शुरू की गई है और नियम के तहत कोई भी अंतिम जांच परिणाम जारी करने के लिए समय उपलब्ध है।
117. इस तर्क के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क लगभग दस वर्षों से लागू है तथा संबद्ध आयातों पर लगाया गया पाटनरोधी शुल्क अपने उद्देश्य को पूरा कर चुका है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जब तक पाटन और क्षति की संभावना है, तब तक शुल्क जारी रखने का अधिदेश है तथा इस अधिसूचना में उचित स्थानों पर वर्तमान मामले के तथ्यों पर ध्यान दिया गया है।
118. इस तर्क के संबंध में कि वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका वर्तमान निर्णायक समीक्षा की शुरुआत का समर्थन करने के लिए कोई सकारात्मक साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रही, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच संभावना का निर्धारण करने के लिए प्रासंगिक साक्ष्यों की प्रथमदृष्टया संतुष्टि के आधार पर शुरू की गई थी तथा उसके बाद सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए संभावना के दावों के पक्ष में तथा उसके विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने का विकल्प खुला था। इस अधिसूचना में केवल साक्ष्यों द्वारा समर्थित दावों को ही प्रासंगिक माना गया है।
119. इस तर्क के संबंध में कि प्राधिकारी को प्रचालन प्रथाओं के व्यापार उपचार मैनुअल के पैराग्राफ 17.30 के अनुसार जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान आयातों की मात्रा और मूल्य के आंकड़ों की समीक्षा करनी चाहिए, यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों को जांच की अवधि के बाद की जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया गया है और हितबद्ध पक्षकारों से इस अवधि के लिए प्राप्त जानकारी इस अधिसूचना का हिस्सा है और ऐसी जानकारी इस मामले में निष्कर्ष का भाग बन सकती है।

120. इस तर्क के संबंध में कि भारत में 20,000-22,000 एमटी की रेंज में सीमित मांग को देखते हुए, भारतीय बाजार चीन जन. गण. के निर्यातकों के लिए कोई आकर्षक नहीं प्रतीत होता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण. के निर्यातकों के पास इतनी कम समग्र मांग में लगभग 10-15% बाजार हिस्सा था, जबकि पाटनरोधी शुल्क लागू था, जो भारतीय बाजार को आकर्षकता को दर्शाता है।

ट. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

ट. 1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

121. जांच की प्रक्रिया के दौरान अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- शुल्क जारी रखने से संबद्ध देश से मौजूदा आपूर्ति श्रृंखला बाधित होगी और घरेलू प्रयोक्ताओं को याचिकाकर्ताओं की दया पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो अनिवार्यतः घरेलू बाजार को नुकसान पहुंचाते हुए अपने निर्यात बाजार का विस्तार करने पर केंद्रित हैं।

ट. 2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

122. जांच की प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं-

- पाटनरोधी शुल्क का समय बढ़ाने से डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर या अंतिम प्रयोक्ताओं पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है और एडीडी को जारी रखना उत्पादकों, डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं और आम जनता के सर्वोत्तम हित में होगा।
- एडीडी की राशि जो मूल जांच में 367.59 अमेरिकी डॉलर प्रति एमटी थी, वर्तमान में 96.05 अमेरिकी डॉलर से 152.78 प्रति एमटी हो गई है। यद्यपि संबद्ध उत्पाद का उपयोग भेषज और खाद्य/पेय अनुप्रयोग आदि की विस्तृत श्रृंखला में किया जाता है, तथापि ऐसे उत्पादों की लागत में संबद्ध वस्तुओं का हिस्सा बहुत नगण्य है। मांगे गए एडीडी का प्रभाव ऐसे प्रयोक्ताओं पर 0.50% से कम होगा जो नगण्य है। साथ ही, इस मामले में कोई प्रयोक्ता/आयातकर्ता प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है जो यह भी दर्शाता है कि ऐसे पक्षकारों पर संबद्ध वस्तु के एडीडी का किसी भी स्तर पर कोई प्रभाव नहीं है।
- संबद्ध वस्तु का एक प्रमुख उपयोग ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन (ओआरएस) में होता है और इसका उपयोग खाद्य मर्दों में भी किया जाता है। नीचे दिए गए कुछ उदाहरणों से पता चलता है कि आवेदन में मांगी गई एडीडी की राशि का प्रयोक्ताओं की लागत पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा:

तालिका - 27

विवरण	यूनिट	मूल्य
21 ग्राम ओआरएस सैशे का खुदरा कीमत	रु/पीसी	21.82
1 सैशे में सोडियम साइट्रेट की मात्रा	ग्राम	2.90
मांगा गया एडीडी (क्षति मार्जिन)	रु/ कि.ग्रा.)	***
प्रति सैशे पर एडीडी का प्रभाव	रु/ कि.ग्रा.)	***
प्रति सैशे पर एडीडी का प्रभाव	%	***
प्रवृत्ति	रेंज	0.25-0.35%

तालिका – 28

विवरण	यूनिट	मूल्य
100 ग्राम अमूल चीज की खुदरा कीमत	रु/पीसी	80.00
1 पैकेट में सोडियम साइट्रेट की मात्रा	ग्राम	4.00
मांगा गया एडीडी (क्षति मार्जिन)	रु/ कि.ग्रा.	***
प्रति पैकेट पर एडीडी का प्रभाव	रु/ कि.ग्रा.	***
प्रति पैकेट पर एडीडी का प्रभाव	%	***
प्रवृत्ति	रेंज	0.10-0.20%

- iv. भारतीय उत्पादक सम्पूर्ण भारतीय मांग को पूरा कर सकते हैं तथा देश इस उत्पाद के लिए आत्मनिर्भर है। भारत में इस उत्पाद के लिए मांग और आपूर्ति में कोई अंतर नहीं है। साथ ही, इस उत्पाद में निर्यात की अपार संभावनाएं हैं तथा निर्यात अवसरों का लाभ उठाने के लिए, घरेलू उद्योग के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए पाटित आयातों से मुक्त एक मजबूत और समुचित घरेलू बाजार आवश्यक है।
- v. मूल जांच के समय भारत में 6 उत्पादक थे, जो प्रथम एसएसआर तथा वर्तमान समीक्षा के दौरान 11 हैं। सोडियम साइट्रेट में आने वाले वर्षों में और भी अधिक वृद्धि की संभावना है तथा यह निर्यात भी कर सकता है तथा उद्योग का ऐसा विकास देश के सार्वजनिक हित में होगा।
- vi. साइट्रिक एसिड संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए मुख्य कच्ची सामग्री है। अभी तक भारत साइट्रिक एसिड का आयात करता है, क्योंकि उत्पादकों को पाटन के कारण अपना कारोबार बंद करना पड़ा था। साइट्रिक एसिड संबद्ध वस्तुओं की कुल लागत का लगभग 45-55% है और 1 किलोग्राम सोडियम साइट्रेट का उत्पादन करते समय लगभग 620-650 ग्राम साइट्रिक एसिड (एसआईओएन बीपी/यूएसपी 0.67 से 0.74 है) की आवश्यकता होती है। साइट्रिक एसिड के आयात के बाद, उत्पादक 45-55% के बराबर पर्याप्त मूल्यवर्धन करते हैं और कंपनियों ने संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए संयंत्र और मशीनरी में पर्याप्त निवेश किया है। इस प्रकार, देश में पर्याप्त विनिर्माण आधार है और यह कोई मात्र रूपांतरण उद्योग नहीं है जिसे निरंतर पाटन के दबाव के आगे झुकने नहीं देना चाहिए।
- vii. आवेदक ने वर्ष 2022-23 के दौरान और जांच अवधि के दौरान भी मौजूदा संयंत्र में पर्याप्त निवेश किया ताकि संयंत्र/प्रक्रिया सुधार सहित वैधानिक आवश्यकताओं/दिशानिर्देशों को पूरा किया जा सके ताकि कंपनी नई अनुसूची-एम दिशानिर्देशों में यथा परिकल्पित उत्तम विनिर्माण प्रथाओं को सुनिश्चित कर सके जो स्पष्ट रूप से भारतीय बाजार के लिए लक्षित है। यदि वर्तमान एडीडी की समाप्ति के कारण पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति होती है तो मूल निवेश और क्षति अवधि सहित समय-समय पर किए गए अतिरिक्त निवेश सभी व्यर्थ हो जाएंगे।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

123. प्राधिकारी ने इस बात पर विचार किया है कि क्या चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के आयातों पर वर्तमान पाटनरोधी शुल्क की अवधि बढ़ाने से जनहित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए, प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या जांच के अधीन उत्पाद के आयात पर पाटनरोधी शुल्क का समय बढ़ाना व्यापक सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा। यह निर्धारण रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना और उत्पाद के घरेलू उद्योग, आयातकों और उपभोक्ताओं सहित विभिन्न पक्षकारों के हितों पर विचार करने के आधार पर किया गया है।

124. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने उपभोक्ताओं के लिए वर्तमान जांच के संबंध में प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की, जिसमें उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव शामिल हैं। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न देशों के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की प्रतिस्थापनीयता, उपभोक्ताओं की स्रोतों को बदलने की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से उत्पन्न नई स्थिति के लिए समायोजन में तेजी लाने या देरी करने वाले कारकों के बारे में जानकारी मांगी।
125. यह नोट किया गया है कि पाटनरोधी उपायों का उद्देश्य, सामान्यतः पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को फिर से बहाल किया जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क के जारी रहने से भारत में संबद्ध वस्तु का उपयोग करके निर्मित पीयूसी के साथ-साथ अन्य डाउनस्ट्रीम उत्पादों के मूल्य स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, पाटनरोधी उपायों के लागू होने से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों के जारी रहने से घरेलू उद्योग की गिरावट पर रोक लगेगी, जो संबद्ध देश से कम कीमत वाले आयातों के परिणामस्वरूप हो सकती है और पीयूसी के उपभोक्ताओं के लिए प्रतिस्पर्धी बाजार बनाए रखने में मदद मिलेगी।
126. आरंभ में, यह नोट किया गया है कि किसी भी प्रयोक्ता/आयातक/उपभोक्ता ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है तथा किसी भी पक्षकार द्वारा ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया है जिससे यह प्रदर्शित हो कि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क के जारी रहने से ऐसे प्रयोक्ताओं तथा देश के व्यापक सार्वजनिक हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
127. वर्तमान मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स में यह स्पष्ट है कि देश में अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है और वास्तव में देश में मांग की तुलना में अधिक क्षमता है। भारतीय उत्पादकों ने जांच अवधि के दौरान पर्याप्त निर्यात भी किया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयात को रोकने के लिए पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जाता है, बल्कि घरेलू बाजार में समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगाया जाता है। पीयूसी का प्रयोक्ता उद्योग उचित कीमतों पर आयात करना जारी रख सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रयोक्ता उद्योग के लिए उचित बाजार का अस्तित्व आवश्यक है ताकि वह एकल स्रोत पर अत्यधिक निर्भर होने से बच सके जिससे भविष्य में आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान की अधिक संभावना हो सकती है।
128. प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि इच्छुक पक्षों ने यह प्रदर्शित नहीं किया है कि संबद्ध वस्तुओं की कीमतों ने उपभोक्ताओं पर किस प्रकार प्रतिकूल प्रभाव डाला है। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने मात्रात्मक जानकारी प्रस्तुत की है, जिसमें दर्शाया गया है कि उपयोगकर्ता उद्योग पर मांगे गए एंटी-डंपिंग शुल्क का प्रभाव नगण्य होगा तथा फार्मा और खाद्य जैसे प्रमुख अनुप्रयोगों में भी 0.50% से कम होगा।

ठ. पोस्ट प्रकटीकरण प्रस्तुतियाँ

ठ. 1 अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए प्रस्तुतियाँ

129. अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा अपने पिछले सबमिशन को दोहराने के अलावा निम्नलिखित पोस्ट प्रकटीकरण टिप्पणियाँ प्रस्तुत की गई हैं:
- प्राधिकारी को इस जांच को बिना किसी डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश किए समाप्त कर देना चाहिए। यदि प्राधिकारी इसके बावजूद जांच जारी रखने का फैसला करता है, तो प्राधिकारी घरेलू उद्योग के लिए गणना की गई एनआईपी को फिर से सत्यापित कर सकता है जो पहली एसएसआर की तुलना में चार्ट से बहुत दूर लगती है।

- ii. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और स्थिति के संबंध में, हम इस पर विवाद नहीं करते हैं और अन्य उत्पादकों द्वारा भागीदारी न किए जाने के कारणों की जांच करने का अनुरोध ऐसे अन्य उत्पादकों की लाभप्रदता को सत्यापित करना है। यदि अन्य गैर-भाग लेने वाले उत्पादक मुनाफे में हैं, तो याचिकाकर्ता को नुकसान डंपिंग के अलावा अन्य कारणों से होता है।
- iii. याचिकाकर्ता ने आज तक अपने किसी भी समर्थक यानी इंडिया फॉस्फेट और सुनील केमिकल्स के समर्थन पत्र का उचित एनसीवी प्रदान नहीं किया है और न ही समर्थकों की अनुक्रमित संख्या प्रदान की है।
- iv. प्रकटीकरण से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को क्षति नहीं लगी है और वह विभिन्न मापदंडों के आधार पर अनुकूल परिणाम प्रदर्शित कर रहा है, जिसे क्षति या निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना को समाप्त करने से पहले प्राधिकारी द्वारा विधिवत विचार किया जाना चाहिए।
- v. प्रकटीकरण में कहा गया है कि अनुसूची एम के अनुपालन में कैपेक्स केवल घरेलू बिक्री के लिए विशिष्ट नहीं था, बल्कि संपूर्ण सुविधा के अनुसार था। हालांकि, प्राधिकारी ने कुछ निवेशों को बाहर रखा है जो पूरी तरह से निर्यात प्रदर्शन से संबंधित हैं, हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि शेष एनएफए को निर्यात और घरेलू बिक्री के बीच तार्किक तरीके से आवंटित किया जाना चाहिए ताकि इस तथ्य पर उचित विचार किया जा सके कि निर्यात बिक्री मात्रात्मक शर्तों में 4 गुना और मूल्य के संदर्भ में 9 गुना बढ़ गई है।
- vi. एनआईपी की गणना वर्तमान जांच में अनुचित रूप से उच्च रही है, जो हम मानते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा एनएफए की भ्रामक रिपोर्टिंग और पूरे एनएफए को केवल घरेलू बिक्री के लिए आवंटित करने के कारण है।
- vii. 22% प्री-टैक्स आरओआई देने का प्राधिकारी का अभ्यास, जो हमें विश्वास है कि न केवल मनमाना है, बल्कि कल्पना के किसी भी खिंचाव से हमारे उद्योग में अत्यधिक है। हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वह 22% की व्यापक दर लागू करने के बजाय प्रत्येक उद्योग की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार आरओआई को युक्तिसंगत बनाए।
- viii. डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत प्रगतिशील उदारीकरण के सिद्धांत के अनुसार पाटनरोधी शुल्क केवल तब तक लागू रहें जब तक हानिकारक पाटन का प्रतिकार करने के लिए आवश्यक हो। घरेलू उद्योग द्वारा पहले से प्राप्त व्यापक संरक्षण इस सिद्धांत के विपरीत है।
- ix. जबकि प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आयातों की प्रवृत्ति बढ़ी हुई है, इसने यह न सोचकर गलती की है कि उन आयातों का 60% से अधिक उन विशिष्ट संस्थाओं को होता है जो अहानिकारक कीमतों पर खरीद कर रही हैं। यदि ऐसे आयातों को बाहर रखा जाता है जैसा कि मूल्य अंडरकटिंग विश्लेषण में प्राधिकारी द्वारा किया गया था, तो प्रवृत्ति के नीचे की ओर या न्यूनतम रूप से बढ़ने की संभावना है।
- x. क्षमता उपलब्धता और निर्यात अभिमुखीकरण के संबंध में प्राधिकारी ने पैरा 103 में यह स्वीकार किया है कि ईयू और यूएसए द्वारा की गई जांच का दायरा व्यापक है। तथापि, प्राधिकारी ने यह दर्शाने के लिए निर्यातकों पर जिम्मेदारी डालने की गलती की कि किस प्रकार चीन जनसंपर्क में क्षमता संबंधी ऐसे निष्कर्ष सोडियम साइट्रेट पर लागू नहीं होते हैं जैसा कि भारतीय पाटनरोधी जांच में परिभाषित किया गया है। यह पीवीसी फ्लेक्स फिल्म पर दूसरे एसएसआर के मामले में सीईएसटीएटी के दृष्टिकोण के खिलाफ है, जिसमें यह कहा गया था कि एडीडी की समाप्ति पर डंपिंग और क्षति की निरंतरता की संभावना को सही ठहराने के लिए पर्याप्त और विश्वसनीय सबूत रिकॉर्ड पर रखने के लिए याचिकाकर्ता पर बोझ था।
- xi. जहां तक अप्रयुक्त क्षमताओं और निर्यात उन्मुखीकरण का संबंध है, प्राधिकारी ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया है कि प्रतिवादियों द्वारा किए गए ऐसे निर्यातों का बड़ा हिस्सा पेप्सिको और कोका कोला जैसी कंपनियों को हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं होती है।

- xii. यदि प्राधिकारी फिर भी शुल्क लगाना जारी रखने का निर्णय लेता है, तो मैसर्स शेडोंग एनसाइन इंडस्ट्री कं, लिमिटेड को एसएसआर जांच के विषय में निर्धारित मार्जिन के अनुसार शुल्क दरें प्रदान की जानी चाहिए। प्राधिकारी ने प्रथम एसएसआर में विषय वस्तुओं पर प्रतिभागी कंपनियों को नए माजन प्रदान किए हैं और प्राधिकारी ने चीन पीआर से ग्लास फाइबर और उसकी वस्तुओं, चीन पीआर से एल्यूमिनियम फॉयल जैसी पाटनरोधी जांचों में इसी प्रकार की पद्धति का अनुसरण किया है।

ठ.2 घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियां

130. घरेलू उद्योग द्वारा अपने पिछले प्रस्तुतियों को दोहराने के अलावा निम्नलिखित प्रकटीकरण पश्चात टिप्पणियां प्रस्तुत की गई हैं

- i. प्रकटन के अनुसार पीओआई के दौरान मैसर्स शेडोंग एनसाइन इंडस्ट्री कं, लिमिटेड के लिए नकारात्मक क्षति मार्जिन से उक्त निर्माता के लिए कोई शून्य शुल्क नहीं होना चाहिए क्योंकि वर्तमान जांच एक सनसेट समीक्षा जांच है। शेडोंग किसी भी मामले में पोस्ट पीओआई अवधि में सकारात्मक क्षति मार्जिन दिखाता है।
- ii. सनसेट समीक्षा के पीओआई के दौरान नकारात्मक क्षति माजन निर्यातक के लिए शून्य शुल्क निर्धारित करने का कोई आधार नहीं हो सकता है जैसा कि नई जांच में किया जाता है क्योंकि प्रकटन में ऐसे साक्ष्य हैं जो उक्त निर्यातक द्वारा और समग्र रूप से चीन पीआर से भी संबंधित वस्तुओं के निर्यात के मामले में डंपिंग और क्षति की संभावना दर्शाते हैं।
- iii. थाई ऐक्रेलिक फाइबर लिमिटेड बनाम पदनामित प्राधिकारी के मामले में माननीय सीईएसटीएटी द्वारा लिए गए विचार वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होते हैं। माननीय सीईएसटीएटी ने उक्त मामले में निम्नानुसार टिप्पणी की:

"14. सूर्यास्त की समीक्षा एक संभावना निधारण पर जोर देती है जिसमें डंपिंग का वर्तमान स्तर स्पष्ट रूप से इतना प्रासंगिक नहीं है जितना कि डंपिंग की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना है। इसके अलावा, जांच अवधि के दौरान, पाटनरोधी शुल्क लागू रहेगा और इसलिए डंपिंग का वर्तमान स्तर अस्तित्वहीन या न्यूनतम हो सकता है। जांच के अधीन निर्यातक भी इस अवधि के दौरान नॉन-डंप्ड मूल्य पर बिक्री कर सकते हैं, यह जानते हुए कि एक सनसेट समीक्षा प्रगति पर होगी। अतः धारा 9क (1) के अंतर्गत यह मानदंड कि पाटनरोधी शुल्क पाटन माजन से अधिक नहीं होना चाहिए, धारा 9क (5) के अंतर्गत शुल्क को जारी रखने के लिए व्यावहारिक अनुप्रयोग नहीं होगा। ऐसा करने के लिए उक्त धारा 9 ए (5) के तहत कानून में ऐसा कोई वारंट भी नहीं है।" (महत्व दिया)

- iv. मैसर्स शेडोंग एनसाइन इंडस्ट्री कं, लिमिटेड ने मूल जांच में सहयोग नहीं किया और न ही निर्यातक ने किसी भी नए शिपर की स्थिति के लिए दायर किया और जैसा कि यह खड़ा है, वर्तमान में शेडोंग पर लागू एडीडी अवशिष्ट शुल्क है और निर्यातक को अचानक इस एसएसआर में किसी भी व्यक्तिगत मार्जिन के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए।
- v. 2 एमएनसी ग्राहकों को आपूर्ति के कारण पीओआई के दौरान शेडोंग से निर्यात मूल्य स्पष्ट रूप से अधिक रहा है और यहां तक कि पीओआई के बाद की अवधि में भी ऐसी कीमतों में गिरावट आई है और एडीडी की अनुपस्थिति में अन्य उपयोगकर्ताओं को भी कम कीमतों पर विषय वस्तुओं की आपूर्ति करने से शेडोंग को कुछ भी नहीं रोकता है और न ही ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बेचा जाने वाला उत्पाद कोई अलग उत्पाद है।
- vi. शेडोंग ने समीक्षा के दौरान उच्च मूल्य दिखाने के लिए पीओआई के दौरान भारत को अपने निर्यात मूल्य का प्रबंधन किया क्योंकि आगामी सूर्यास्त समीक्षा निर्यातकों के ज्ञान में थी। शेडोंग के NCV-EQR से पता चलता है कि निर्यातक ने आधार वर्ष और POI के बीच भारत में केवल 27% की वृद्धि की और अन्य देशों के लिए, कीमतों में 16% की कमी आई। चीन जनसंपर्क के घरेलू बाजार में भी उक्त निर्यातक ने इसकी कीमत में 28 प्रतिशत की कमी की। इससे पता चलता है कि अकेले भारतीय बाजार में मूल्य वृद्धि बहुत संदिग्ध है और स्पष्ट रूप से वर्तमान समीक्षा के दौरान निर्यात मूल्य को प्रभावित करने के लिए उच्च मूल्य दिखाने के लिए किया गया है।

- vii. आयात आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि अप्रैल-2023 और फरवरी, 2024 के पहले सप्ताह के बीच शेडोंग की कीमत लगभग ₹98/किलोग्राम थी, फरवरी 2024 के दूसरे भाग और जुलाई 2024 तक उक्त निर्यातक की कीमत केवल ₹74/किलोग्राम है। इस प्रकार, पीओआई के बाद की अवधि में कीमत में पहले से ही 24% की गिरावट है और यह अकेले इस तथ्य को दर्शाता है कि पीओआई के लिए निर्यातक द्वारा स्पष्ट रूप से दावा की गई उच्च कीमत पूरी तरह से अविश्वसनीय है और इस तरह के बड़े हुए और अविश्वसनीय निर्यात मूल्य के आधार पर कोई व्यक्तिगत मार्जिन निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए।
- viii. जैसा कि खुलासा किया गया तथ्य पीओआई के बाद की अवधि के दौरान कीमत में गिरावट के अलावा शेडोंग के साथ उच्च निर्यात अभिविन्यास, अतिरिक्त क्षमता और उपलब्ध इन्वेंट्री को दर्शाता है। इस तरह के तथ्य मजबूत संभावना दिखाते हैं।
- ix. मैसर्स शेडोंग एनसाइन इंडस्ट्री कं, लिमिटेड को शून्य शुल्क, जब पीओआई के अंतिम भाग के लिए औसत स्तर पर इसकी कीमत पहले ही 24% तक गिर गई है और पीओआई अवधि के बाद इस मामले में एडीडी की कोई भी निरंतरता पूरी तरह से निरर्थक हो जाएगी और संपूर्ण भारतीय बाजार मैसर्स शेडोंग एनसाइन इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड को प्रदान किया जाएगा।
- x. मैसर्स जिआंगसु गुओक्सिन यूनियन एनर्जी कं, लिमिटेड, जिसे पहले व्यक्तिगत मार्जिन मिला था, पर एडीडी को जारी रखना आवश्यक है। तथ्य भी जिआंगसू के लिए उच्च निर्यात अभिविन्यास, अतिरिक्त क्षमता, उच्च इन्वेंट्री स्तर आदि दिखाते हैं।
- xi. प्रकटीकरण स्पष्ट रूप से भारतीय बाजार के आकर्षण और तीसरे देश के निर्यात की पर्याप्त मात्रा को दर्शाता है जो भारतीय बाजार की कीमतों से कम कीमतों पर किए जाते हैं। ऐसे कम कीमत वाले निर्यातों को वर्तमान शुल्कों की समाप्ति अथवा शून्य शुल्क के मामले में एक निर्यातक को तत्काल भारत भेज दिया जाएगा।
- xii. चीन पीआर में निर्यातकों की स्थिति वर्तमान शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में डंपिंग और क्षति की बहुत मजबूत संभावना दर्शाती है। चीन जनगण से विषयगत वस्तुओं के निर्यात के प्रति अन्य क्षेत्राधिकार में एडीडी/सीवीडी के साथ युग्मित देशव्यापी अतिरिक्त क्षमता और निर्यात अभिविन्यास के अलावा, प्रतिक्रिया देने वाले निर्यातकों के पास भी महत्वपूर्ण अप्रयुक्त क्षमता है और निर्यात अभिविन्यास 50% से अधिक है और ऐसे प्रतिक्रियात्मक निर्यातकों के मामले में भारतीय बाजार का आकर्षण 25-300% की रेंज में बहुत अधिक है।
- xiii. घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित एनआईपी पर कुछ पुनर्विचार की आवश्यकता है, विशेष रूप से इस तथ्य के लिए कि एनआईपी का निर्धारण करते समय कार्यशील पूंजी दावों से अधिकांश राशि को अस्वीकार कर दिया गया है। दावा के अनुसार कार्यशील पूंजी के बहुमत की अस्वीकृति ने एनआईपी को काफी कम कर दिया है जो वर्तमान मामले के समग्र तथ्यों में उचित नहीं है। अन्य खर्चों की भी अनुमति नहीं है जिन पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।
- xiv. प्राधिकारी पीयूसी, जैसे अनुच्छेद और घरेलू उद्योग के संबंध में प्रकटीकरण विवरण में लिए गए विचारों की पुष्टि कर सकता है और इस मामले में अंतिम निष्कर्ष जारी करते समय खड़ा हो सकता है। तथ्य स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि आवेदक के पास नियम 2 (बी) के तहत आवश्यक स्थिति है।
- xv. विचाराधीन उत्पाद का भारत को संबंधित देश से पाटित कीमतों पर निर्यात जारी है और जैसा कि प्रकट किया गया है, तथ्यों से पता चलता है कि वर्तमान शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में ऐसी पाटन जारी रहेगी।
- xvi. मात्रा और मूल्य पैरामीटरों दोनों के संदर्भ में घरेलू उद्योग को क्षति बहुत स्पष्ट है और प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि इस मामले में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। कीमतों में कमी है और यह भी स्पष्ट है कि 2 एमएनसी पेय निर्माताओं के अलावा अन्य आयातकों द्वारा आयात के मामले में भी कीमतों में कमी सकारात्मक रही है।

- xvii. इस प्रकार की पाटन और परिणामी क्षति के विषय देश से तीव्र होने की संभावना है और मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति होने की संभावना है।
- xviii. डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं अथवा अंतिम अंतिम-प्रयोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्कों के विस्तार पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है और एडीडी को जारी रखना उत्पादकों, डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं और आम जनता के सर्वोत्तम हित में होगा। भारतीय उत्पादक भारत की पूरी मांग को पूरा कर सकते हैं और देश उत्पाद के लिए आत्मनिर्भर है। भारत में उत्पाद के लिए मांग और आपूर्ति में कोई अंतर नहीं है।
- xix. सहायक उत्पादकों ने पहले प्रस्तुत अपने विचारों को भी दोहराया और चीन पीआर से विषय वस्तुओं पर एंटी-डंपिंग शुल्क जारी रखने का अनुरोध किया।

ठ.3. प्राधिकारी द्वारा समीक्षा

131. प्राधिकारी नोट करता है कि इच्छुक पाटयों द्वारा प्रकटीकरण पश्चात टिप्पणियां/प्रस्तुतीकरण अधिकांशतः उनके पहले के निवेदनों की पुनरावृत्ति हैं, जिनकी पहले ही उपयुक्त रूप से और पर्याप्त रूप से जांच की जा चुकी है और वर्तमान निष्कर्ष के संगत पैरा में प्रकटीकरण विवरण में समुचित रूप से और समुचित रूप से संबोधित किया जा चुका है। प्राधिकारी इच्छुक पार्टियों द्वारा उठाए गए नई टिप्पणियों/ मुद्दों के संबंध में आगे निम्नानुसार विचार करता है:
- i. इस तर्क के संबंध में कि यदि प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्कों की परवाह किए बिना जारी रखने का निर्णय लेता है, तो प्राधिकारी घरेलू उद्योग के लिए परिकल्पित एनआईपी को पुनः सत्यापित कर सकता है जो प्रथम एसएसआर की तुलना में चार्ट से बहुत दूर प्रतीत होता है, प्राधिकारी नोट करता है कि एनआईपी का निर्धारण प्रत्येक जांच के तथ्यों में सीमा शुल्क टैरिफ (पहचान, (ii) पाटित वस्तुओं पर पाटित पाटनरोधी शुल्क का मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए (2005) नियमावली, 1995।
 - ii. इस तर्क के संबंध में कि अन्य भारतीय उत्पादकों ने क्षति के आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं, प्राधिकारी नोट करता है कि घरेलू उद्योग के रूप में आवेदक की पात्रता का निर्धारण एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 2 (बी) के अनुसार किया जाता है और घरेलू उद्योग को नुकसान का निर्धारण एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 11 के अनुलग्नक II में निहित सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यह निर्धारित करने के बाद कि आवेदक "घरेलू उद्योग" की आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसके बाद आवश्यकता "घरेलू उद्योग" से संबंधित क्षति का निर्धारण करना है जो वर्तमान जांच में किया गया है।
 - iii. इस तर्क के संबंध में कि याचिकाकर्ता ने आज तक अपने किसी भी समर्थक के समर्थन पत्र का उचित एनसीवी प्रदान नहीं किया है, प्राधिकारी नोट करता है कि समर्थन पत्र अन्य 3 सहायक उत्पादकों द्वारा स्थिति के निर्धारण के संदर्भ में प्रदान किए गए हैं और ऐसे पत्रों के अनुसार उत्पादन के विवरण पर प्राधिकारी द्वारा कुल भारतीय उत्पादन की गणना के लिए विचार किया गया है। यह आगे ध्यान दिया गया है कि प्रकटीकरण में कुल भारतीय उत्पादन में याचिकाकर्ता और अन्य पार्टियों की हिस्सेदारी पर पर्याप्त सारांशित जानकारी थी और यह भी ध्यान दिया गया है कि इस तरह के विवरण आवेदन में भी प्रदान किए गए हैं।
 - iv. इस तर्क के संबंध में कि प्रकटीकरण से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को क्षति नहीं लगी है और वह विभिन्न मापदंडों के आधार पर अनुकूल परिणाम प्रदर्शित कर रहा है, जिसे क्षति या निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना को समाप्त करने से पहले प्राधिकारी द्वारा विधिवत विचार किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करता है कि इस निष्कर्ष में लिए गए अंतिम विचार डंपिंग और घरेलू उद्योग को परिणामी नुकसान पर विरोधी पक्षों की टिप्पणियों को संबोधित करते हैं।

- v. इस तर्क के संबंध में कि जबकि प्राधिकारी ने कुछ निवेशों को बाहर रखा है जो नियोजित पूंजी की गणना के उद्देश्य से पूरी तरह से निर्यात प्रदर्शन से संबंधित हैं, और शेष एनएफए को निर्यात और घरेलू बिक्री के बीच तार्किक तरीके से आवंटित किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करता है कि जैसा कि प्रकटीकरण के समय दर्ज किया गया था, घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई पूंजी की विस्तृत जांच की गई है और नियोजित पूंजी पर विचार किया गया है एनआईपी गणना का उद्देश्य नियमों के अनुलग्नक III की आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है।
- vi. इस तर्क के संबंध में कि एनआईपी की गणना वर्तमान जांच में अनुचित रूप से अधिक रही है, जो याचिकाकर्ता द्वारा एनएफए की भ्रामक रिपोर्टिंग और केवल घरेलू बिक्री के लिए पूरे एनएफए को आवंटित करने के कारण हो सकती है, प्राधिकारी नोट करता है कि विवाद में कोई योग्यता नहीं है क्योंकि एनआईपी एडी नियमों के अनुलग्नक-III के अनुसार निर्धारित किया गया है, (ग) प्राधिकारी की सतत प्रथाओं में संशोधन किया गया है।
- vii. इस तर्क के संबंध में कि प्राधिकारी द्वारा 22% कर-पूर्व ROI प्रदान करने की प्रथा न केवल मनमानी है, बल्कि अत्यधिक भी है, प्राधिकारी ने नोट किया कि नियोजित पूंजी पर 22% का रिटर्न प्राधिकारी की सुसंगत प्रथा के अनुसार सभी मामलों में लागू होता है, जिसमें विषयगत उत्पाद के आयातों से संबंधित मूल और प्रथम सनसेट समीक्षा शामिल है।
- viii. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत प्रगतिशील उदारीकरण के सिद्धांत के अनुसार यह अपेक्षित है कि पाटनरोधी शुल्क केवल तब तक लागू रहें जब तक हानिकारक पाटन का प्रतिकार करने के लिए आवश्यक हो, प्राधिकारी नोट करता है कि इस अंतिम निष्कर्ष में निकाले गए निष्कर्ष ऐसे मुद्दों पर स्वतः व्याख्यात्मक हैं और मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों को और जारी रखने की आवश्यकता की व्याख्या करते हैं।
- ix. इस तर्क के संबंध में कि जबकि प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला है कि आयात में वृद्धि की प्रवृत्ति है, और यह विचार नहीं करके गलती की है कि उन आयातों का 60% से अधिक उन विशिष्ट संस्थाओं को है जो एनआईपी में खरीद रहे हैं, प्राधिकारी नोट करता है कि भारत में संबंधित वस्तुओं के आयात की प्रवृत्ति की जांच के उद्देश्य से, भारत में संबंधित वस्तुओं का कुल आयात प्रासंगिक है और ऐसे आयातों से क्षति माजन को पीओआई के दौरान सकारात्मक के रूप में नोट किया जाता है।
- x. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि प्राधिकारी ने यह स्वीकार किया है कि ईयू और यूएसए द्वारा जांच का दायरा व्यापक है और इसने निर्यातकों पर यह दिखाने की जिम्मेदारी डालने में गलती की है कि चीन पीआर में क्षमता पर ऐसे निष्कर्ष सोडियम साइट्रेट पर लागू नहीं होते हैं जैसा कि भारतीय पाटनरोधी जांच में परिभाषित किया गया है, प्राधिकारी नोट करता है कि निर्यातकों पर कोई दायित्व डालने की टिप्पणी सही नहीं है। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि निर्यातकों ने ऐसी आपत्तियों के आधार को प्रमाणित किए बिना ईयू/यूएसए द्वारा निष्कर्षों में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने पर आपत्ति की है जिसमें संबंधित वस्तुएं शामिल हैं। यह भी नोट किया जाता है कि इस तरह के निष्कर्षों पर विचार करने से संबंधित वस्तुओं सहित उत्पादों के सबसे संकीर्ण समूह या श्रेणी से संबंधित जानकारी तक पहुंच सक्षम होती है, जो नियमों के अनुलग्नक II के पैरा (vi) के आलोक में अनुमेय है जो एंटी-डंपिंग समझौते के अनुच्छेद 3.6 के अनुरूप है।
- xi. इस तर्क के संबंध में कि प्रतिवादियों द्वारा निर्यात का बड़ा हिस्सा पेप्सिको और कोका कोला जैसी संस्थाओं को है जो घरेलू उद्योग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, प्राधिकारी नोट करता है कि भारत में संबंधित वस्तुओं के कुल आयातों के आधार पर डंपिंग और क्षति की जांच की गई है और परिणामों पर इस निष्कर्ष में उपयुक्त स्थानों पर चर्चा की गई है जो विरोधी पक्षों की टिप्पणियों का समर्थन नहीं करता है यहाँ।
- xii. इस तर्क के संबंध में कि यदि प्राधिकारी फिर भी शुल्क लगाना जारी रखने का निर्णय लेता है, तो मैसर्स शेडोंग एनसाइन इंडस्ट्री कं, लिमिटेड को एसएसआर जांच के विषय में निर्धारित मार्जिन के अनुसार शुल्क दरों से

सम्मानित किया जाना चाहिए, यह नोट किया जाता है कि दावे को इस निष्कर्ष में उपयुक्त अनुभाग में संबोधित किया गया है।

- xiii. जहां तक एनआईपी के निर्धारण के संबंध में घरेलू उद्योग के तर्कों का संबंध है, टिप्पणियों की उचित जांच के बाद यह नोट किया गया है कि एनआईपी निर्धारण में कोई संशोधन आवश्यक नहीं है क्योंकि एनआईपी का खुलासा सीमा शुल्क टैरिफ (डंप की गई वस्तुओं पर एंटी-डंपिंग शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रह और क्षति के निर्धारण के लिए) नियमों के अनुलग्नक- III के अनुसार निर्धारित किया गया है। (ग) प्राधिकारी ने 1995 में और प्राधिकारी की सतत प्रथा के अनुसार 1995 में एक मामला दर्ज किया है। इस तरह के निर्धारण पर पुनर्विचार करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई नया तथ्य नहीं लाया गया है।

ड. निष्कर्ष

132. उठाए गए तर्कों, इच्छुक पक्षों द्वारा प्रदान की गई जानकारी और प्रस्तुतियों और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि उपरोक्त निष्कर्षों में दर्ज किया गया है, और घरेलू उद्योग को डंपिंग और क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी निम्नानुसार निष्कर्ष निकालता है:

क. विचाराधीन उत्पाद "सोडियम साइट्रेट" है जो चीन पीआर से उत्पन्न या निर्यात किया जाता है। यह एक रासायनिक यौगिक है जो मोनोसोडियम साइट्रेट, डिसोडियम साइट्रेट और ट्राई-सोडियम साइट्रेट के रूप में आता है। विचाराधीन उत्पाद का लेन-देन निम्नलिखित वैकल्पिक नामों से भी किया जा सकता है:- क. सोडियम साइट्रेट ख. ट्राई सोडियम साइट्रेट ग. ट्राई सोडियम साइट्रेट डाइहाइड्रेट घ. सोडियम साइट्रेट डाइहाइड्रेट ड. ट्राइबेसिक सोडियम साइट्रेट च. सोडियम साइट्रेट ट्राइबासिक डाइहाइड्रेट छ. सोडियम साइट्रेट डिबासिक सेसक्विहाइड्रेट ज. सोडियम साइट्रेट मोनोबैसिक बायोक्स्ट्रा।

ख. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद चीन से आयातित उत्पाद के लिए वस्तु की तरह है।

ग. आवेदक अर्थात् मैसर्स डैफोडिल फार्माकिम प्राइवेट लिमिटेड नियम 2 (बी) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग का गठन करता है। इसके अलावा, एंटी-डंपिंग ड्यूटी के विस्तार के अनुरोध को तीन अन्य उत्पादकों अर्थात् मैसर्स इंडिया फॉस्फेट, मैसर्स सुनील केमिकल्स और मैसर्स वांग फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल्स द्वारा समर्थित किया गया था।

घ. आवेदन में सूर्यास्त समीक्षा की शुरुआत के उद्देश्य से प्रासंगिक सभी जानकारी शामिल थी। इसके अलावा, आवेदक ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक और आवश्यक समझी जाने वाली सभी जानकारी प्रदान की।

ड. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर संबंधित वस्तुओं के लिए सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन माजन निर्धारित किया गया है। विषय देश से विषयगत वस्तुओं के निर्यात के लिए निर्धारित डंपिंग माजन न्यूनतम स्तर से ऊपर बना हुआ है।

च. पाटित आयातों की मात्रा में निरपेक्ष रूप से और खपत के संबंध में वृद्धि हुई है।

छ. कुल आयात से कम कीमत नकारात्मक के रूप में नोट की जाती है। हालांकि, यह नोट किया गया है कि पेप्सिको इंडिया और कोका कोला इंडिया के अलावा अन्य पार्टियों द्वारा किए गए आयात के मामले में मूल्य अंडरकटिंग सकारात्मक रही है।

ज. जबकि घरेलू उद्योग के विभिन्न वॉल्यूम मापदंडों में क्षति की अवधि में सुधार हुआ, बेस वर्ष और वर्ष 2021-22 के बीच कुछ सकारात्मक वृद्धि के बाद POI के दौरान कीमत पैरामीटर में गिरावट जारी रही। इसके अलावा, हालांकि वॉल्यूम मापदंडों के संदर्भ में समग्र सकारात्मकता रही है, घरेलू उद्योग के इन्वेंट्री स्तर में पीओआई के दौरान काफी वृद्धि हुई है। यह भी नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है जबकि इसी अवधि के दौरान पाटित आयातों की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है।

- झ. संबंधित देश से पाटित आयातों की मात्रा और मूल्य प्रभाव और घरेलू उद्योग पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करने के बाद यह नोट किया गया है कि जांच की वर्तमान अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।
- ज. एंटी-डंपिंग शुल्क की समाप्ति की स्थिति में डंपिंग और क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना है, जैसा कि निम्नलिखित कारकों द्वारा स्थापित किया गया है;
- i. पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद संबंधित वस्तुओं की पाटन जारी है।
 - ii. आयात की मात्रा भी महत्वपूर्ण बनी हुई है और वास्तव में पूर्ण और खपत के सापेक्ष बढ़ी है।
 - iii. विषय आयातों की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है।
 - iv. चीन पीआर में संबंधित वस्तुओं के लिए महत्वपूर्ण अधिशेष क्षमताएं मौजूद हैं, और अधिशेष अप्रयुक्त क्षमताएं भारतीय घरेलू मांग से कहीं अधिक हैं। प्रतिक्रिया देने वाले निर्यातकों के मामले में भी ऐसी अतिरिक्त क्षमता स्पष्ट है।
 - v. संबंधित देश में प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों के पास पर्याप्त मात्रा में माल मौजूद है।
 - vi. विषय देश के उत्पादक न केवल भारत में पाटन कर रहे हैं बल्कि अनुबन्ध वस्तुओं का निर्यात भी कर रहे हैं जो उत्तर देने वाले निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य और गैर-हानिकारक मूल्य की तुलना में पाटित और हानिकारक मूल्यों पर तीसरे देशों को निर्यात कर रहे हैं।
 - vii. चीन पीआर के उत्पादकों के लिए भारत एक आकर्षक आकर्षक बाजार है।
 - viii. विषयगत वस्तुओं के निर्यात पर दूसरी सनसेट समीक्षा के बाद ईयू में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाते हैं और ऐसे निर्यातों पर दूसरी सनसेट समीक्षा के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में पाटनरोधी और प्रतिकारी शुल्क भी लगाए जाते हैं। जैसा कि उल्लेख किया गया है, अतिरिक्त क्षमता के साथ-साथ अन्य देशों में व्यापार बाधाओं से वर्तमान शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में डंप की गई कीमतों पर निर्यात बढ़ने की संभावना है।
- ट. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में इस बात की पूरी संभावना है कि चीन जनसंरक्षक से संबंधित वस्तुओं के आयात पाटित और हानिकारक मूल्यों पर बढ़ेंगे।
- ठ. जांच में ऐसा कोई विचार प्रकाश में नहीं आया था जिससे यह पता चले कि पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना जनहित में नहीं होगा। जैसा कि उल्लेख किया गया है, भारत में उत्पाद की पूरी मांग को पूरा करने की क्षमता है और चीन जनगण से संबंधित वस्तुओं के आयात पर अकेले मौजूदा एंटी-डंपिंग शुल्क जारी रखने की सिफारिश की जा रही है।
133. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में पाटन जारी रहने या इसकी पुनरावृत्ति होने तथा इसके परिणामस्वरूप क्षति होने की स्पष्ट संभावना है, और इसलिए प्राधिकारी चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्कों को पांच वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए जारी रखने की सिफारिश करते हैं।
- ढ. सिफारिशें
134. प्राधिकारी नोट करता है कि जांच शुरू की गई थी और सभी इच्छुक पक्षों को अधिसूचित किया गया था और घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों, उपयोगकर्ताओं और अन्य इच्छुक पक्षों को डंपिंग, क्षति और कारण लिंक के पहलुओं और घरेलू उद्योग को डंपिंग और क्षति की संभावना के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था।

135. इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त करने की अनुमति दी जाती है तो पाटन और क्षति की संभावना का सकारात्मक साक्ष्य है, प्राधिकारी का विचार है कि संबंधित देश से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर लागू पाटनरोधी शुल्क को आगे जारी रखा जाना अपेक्षित है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर स्थापित किया गया है, नामित प्राधिकारी संबंधित देश से संबंधित वस्तुओं के आयात पर मौजूदा एंटी-डंपिंग शुल्क को जारी रखने की सिफारिश करना उचित समझता है। तदनुसार, चीन जन गण के उत्पादकों के लिए पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश नीचे दी गई शुल्क सारणी के अनुसार की जाती है।
136. यह निर्धारित करने के बाद कि वर्तमान मामले में डंपिंग और क्षति की संभावना है यदि मौजूदा एंटी-डंपिंग शुल्क वापस ले लिया जाता है, तो वर्तमान जांच के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए शुल्कों की वर्तमान मात्रा में किसी भी संशोधन के बिना चीन पीआर से संबंधित वस्तुओं के आयात पर मौजूदा एंटी-डंपिंग शुल्क को जारी रखना उचित समझा जाता है। तथापि, प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि मैसर्स शेडोंग एनसाइन इंडस्ट्री कं लि. नामक एक निर्यातक ने वर्तमान सनसेट समीक्षा जांच में भाग लिया है जिसने मूल जांच अथवा प्रथम सूर्यास्त समीक्षा के समय भाग नहीं लिया था। निर्यातक ने वर्तमान सनसेट समीक्षा के दौरान सहयोग किया है और निर्यातक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों को डेस्क सत्यापन के माध्यम से प्राधिकारी द्वारा सत्यापित भी किया गया था। प्राधिकारी ने उक्त निर्यातक के निर्यातों की मात्रा और मूल्य की जांच की है और यह नोट किया गया है कि निर्यात की मात्रा और मूल्य प्रतिनिधि मूलक प्रकृति के हैं। ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों में, प्राधिकारी मैसर्स शेडोंग एनसाइन इंडस्ट्री कं, लिमिटेड के लिए व्यक्तिगत एंटी-डंपिंग शुल्क दर निर्धारित करना उचित समझता है। हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान जांच में मौजूदा एंटी-डंपिंग ड्यूटी की समाप्ति की स्थिति में डंपिंग और क्षति लगने की संभावना है, उक्त उत्पादक/निर्यातक के लिए एंटी-डंपिंग ड्यूटी की मात्रा पूरी तरह से डंपिंग के मार्जिन के बराबर एंटी-डंपिंग ड्यूटी के सिद्धांत के आधार पर निर्धारित नहीं की जा सकती है या नियम 4 (1) (डी) (आई) के तहत प्रदान की गई नई जांच की तरह कम है। चीन जनगण से विषयगत वस्तुओं के आयात पर लागू वर्तमान पाटनरोधी शुल्क में पाटनरोधी शुल्क शामिल है जिसका निर्धारण प्राधिकारी द्वारा सहयोगी उत्पादकों/निर्यातक जिन्होंने प्रथम सूर्यास्त समीक्षा जांच में भाग लिया था और गैर-सहकारी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए लागू शुल्क भी शामिल हैं। चूंकि वर्तमान सनसेट समीक्षा में संबंधित देश से संबंधित वस्तुओं के आयातों पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की जा रही है, प्राधिकारी सहयोगी निर्यातक के लिए मैसर्स शेडोंग एनसाइन इंडस्ट्री कं लि. के लिए भी लागू मौजूदा पाटनरोधी शुल्क दर की सिफारिश करना उचित समझता है।
137. इस प्रकार, एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 23 (1 बी) और नियम 23 (3) के साथ पठित नियम 17 (1) (बी) में निहित प्रावधान के संदर्भ में, प्राधिकारी मौजूदा एंटी-डंपिंग शुल्क को जारी रखने की सिफारिश करता है, ताकि घरेलू उद्योग को डंपिंग और क्षति की संभावना को दूर किया जा सके। तदनुसार, नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम (vii) में उल्लिखित राशि के बराबर निश्चित एंटी-डंपिंग शुल्क केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच (5) वर्षों के लिए लगाने की सिफारिश की जाती है, जो संबंधित देश में उत्पन्न या निर्यात की जाने वाली संबंधित वस्तुओं के सभी आयातों पर है।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	एच एस कोड	माल का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	निर्माता	शुल्क (\$/एमटी)
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
1.	29181520#	सोडियम साइट्रेट*	चीन पीआर	चीन पीआर सहित कोई भी देश	मेसर्स शेडोंग एनसाइन इंडस्ट्री कं, लिमिटेड	96.05
2.	- वही-	- वही-	चीन पीआर	चीन पीआर सहित कोई भी देश	मेसर्स जिआंगसु गुओक्सिन यूनियन एनर्जी कं, लिमिटेड	96.05
3.	- वही-	- वही-	चीन पीआर	चीन पीआर सहित कोई भी देश	क्रम संख्या 1 और 2 के अलावा कोई अन्य निर्माता	152.78
4.	- वही-	- वही-	चीन पीआर के अलावा कोई भी देश	चीन पीआर	कोई	152.78

- सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

* - उपरोक्त शुल्क तालिका में माल के विवरण में निम्नलिखित वैकल्पिक नाम भी शामिल हैं: - (क). ट्राई सोडियम साइट्रेट; (ख). ट्राई सोडियम साइट्रेट डाइहाइड्रेट; (ग). सोडियम साइट्रेट डाइहाइड्रेट (घ). ट्राइबासिक सोडियम साइट्रेट; (ङ). सोडियम साइट्रेट ट्राइबासिक डाइहाइड्रेट; (च). सोडियम साइट्रेट डिबासिक सेसक्विहाइड्रेट; (छ). सोडियम साइट्रेट मोनोबैसिक बायोएक्स्ट्रा।

138. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए आयातों का अवतरण मूल्य सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमाशुल्क द्वारा यथा निर्धारित कर निर्धारण योग्य मूल्य होगा और समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 8ख, 9, 9क के अंतर्गत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर लागू सीमा शुल्क होगा।

ण. आगे की प्रक्रिया

139. इस अंतिम निष्कर्ष से उत्पन्न पदनामित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील की जाएगी।

दर्पण जैन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 12th February, 2025

Case No. AD (SSR) - 02/2024

Subject: Second Sunset Review anti-dumping investigation concerning anti-dumping duties on imports of “Sodium Citrate” originating in or exported from China PR – reg.

F. No. 7/08/2024-DGTR—Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (“AD Rules”).

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. **M/s Daffodil Pharmachem Private Limited** (hereinafter referred to as the “applicant”), has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) seeking initiation of second sunset review investigation and the continuation of extant anti-dumping duties on imports of Sodium Citrate (hereinafter referred to as the “subject goods”, or “the product under consideration”), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the “subject country”).
2. The original anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from China PR was initiated by the Authority on 28.02.2014 *vide* Notification No. 14/23/2013-DGAD. The final finding in the original investigation was issued by the Authority on 26.02.2015 recommending imposition of definitive anti-dumping duties on the imports of the subject goods originating in or exported from China PR. The aforesaid recommendation was accepted by the Central Government *vide* Notification No. 19/2015-Customs (ADD) dated 20.05.2015 and final anti-dumping duties were imposed on the subject goods originating in or exported from China PR.
3. The Authority initiated the first sunset review investigation *vide* Notification No. 7/21/2019-DGTR dated 25.10.2019. By way of its final findings dated 30.04.2020, the Authority recommended continuation of the anti-dumping duties as modified on imports of the subject goods from China PR for another period of 5 years which was subsequently accepted by the Central Government and duties were continued *vide* Notification No. 8/2020-Customs (ADD) dated 19.05.2020 for a period of 5 years. The duties as extended with effect from 19.05.2020 for a period of 5 years are valid till 18th May, 2025.
4. On the basis of the duly substantiated application by the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of *prima facie* evidence submitted by the applicant substantiating the likelihood of dumping and consequent injury to the domestic industry, and in accordance with Rule 23(1B) of the Rules, the Authority initiated the investigation *vide* Notification No. 7/08/2024-DGTR on 30th September, 2024 to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country, and to examine whether the expiry of existing anti-dumping duty is likely to lead continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

5. The procedure described herein below has been followed with regard to the subject investigation:
 - a. The Authority notified the embassy of the subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the AD Rules.
 - b. The Authority issued a public notice dated 30th September, 2024 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the second sunset review anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject country into India.

- c. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 30th September, 2024, to the embassy of the subject country in India, the known producers and exporters from the subject country, known importers, importer/user, associations, the domestic industry, other known Indian producers and any other interested parties, as per the addresses/ emails made available by the applicant. The interested parties were advised to provide relevant information in the form and manner prescribed and make their submissions known in writing within the prescribed time-limit, in accordance with Rules 6(2) and 6(4) of the Rules.
- d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Government of the subject country, through its embassy in India in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules.
- e. The embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.
- f. The Authority sent questionnaires to the following known producers/exporters in the subject country in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:
 - i. M/s AHA International Co. Ltd.
 - ii. M/s COGNIS Ltd.
 - iii. M/s Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd.
 - iv. M/s Shandong Ensign Industry Co., Ltd.
 - v. M/s Shanghai Nuvit Bio-Tech Co. Ltd.
- g. In response, the following exporters/producers from the subject country filed Exporter's Questionnaire Response, Exporters Questionnaire - Part II and also Economic Interest Questionnaire:
 - i. M/s Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd.
 - ii. M/s Shandong Ensign Industry Co., Ltd.
- h. The producers/exporters from the subject country who have not submitted the questionnaire response or have not cooperated in the investigation have been treated as non-cooperative in the investigation.
- i. The Authority sent the Importer's Questionnaire to the following known importers/users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rule.
 - i. M/s Aimchem Ingredients Pvt Ltd.
 - ii. M/s COCA-COLA India Pvt Ltd.
 - iii. M/s Gopal Enterprises
 - iv. M/s Ishita Drugs Industries Ltd.
 - v. M/s Kiara Ingredients INC
 - vi. M/s NDC Drug Chemical Company Pvt Ltd.
 - vii. M/s P D Navkar Bio-Chem Pvt Ltd.
 - viii. M/s PepsiCo India Holdings Pvt Ltd.
 - ix. M/s Prakash Chemicals Agencies Pvt. Ltd.
 - x. M/s Ratanchand Sons
- j. In response, none of the importers/users have responded within the stipulated time and filed any Importers/Users Questionnaire Response.
- k. Apart from the above noted foreign producers/exporters, M/s Wang Pharmaceuticals & Chemicals on 5th December, 2024 expressed support to the present investigation claiming to be producer of subject goods in India. However, no injury information has been submitted by the said producer.
- l. The Authority issued the Economic Interest Questionnaire (EIQ) to all interested parties and the concerned line Ministry/ Department. Response to EIQ was submitted by the domestic industry and responding exporters. None of the users or importers filed any EIQ.

- m. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR website along with the request to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties along with the investigation team.
- n. A request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the transaction-wise details of imports of the subject goods for the past three years, and the period of investigation, which was received by the Authority. The Directorate General of Systems & Data Management (DG Systems) was also requested to provide transaction-wise details of the imports of the subject goods for the injury period and the same was also received by the Authority. The information so received have been compared with the summary information published by DGCI&S as claimed by the applicant and no difference was noted. Hence, the Authority has relied upon the import information as published by DGCI&S for computation of the volume and value of imports of subject goods into India for the purposes of this notification.
- o. The Non-Injurious Price (NIP) has been determined based on the cost of production and the cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure-III to the Anti-Dumping Rules so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- p. The period of investigation (POI) adopted by the Authority for the present investigation is 1st April 2023 to 31st March, 2024 (12 months). The injury investigation period covers the periods 1st April 2020 to 31st March 2021, 1st April 2021 to 31st March 2022, 1st April 2022 to 31st March 2023 and the POI.
- q. Verification/ desk verification of the information provided by the applicant, responding producers and exporters from the subject country to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority. Only such verified information with necessary modification/ rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of present notification.
- r. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority also provided the opportunity to all interested parties to present their views orally in the oral hearing held in the hybrid mode on 8th January, 2025. All the parties who had attended the oral hearing were provided an opportunity to file written submissions by 13th January, 2025 followed by rejoinders, if any by 16th January, 2025. The interested parties were further directed to share the non-confidential version of the written submission submitted by them with the other interested parties and the list of interested parties has been communicated to all the parties by the Authority.
- s. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation so far, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered and addressed by the Authority, in this notification.
- t. Information provided by the interested parties on the confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- u. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the views/observations on the basis of the facts available.
- v. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties in the present final findings, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation.
- w. In accordance with Rule 16 of Rules *Supra*, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties *vide* disclosure statement dated 27th January, 2025 and the interested parties were

originally allowed time up to 3rd February, 2025 to comment on the same. Some of the interested parties sought further extension of time and on consideration of such requests, the time line to comment on the Disclosure statement was extended up to 6th February, 2025 till 2 PM. The comments to disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant and non-repetitive, in this final finding notification.

- x. ‘***’ in this final findings represents information furnished by an interested party on the confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- y. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US\$1 = ₹83.69.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1. Submissions by the other interested parties

- 6. The other interested parties have made the following submissions with respect to the product under consideration (PUC):
 - i. The product involved in the investigation produced and sold by the respondent is Sodium Citrate. The specification range includes 20-100 meshes and 12-40 meshes; the package type includes 25kg/bag, 500kg/bag and 1,000kg/bag. The product can be used as food additive, detergent and industrial uses.
 - ii. There is no difference in physical/ technical/ chemical characteristics between PUC exported to India and PUC sold in the domestic market or exported to other countries.
 - iii. There is no difference between the product produced by the Respondent and the product defined by the Authority.

C.2. Submissions of the domestic industry

- 7. The domestic industry has submitted as follows with regard to the product under consideration (PUC) and like article:
 - i. The PUC in the second Sunset Review (SSR) application is “Sodium Citrate”.
 - ii. Sodium Citrate is a chemical compound that comes in the form of mono-sodium citrate, disodium citrate and tri-sodium citrate. Sodium Citrate is the sodium salt of citric acid. Like citric acid, it has a sour taste. Like other salts, it also has a salty taste.
 - iii. Sodium Citrate is mainly used as an expectorant and a urine alkalinizer. It is also used as a pharmaceutical aid and as a food additive in dairy industries which cater to cheese manufacturing and beverages. It is also a water treatment chemical and a laboratory reagent.
 - iv. Sodium Citrate has been transacted in the following names and all such names must be please considered as part of the definition of PUC as has been done in the previous investigations:
 - a) Sodium Citrate
 - b) Tri Sodium Citrate
 - c) Tri Sodium Citrate dihydrate
 - d) Sodium Citrate dihydrate
 - e) Tribasic Sodium Citrate
 - f) Sodium Citrate Tribasic Dihydrate
 - g) Sodium Citrate Dibasic Sesquihydrate
 - h) Sodium Citrate Monobasic Bioextra
 - v. The PUC may be described differently based on applications. Based on applications, it can be industrial, food ingredients, pharma grade (IP/BP/USP), reagent, fish grade. The present petition covers all forms, all types and all possible descriptions of sodium citrate. Further, it includes all alternate names of sodium citrate.

- vi. The PUC is imported under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975, under customs sub-heading 29181520. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the PUC since the import of the product in other headings also cannot be ruled out fully.
- vii. There is no known difference in the PUC exported from China PR and that produced by the Indian industry. In the present case, both products are comparable in terms of technical characteristics, similar end uses, technical and commercial substitutability, and tariff classification. The two are technically and commercially substitutable.
- viii. Since the present application is for the second sunset review of existing ADD on imports of Sodium Citrate from China PR, it is important that the Authority may consider the scope of PUC and Like Article as has been found in the previously concluded first sunset review following the original investigation.

C.3. Examination by the Authority

- 8. The PUC in the present investigation is “Sodium Citrate” originating in or exported from China PR.
- 9. The present investigation being a second sunset review investigation, the scope of the PUC remains the same as that in the first sunset review. The PUC in the first sunset review was defined as under:

10. The PUC in the present investigation is Sodium Citrate. The subject goods are mainly used as an expectorant and a urine alkalinizer. Sodium Citrate is a chemical compound that comes in the form of mono-sodium citrate, disodium citrate and tri-sodium citrate.

11. The subject goods fall under customs sub-heading 29181520. However, the said customs classifications are only indicative, and not binding on the scope of the investigations. The description of goods shall prevail for the imposition and collection of duties.

12. This being a sunset review investigation, the scope of the PUC remains the same as that in the original and subsequent review investigation. The PUC as mentioned in the original investigation was:

“The product under consideration for the purpose of present investigation is “Sodium Citrate”. It’s a chemical compound that comes in the form of monosodium citrate, disodium citrate and tri-sodium citrate. It is sodium salt of citric acid and has a sour and salty taste. Sodium Citrate is mainly used in pharma industries as an expectorant and urine alkalinizer. It is also used as a pharmaceutical aid, food additive in dairy industries, laboratory reagent in water treatment, acidity regulator in drinks, an emulsifier for oils when making cheese and an antioxidant in food, etc.

The product under consideration can also be transacted by the following alternate names: - a. Sodium Citrate b. Tri Sodium Citrate c. Tri Sodium Citrate dihydrate d. Sodium Citrate dihydrate e. Tribasic Sodium Citrate f. Sodium Citrate Tribasic Dihydrate g. Sodium Citrate Dibasic Sesquihydrate h. Sodium Citrate Monobasic Bioextra.

Sodium Citrate is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act under customs subheading 29181520. The customs classification is however indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.”

13. Rule 2(d) relating to the definition of "like article" specifies that "like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation, or in the absence of such an article, another article having characteristics closely resembling those of the article under investigation.

14. From the above definition of the term "like article", it is noted that the like article has to be identical or alike in all respects to the article under investigation. The scope of the term like article shall also

include those articles having closely resembling characteristics to those under investigation in the absence of articles identical or alike in all respects.

15. On the basis of information on record, the Authority holds that there is no known difference in the subject goods produced by the Domestic Industry and those imported from the subject country. The two are comparable in terms of physical characteristics, manufacturing process, functions and uses, product specifications, distribution and marketing, and tariff classifications of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers also use the two interchangeably. The Authority holds that the product manufactured by the Applicant constitutes like article to the subject goods being imported into India from the subject country.

10. With regard to like article, Rule 2(d) of the Anti-Dumping Rules provides as under:

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation.

11. From the above definition of the term "like article", it is noted that the like article has to be identical or alike in all respects to the article under investigation. The scope of the term like article shall also include those articles having closely resembling characteristics to those under investigation in the absence of articles identical or alike in all respects.
12. There is no dispute regarding likeness between the article produced by the domestic industry and the PUC. The Authority notes that the PUC produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The goods produced by the domestic industry and that imported from the subject country are like articles in terms of the Rules. The two are technically and commercially substitutable. Thus, the Authority holds that the subject goods produced by the domestic industry are like article to the PUC imported from the subject country within the scope and meaning of Rule 2(d) of Anti-dumping Rules.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1. SUBMISSION OF THE OTHER INTERESTED PARTIES

13. The submissions on the aspect of the domestic industry and the standing as filed by other interested parties are as follows:
- i. Non-participation of other producers must be investigated by the Authority.
 - ii. There are close to a dozen producers of the PUC in India and since the initiation of the original investigation on the PUC, number of supporters have been reducing consistently (from four in the 1st SSR to merely two in the current SSR, as per the petition).
 - iii. Non-participation by other producers raises serious doubts on the profitability and performance of other non-participating producers. It appears that all other producers are showing improved metrics and no signs of injury and as a result, those have deliberately been kept aside by the petitioner to present a skewed image of the domestic industry.

D.2. Submissions made by the domestic industry

14. The submissions made by the domestic industry with regard to scope of the domestic industry and standing are as follows:
- i. M/s Daffodil Pharmachem Private Limited is the applicant and largest producer of Sodium Citrate in India and holds a major proportion in total Indian production to the tune of 45-50%. Applicant had been domestic industry in the original investigation and also in the first sunset review and the applicant is not related to any importer/exporter of the subject goods, nor have imported the subject goods themselves. Thus, the applicant constitutes domestic industry for all practical purposes in this matter.

- ii. Apart from the applicant two producers namely M/s India Phosphate, M/s Sunil Chemicals supported the application. Another producer namely M/s Wang Pharmaceuticals & Chemicals supported the application post initiation. The Authority must treat M/s Wang Pharmaceuticals & Chemicals also as the supporter in this matter. Applicant along with M/s India Phosphate, M/s Sunil Chemicals holds 60-65% share in the Indian production and with M/s Wang Pharmaceuticals & Chemicals, the share is 65-70%.
- iii. India had 6 producers at the time of original investigation which has been 11 during the 1st SSR and in the present review. While the 1st SSR had the petitioner holding 32% share in total Indian production and 61% share along with the supporters, the present application has 45-50% share in total Indian production held by the applicant alone and the share of the applicant along with the supporters is in the range of 65-70% (60-65% without M/s Wang Pharmaceuticals & Chemicals). Thus, the application now represents a higher volume of Indian production and the support has not gone down as alleged by the exporters in terms of thresholds which alone is relevant while looking at the representative nature of the application.
- iv. As of now India has 11 producers and out of such producers, the applicant is the largest producer with 45-50% share in total Indian production. Producer is an MSME unit. The details of the applicant and supporters in the previous investigation and the present application is provided herein below:

Table - 1

Sl. No.	Name of the producer	Status
Original Investigation		
1	M/s Posy Pharmachem Private Limited (<i>Currently M/s Daffodil Pharmachem Private Limited</i>)	Applicant
2	M/s Sunil Chemicals	Supporter
3	M/s Amijal Chemicals (<i>created capacity as per information</i>)	Neutral
4	M/s Sujata Chemicals (<i>created capacity as per information</i>)	Neutral
5	M/s Vasa Pharmachem Pvt. Ltd. (<i>created capacity as per information</i>)	Neutral
6	M/s Adani Pharmachem Private Ltd. (<i>created capacity as per information</i>)	Neutral
1st SSR investigation		
1	M/s Posy Pharmachem Private Limited (<i>Currently M/s Daffodil Pharmachem Private Limited</i>) (32% share in Indian production)	Applicant
2	M/s Adani Pharmachem Pvt. Ltd.	Supporter
3	M/s Alpine Labs	Supporter
4	M/s India Phosphate	Supporter
5	M/s Sunil Chemicals	Supporter
6	M/s Amijal Chemicals	Neutral
7	M/s Sujata Chemicals	Neutral
8	M/s Vasa Pharmachem Pvt. Ltd.	Neutral
9	M/s Devendra Kirti Pharmachem Pvt. Ltd.	Neutral
10	M/s Wang Pharmaceuticals & Chemicals	Neutral
11	M/s Ishita Drugs & Industries Ltd	Neutral
2nd SSR Application (Current Investigation)		
1	M/s Daffodil Pharmachem Private Limited – (<i>Formerly M/s Posy Pharmachem Private Limited</i>) (45-50% share in Indian production)	Applicant
2	M/s India Phosphate	Supporter
3	M/s Sunil Chemicals	Supporter
4	M/s Wang Pharmaceuticals & Chemicals (<i>Supported investigation after the initiation of the investigation</i>)	Supporter
5	M/s Adani Pharmachem Pvt. Ltd.	Neutral
6	M/s Alpine Labs,	Neutral
7	M/s Amijal Chemicals	Neutral
8	M/s Sujata Chemicals	Neutral
9	M/s Vasa Pharmachem Pvt. Ltd.	Neutral
10	M/s Devendra Kirti Pharmachem Pvt. Ltd.	Neutral
11	M/s Ishita Drugs & Industries Ltd	Neutral

- v. Practically, the largest producer is the applicant and three other largest producers are supporting the application. The parties who have not expressed support are either very small producers or subject goods is only a small share of their total production. Thus, the domestic industry of Sodium Citrate in India is well represented in this matter.

- vi. Efforts were made to get injury information from supporting producers also. However, the difficulty has been that the supporters, who are small units and are into production of other chemicals also, could not prepare the injury data as required by the anti-dumping application formats for the subject goods. The units do not have the support system to maintain and present such comprehensive and technical data as desired and such challenges of the units should not be construed as less participation in the petition.
- vii. The challenges from the dumped imports faced by the applicant and other producers are similar and the performance of the applicant is representative of the actual situation of such other producers also.

D.3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

15. Rule 2 (b) of the AD rules defines the “domestic industry” as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers.”

16. The application for initiation of second sunset review and continuation of anti-dumping duties existing on subject goods from China PR has been filed by M/s Daffodil Pharmachem Private Limited. It is noted that the applicant did not import the subject goods from the subject country during the period of investigation/ injury period and is also not related to any of the exporters/importers of the subject product from the subject country.
17. Further, information in the application shows that there are 10 other producers of subject goods in India apart from the applicant and the applicant holds ***% (Range: 45-50%) share in total Indian production. Out of such 10 other producers, two producers namely M/s India Phosphate and M/s Sunil Chemicals have supported the application prior to the initiation and another producer namely M/s Wang Pharmaceuticals & Chemicals supported the investigation *vide* its letter dated 05.12.2024. The applicant along with M/s India Phosphate and M/s Sunil Chemicals holds ***% (Range: 60-65%) share in total Indian production which is ***% (Range: 65-70%) along with support from M/s Wang Pharmaceuticals & Chemicals.
18. Apart from the applicant and supporters as above, the applicant has identified companies namely M/s Adani Pharmachem Pvt. Ltd., M/s Alpine Labs, M/s Amijal Chemicals, M/s. Sujata Chemicals M/s Vasa Pharmachem Pvt. Ltd., M/s Devendra Kirti Pharmachem Pvt. Ltd. and M/s Ishita Drugs & Industries Ltd. as producers of subject goods in India, but such producers have neither supported nor opposed the present investigation.
19. Therefore, considering the information on record, the Authority holds the applicant/ petitioner as eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules.
20. With regard to the contention of other interested parties that non-participation of other producers must be investigated by the Authority and number of supporters have been reducing consistently, the Authority notes that all such known other producers were intimated about the initiation of the present investigation but there has been no response from such other parties. It is also noted that the eligibility conditions under Rule 2(b) needs to be examined and satisfied in the context of an investigation in hand and not in comparison to support or opposition to any other concluded investigation in the past as put forth by the opposing parties. As far as the facts of the present investigation is concerned, the application fulfills the criteria of Rule 2(b). Applicant alone holds *** % (Range: 45-50%) share in total Indian production and the share is *** % (Range: 65-70%) along with supporters.
21. With regard to the contention that non-participation by other producers raises serious doubts on the profitability and performance of other non-participating producers, the Authority notes that though the exporters have raised such contentions, no evidences has been submitted to support such contentions. The injury information considered in the present investigation pertains to the “domestic industry” as required under the Anti-dumping Rules and the doubts raised by the other interested parties cannot be considered as they are not supported by any facts to the contrary.

E. ISSUES ON CONFIDENTIALITY**E.1. Submissions made by other interested parties**

22. The following submissions have been made by other interested parties with regard to confidentiality issues:

- i. Annexure I of Trade Notice No. 10/2018 dated 7th September, 2018 provides a specific standard of disclosures for the supporters. However, the petitioner has failed to comply with the requirements of the Trade Notice.
- ii. In Annexure 2.3 of the petition, the support letters filed do not contain the indexed numbers for capacity, production and sales. This is in clear contravention of the Authority's Trade Notice. The domestic industry has also not shown any good cause for such excessive confidentiality.

E.2. Submissions made by the domestic industry

23. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality issues:

- i. The responding exporters have adopted excessive confidentiality in EQR and Part II Response and indexation also have been provided at limited places making it difficult to understand the claims of the exporters in any fair manner.
- ii. No indexation or range is provided concerning information which is relevant in the evaluation of likelihood aspects and such excessive use of confidentiality must not be permitted.
- iii. Even basic information such as world-wide corporate structure chart, List of Related Companies, Exports Flowchart to India and Domestic Flowchart is held confidential without any cogent reason.
- iv. The Authority may check whether the export chain is complete in case of the responding exporters since the basic information in this regard is not disclosed in the NCV version of responses.

E.3. Examination by the Authority

24. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provides as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

25. As required under Rule 6(7), the Authority made available the evidence presented to it by one interested party to the other interested parties, participating in the investigation. Such information was circulated among the participating interested parties with directions to exchange such evidences among the interested parties participating in the investigation.
26. The information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regards to sufficiency of such claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties.

Wherever possible, the parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

27. With regard to the contention that the applicant has not provided information pertaining to the supporting producers in the indexed form, it is noted that the non-confidential version of the application contains the share of applicant in total Indian production of subject goods along with the supporters.

F. MARKET ECONOMY TREATMENT (MET), NORMAL VALUE, EXPORT PRICE & DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

F.1. SUBMISSION OF OTHER INTERESTED PARTIES

28. The following submissions have been made by the other interested parties concerning determination of normal value, export price and dumping margin:
- i. The Petitioner has suggested two methods for computation of the constructed normal value (CNV) using either the cost of production (COP) of the petitioner or using its export prices to third country being USA in this case. In accordance with the consistent practice of the Authority in all the investigations and also in the past two investigations of the PUC, the Authority must determine the CNV using the COP data of the petitioner.
 - ii. The Authority may verify the raw material prices considered by the petitioner in CNV calculation to ensure that there remains no error in the data.
 - iii. As the responding exporters in this investigation have filed the questionnaire response within the timelines, the same be considered for determination of the net export price (NEP).

F.2. SUBMISSIONS MADE BY THE DOMESTIC INDUSTRY

29. The following submissions have been made by the domestic industry:
- i. China PR should be treated as a non-market economy (NME) country for the purpose of present petition and normal value in case of Chinese producers should be determined as per the provisions of Annexure I Para 7.
 - ii. The Authority may consider the price of the subject goods in the USA on the basis of the export price of the subject goods from India to the USA at landed levels in the USA as the normal value for the subject goods concerning China PR.
 - iii. As an alternative to the normal value claimed based on price in the USA, the applicant proposes normal value based on the price actually paid or payable in India, duly adjusted to include a reasonable profit margin.
 - iv. Volume and value of import of subject goods be determined as per the information from DGCI&S which forms the basis of export price also in the petition.
 - v. The information as provided in the petition clearly shows that dumping of the subject goods continued and the dumping as claimed has been significantly positive during the POI. Such dumping during the POI when the ADD is in force signifies the fact the such dumping will only continue if the ADD is allowed to expire at this juncture.
 - vi. Dumping margin during the POI establishes likely dumping also in the event of expiry of present duties.
 - vii. It has been contended by the opposing parties during the hearing that the rate of caustic soda considered ₹73.43/- per KG as per the NCV of application which appears wrong. It is clarified in this regard that the rate actually considered for working of CNV is ₹43.22/- per KG only which was disclosed in the working documents along with the NCV application.

- viii. There are two exporters who have filed responses in this matter. However, the parties have not rebutted the presumption of non-market economy status of China PR by submitting the applicable response.
- ix. One of the responding producers/exporters namely M/s Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd. is subjected to individual duty already and there is a need for continuation of such duties on the said producer instead of any price undertaking offer in view of likelihood of dumping and injury in this matter. In fact, M/s Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd. attracts an ADD of 32.6% in export of subject goods to EU which shows the said producer is not only dumping in India but engaged in dumping in other territories also and any expiry or reduction of ADD on such exporters shall only lead to increased dumped exports from such exporter.
- x. Also, the responding exporters must be directed to provide the following information specifically if not provided already so as to enable the Authority to conduct likelihood examination:
- Capacity to produce the subject goods during POI and post POI (April - September 2024 preferably).
 - Capacity utilisation of subject goods during POI and post POI (April - September 2024 preferably).
 - Inventory level of subject goods during POI and post POI (April - September 2024 preferably).
 - Export price to third countries on transaction to transaction (T/T) basis for subject goods during POI and post POI (April - September 2024 preferably).
 - Export price to India on T/T basis for subject goods during post POI (April - September 2024 preferably).
- xi. With regard to the basis of normal value for China PR, the applicant claimed normal value based on export price of subject goods from India to USA at landed levels in USA as the normal value in a market economy third country. Alternatively, normal value based on constructed basis by considering international price of key raw materials (Price of Citric Acid and Caustic Soda as per DGCI&S import price) also been submitted. The Authority may consider such claims for the determination of normal value and it is not shown by any opposing parties that the normal value based on export price from India to USA is not an appropriate basis in this matter.
- xii. It is a settled practice that likelihood of dumping and injury needs to be seen *qua* the subject country and not *qua* the responding exporters alone. Thus, even if the responding exporters show absence of likelihood of dumping and injury concerning their exports, a country wide determination of likelihood alone is relevant. In any case, the responding exporters have not shown absence of likelihood of dumping and injury and the response is deficient in terms of relevant information essential to determine likelihood concerning exports of subject goods from China PR to India.
- xiii. The responding exporters have left the information sought on following crucial aspects in the EQR (Attachment III to the EQR) relevant for likelihood analysis blank by stating such information is not applicable to the responding parties:
- Country's production
 - Other producer sales in domestic market
 - Total sales in domestic market
 - Imports in your country
 - Total demand in your country
 - Other producers' exports to India
 - Other producer's exports to countries other than India
- xiv. Since the responding exporters have failed to submit any evidence to refute the claims of likelihood raised by the applicant, it is requested that likelihood examination in the present matter be based on information submitted in the application.
- xv. Also, the responding exporter namely M/s Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd. claimed that they have exported the subject goods at a higher rate hinting at negative margins in their exports. However, negative margin in the POI is not a factor to determine the continuation or not of ADD and what is relevant is examination of likelihood. Thus, as long as there is likelihood of dumping and injury from exports of subject goods to India, the ADD on responding producer namely M/s Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd. is also liable to be continued. Such is the view taken by the Authority in the past also and SSR concerning Clear Float Glass is a glaring example wherein ADD were continued while the exporter having positive dumping margin and negative injury margin during the POI.

- xvi. Likelihood of dumping and injury is the determining factor even in case of individual responding exporters and any negative dumping or injury margin does not entitle them for any nil duty as evident in the Rule and also past practices of the Authority.

F.3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

NORMAL VALUE

30. Under Section 9A (1)(c), normal value in relation to an article means:

(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under subsection (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

Market economy status for producers from China PR

31. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows: "Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

(a) "In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following Rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

- (c) *The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*
- (d) *Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."*
32. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a) (ii) have expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/ data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status.
33. At the stage of initiation, the Authority proceeded by constructing the normal value as per the information furnished by the applicant based on the cost of production of subject goods in India with due addition of selling, general and administrative expenses and profits. Upon initiation, the Authority advised the producers/exporters in China PR to respond to the notice of initiation and provide information relevant to determination of their market economy status. The Authority sent copies of the supplementary questionnaire to all the known producers/exporters for rebutting presumption of non-market economy in accordance with criteria laid down in Para 8(3) of Annexure-I to the Rules and furnishing relevant detailed information. The Authority also requested the Government of China PR to advise the producers/exporters in China PR to provide the relevant information.
34. None of the exporters/producers from China PR contested the NME presumption of China PR. Thus, in view of the above position and in the absence of rebuttal of the non-market economy presumption by any exporting company from China PR, the Authority considers it appropriate to treat China PR as a non-market economy country in the present investigation and proceed with para 7 of Annexure-I to the Rules for determination of normal value in case of China PR.
35. Accordingly, the normal value for all the producers/exporters from China PR have been determined as given below.

Normal value for all producers in China PR

36. Annexure I of the Rules which reads as under:

In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Account shall also be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

37. Para 7 of Annexure – I lays down a hierarchy for determination of normal value and provides that normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other country, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin.
38. At the time of initiation, interested parties were advised to comment on the proposal made by the applicant to consider normal value for China PR based on price in a market economy third country and price in USA has been claimed based on export price of subject goods from India to USA at landed levels in USA. The claims have not

been substantiated further by the applicant nor there are any substantive comments on such proposal made by the exporters other than a request to reject such proposal. In the absence of any further information in this regard from any of the interested parties, determination of normal value on such basis is not considered.

39. Since there is no substantiated claim on record with regard to the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India made by any of the interested parties including the applicant, normal value could not be determined on any of such basis. Therefore, the Authority has constructed normal value for the subject goods from China PR as price actually payable in India as stipulated in para 7 of Annexure – I to the Anti-dumping Rules, duly adjusted. It has been computed based on the cost of production of the domestic industry, with reasonable addition for selling, general and administrative expenses, and profits. The constructed normal value so determined is given below in the dumping margin table.

Determination of export price for cooperating producers and exporters

i. Export price

a) M/s Shandong Ensign Industry Co., Ltd.

40. From the exporters' questionnaire response of M/s Shandong Ensign Industry Co., Ltd. who is the producer cum exporter of the subject goods, it is noted that during the POI the Company has exported *** MT of subject goods to India. The Authority has verified the data through desk verification and other supporting documents. The producer/exporter has claimed adjustments on account of ocean freight, marine insurance, inland freight, port expenses and credit cost, and the same have been allowed. Accordingly, the export price determined is provided in the dumping margin Table.

b) M/s Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd.

41. From the exporters' questionnaire response of M/s Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd. who is the producer cum exporter of the subject goods, it is noted that during the POI the Company has exported *** MT of subject goods to India. The Authority has verified the data through desk verification and other supporting documents. The producer/exporter has claimed adjustments on account of ocean freight, marine insurance, inland freight, port expenses, and the same have been allowed. Credit cost was not claimed by the exporter and the same has been calculated based on the other cooperating exporter. Accordingly, the export price determined is provided in the dumping margin Table.

Determination of normal value and export price for all non-cooperating producers and exporters in China PR

42. The normal value and export price for other non-cooperating exporters from China PR has been determined as per facts available and the same is mentioned in the dumping margin table.

Dumping margin

43. Considering the normal value and export price for the subject goods, the dumping margins for the subject goods from the subject country have been determined as follows:

Table - 2
Dumping Margin Table

Sl. No.	Country	Producer	Normal Value US\$/MT	Net Export Price US\$/MT	Dumping Margin		
					US\$/MT	(%)	(Range %)
1.	China PR	M/s Shandong Ensign Industry Co., Ltd.	***	***	***	***	10-20
2.	China PR	M/s Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd.	***	***	***	***	65-75
3.	China PR	Any other producer	***	***	***	***	90-100

G. INJURY ASSESSMENT AND EXAMINATION OF CAUSAL LINK

G.1. SUBMISSIONS MADE BY OTHER INTERESTED PARTIES

44. The submissions made by the other interested parties have been as follows:
- i. The application has been filed based on the facts that there is continuing injury. However, it can be seen that there is no injury currently faced by the domestic industry. Consequently, the basis of filing the application is itself bad and the investigation must be terminated.
 - ii. Increase in total imports must be seen in light of massive increase in domestic demand and petitioner's production and sales growth.
 - iii. If the subject imports were actually causing or threatening to cause any injury, there is no explanation as to how the production and sale of PUC has increased during the injury period.
 - iv. Price undercutting for imports from China PR is negative. This means that the price at which the petitioner is making sales is lower than the landed price of imports. This establishes that injury caused to petitioner is due to reasons other than dumped imports.
 - v. The petitioner has been able to increase/ maintain the selling prices when there has been increase in cost of sales. Further, there cannot be a case for price depression since there was a continuous increase in the selling price of the domestic industry. Therefore, there is no case made for the existence of price suppression or depression in the present investigation.
 - vi. The domestic industry has enjoyed a sharp increase in its capacity utilisation, production and sales. There has been an increase in capacity utilisation of more than 150% as compared to the base year. Production and sales have also increased.
 - vii. The domestic industry has faced no injury in terms of the number of employees. As the number of employees has increased during the injury period, the loss in productivity can be clearly attributed to internal inefficiencies due to rapid expansion in production activities.
 - viii. The inventory of the petitioner appears to have increased during the injury period. While the opening inventory has been increasing during the injury investigation period (IIP), the closing inventory has not been increasing to such an extent.
 - ix. The inventory *qua* the production and sales are declining which also explains that this is not related to dumping or imports.
 - x. It appears that the negative profitability is due to other factors such as internal inefficiencies, etc.
 - xi. The export performance of the industry consistently improved throughout the IIP. The petitioner is highly focused on the export market and is not able to concentrate sufficiently on the domestic front.
 - xii. The return on capital employed has been negatively affected due to the reduction in profitability of the petitioner. The reduction in profitability is attributable to the slump in export performance and the high depreciation.
 - xiii. The interest cost has decreased from 100 indexed points to 23 basis points in the POI, the average capital employed has increased from 100 to 791 indexed points. The petitioner attributed this increase in the average

capital employed to additional compliance costs due to stringent regulatory quality checks. However, the claims must be validated by the Authority, and more importantly, it must be ensured that the compliance costs pertaining solely to the domestic market have been considered.

- xiv. The Authority must disallow any amounts that have been incurred in view of export sales market. It appears that the applicant has increased the average capital employed by including all costs to eventually enhance the determination of NIP artificially.
- xv. It can be verified from the petition itself that the landed value as well as the sales price of the petitioner itself are moving in tandem with the cost of the raw materials. The decline in selling price is not a function of imports.
- xvi. In order to make a determination of injury to the domestic industry, the overall state of the domestic industry must be examined. The decision of the WTO panel in Thailand – H-Beams (WT/DS/122/R) is relevant. Reliance was also placed on the Council Implementing Regulation (EU) No. 135/2014 of 11th February, 2014 concerning imports of Dicyandiamide from China PR to suggest that in the present case also, the performance of the petitioner has improved during the injury period. The injury, if any, is due to factors other than the imports. Applying the above decision to the present case, it is clear that there is no likelihood of injury.
- xvii. The overall state of the domestic industry is healthy. All economic parameters, operational and financial, are improving. Therefore, there is no continuance of dumping or injury that the domestic industry can be said to be suffering due to the imports requiring continuation of the ADD.

G.2. SUBMISSIONS MADE BY THE DOMESTIC INDUSTRY

- 45. The following submissions have been made by the domestic industry:
 - i. Application shows current dumping and injury which must be considered as a predominant factor bolstering our claims of likelihood of dumping and injury in the event of expiry of existing ADD and there are other factors also apart from current dumping and injury which shows very strong likelihood of dumping and injury in the present matter in the event of expiry of existing ADD.
 - ii. The domestic industry suffered losses and the losses suffered by it is the direct fall out of unfair competition from landed price of imports from China PR at cost undercutting levels and the situation would have been even grave in the absence of present ADD.
 - iii. Imports from China PR have increased in absolute terms between the base year and the POI. Imports which were 1,137 MT in the base year increased to 2,025 MT showing an increase in absolute terms.
 - iv. Dumped imports in relation to production has declined between the POI and the base year which is in line with the increase in production of the domestic industry over the injury period as a positive effect of the ADD in force concerning this parameter. However, the domestic industry was left with significant unutilized capacity during the POI.
 - v. Dumped imports increased between base year and the POI in relation to demand. This shows imports is persisting in Indian market and continues to grow with the growth in demand for the product in India. Such preference for dumped imports will only increase in the event of expiry of present duties.
 - vi. The share of dumped imports in Indian demand increased when the Indian producers have adequate capacity to meet the entire Indian demand. Significant share of dumped material even when India is self-reliant on the product shows the probability that such share will increase significantly leading to aggravated injuries to the domestic industry should the ADD in force expire.
 - vii. ADD on import of subject goods from China PR came into force on 20th May, 2015. Import information since such levy and till the current POI shows that the dumped imports have been very persistent in nature in the Indian market even when ADD measures are in force. Imports has been as follows:

Table - 3

Year	Sodium Citrate Import from China PR (Value in MT)
2015-16	843
2016-17	1,168
2017-18	975
2018-19	736
2019-20	960
2020-21	1,137
2021-22	1,418
2022-23	2,123
2023-24	2,025
April-Sept. 2024 (Annualised)	966

- viii. Market share of dumped imports from China PR has increased by the POI in comparison to the base year and has been at very significant level in absolute terms throughout the injury period.
- ix. Market share of dumped imports has been more than 10% post the base year and in the POI which must be noted as a significant share to distort the market equations.
- x. Market share of other countries has declined between base year and the POI and have been at very low levels in terms of market share. Such other imports were also at higher prices and evidently, imports from China PR are preferred for its dumped prices.
- xi. While market share in Indian demand that of the dumped imports increased by the POI, the market share in demand that of the domestic industry declined in the same period. The decline in market share was about 1.70% in absolute terms which is a fall of about 7% and must be noted as substantial loss of market share.
- xii. Though the market share of other Indian producers increased between POI and the base year, the benefit of significant growth in demand did not go fully to other Indian producers either. While the growth in demand between base year and the POI was about 66%, the growth in market share of other producers have been only 6%.
- xiii. Petition shows capacity available with the domestic industry remained unchanged over the years. However, the capacity available with the applicant alone is sufficient to meet 85-95% of the Indian demand and the country has capacity to the tune of 30,000-35,000 MT against a demand of 19,000-20,000 MT.
- xiv. Capacity utilisation of the domestic industry increased by the POI, even though the capacity was unutilized at significant level in the range of 30-40% during the POI.
- xv. Growth in domestic sales between the POI and immediate previous year have been very meagre at 2% whereas the Indian demand grew at 17% during the same period. Such meagre growth in sales is the result of a 2% fall in market share of the domestic industry to the dumped imports in the same period.
- xvi. Production and capacity utilisation of the domestic industry increased but as a result of positive growth in exports and the growth in production and capacity utilisation also would have been meagre had there been no growth in exports undertaken by the domestic industry.
- xvii. There has been a substantial increase in inventory level of the domestic industry though there was an increase in capacity utilisation and production. This signifies the fact the increase in production could not be fully converted into sales and the inventory build-up could have been avoided in the absence of dumped imports.
- xviii. The situation of volume parameters shows that the ADD have been instrumental in providing some impetus to the volume performance and it is also clear that the volume performance is highly vulnerable to any increase in dumped imports in the event of expiry of present duties.
- xix. The level of employment slightly increased by the POI in line with the increase in production. The domestic industry could have employed more people had there been no underutilisation of capacity.

- xx. Domestic industry is committed to increase wages and salaries timely as required under the laws of the land and there have been some increases in overall wages over the years. However, the wages per unit of production did not increase any significantly and it cannot be said the injury claimed is on account of any wage increases.
- xxi. There has been significant improvement in productivity per employee and the numbers have been robust showing very efficient use of work force of the domestic industry. Hence, any deterioration in productivity is not the cause of injury to the domestic industry.
- xxii. The profitability of the domestic industry which was positive in terms of PBIT and PBDIT in the initial two years of the injury period once again turned significantly negative during the POI. Losses on such parameters is evident during the immediate previous year to the POI also. Even PBT was positive during the year 2021-22 which also turned significantly negative during the POI and immediate previous year.
- xxiii. The domestic industry has been able to better its efficiency by reducing the interest cost etc. significantly by the POI, however, the price realized during the POI has been unremunerative and the domestic industry could not even recover its cost since the dumped imports undermined such efforts. Thus, the domestic industry has been once again in losses during the POI and such losses has been on account of presence of dumped imports at a rate even lower than the cost of sales of the domestic industry.
- xxiv. The cash profits were positive during the initial two years of the injury period and even such cash profits turned significantly negative during the POI. As a result of unfair price competition from dumped imports, the domestic industry could not operate at profitable levels which is reflected in the cash profit situation also.
- xxv. Return on investment (ROI) has been positive during the initial two years of the injury period which turned significantly negative during the POI and during the immediate previous year. A situation of negative return on investment is a serious concern of the domestic industry that too when the product has shown some robust increase in demand and negative ROI in such a situation questions the purpose of existence itself of the domestic industry.
- xxvi. While the market share of domestic industry and inventory level has grown negatively during the POI though some other volume parameters such as production, capacity utilisation and sales showed positive trend. However, all the price parameters such as selling price, profits, cash profits and ROI have shown significant negative growth. The situation would have been even grave had there been no ADD and the situation also shows continuation of ADD is very essential in this matter to ensure growth of the domestic industry.
- xxvii. The domestic industry is still grappling to achieve reasonable levels of return on the investments that has been already made by it. Dumped imports continues to be a dampener on realizing any prudent level of return on such investments already made and raising any further capital to significantly expand the capacity etc. will depend on the continuation of level playing field in the Indian market.
- xxviii. The domestic industry had to make further and substantial investments in the existing facility during 2022-23 and 2023-24 especially to revamp the facility with most modern infrastructure and newer additions in the plant and machinery so as to adopt best manufacturing practices in the facility in line with the Schedule M Notification dated 28th December, 2023.
- xxix. The landed price of imports from China PR sharply declined during the POI in comparison to immediate previous year though the price undercutting has been negative during the POI. The real price effect must be seen in the fact that the landed price of imports from China PR prevented the price increases which otherwise would have occurred, to a significant degree and the landed price of imports have been below the cost of production of the domestic industry.
- xxx. Negative price undercutting during the POI is immaterial for the reason that the landed price of imports has been below the cost of production of the domestic industry and the domestic industry was forced to sell at a price lower than its cost.
- xxxi. It is a settled principle that negative price undercutting does not mean absence of injury nor price undercutting is the lone parameter to measure price injury. In plethora of cases, the Authority found injury even when the price undercutting has been negative (Matter like TDI, PTA, etc., are examples).

- xxxii. Price underselling from dumped imports is very significant as provided in the application. Dumped imports below the cost of production and fair price (NIP) of the applicant must be noted as a key factor showing continued injury to the domestic industry.
- xxxiii. Though the cost of production of the domestic industry, selling price and also landed price of imports declined during the POI in comparison to the immediate previous year, the landed price of imports remained significantly lower than the cost of sales of the domestic industry. This shows the price of the domestic industry has been suppressed in the market in the hands of landed price of dumped imports.
- xxxiv. The exporters reduced the price of subject goods at a rate much higher than the drop in major raw material price i.e., Citric Acid during the POI. The unexplained extra drop in price to the tune of 29% is one of the facts which demonstrates the element of dumping in the export pricing strategy being followed by the producers of subject goods from China PR.
- xxxv. The above discussions show the fact that the domestic industry continued to suffer injury in terms of financial losses and below par performance in terms of volume parameters and the growth was also negative in terms of such key injury parameters. The injury would have been higher on the above parameters in the absence of present ADD.

G.3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

- 46. Rule 11 of the AD Rules, 1995 read with Annexure II to the AD Rules, 1995 provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...*”. Further, in considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
- 47. Rule 23 of the Rules provides that the provisions of Rule 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19 and 20 shall apply *mutatis mutandis* in case of a review. In case the performance of the domestic industry shows that it has not suffered injury during the current injury period, the Authority shall determine whether cessation of the present duty is likely to lead to recurrence of injury to the domestic industry.
- 48. The submissions made by the domestic industry and other interested parties during the course of investigation with regard to injury and causal link considered relevant by the Authority are examined and addressed below under the relevant parameters.
- 49. With regard to the contention that the increase in average capital employed claimed to be on account of compliance cost must be validated and the compliance costs pertaining solely to the domestic market needs to be considered for NIP, the Authority has subjected the claims of the applicant in view of the contentions of the exporters to detailed verification. It has been explained by the domestic industry during the verification along with supporting documents that investments were made in the existing facility and capitalized during 2022-23 and 2023-24 to make the production facility compatible with the new Schedule M in the Drug Rule, 1945 as proposed in the year 2018. The Company took its investment decision based on expert recommendation and the new schedule M, which covers good manufacturing practices and requirements of premises, plant and equipment for pharmaceutical products, has been notified and implemented by the Ministry of Health & Family Welfare under Government of India on 28th December, 2023 *vide* Notification No. G.S.R. 922(E). Thus, the domestic industry could upgrade its plant with the help of planned capex by the time the new schedule M was implemented by the nodal Ministry. It is noted that the capex has been for production as a whole and not for exports alone as contended. Nevertheless, certain investments applicable primarily for exports have been identified and excluded while computing the capital employed wherever applicable.
- 50. With regard to the contention on injury concerning various injury parameters, the Authority notes that it is not necessary that all parameters of injury show deterioration. Some parameters may show deterioration, while some others may not. The Authority considers all injury parameters for assessing the financial parameters of the domestic industry. The Authority has examined the injury parameters objectively considering the facts and arguments submitted by the domestic industry and the other interested parties.

i. Volume effect of dumped imports on the domestic industry

a. Assessment of demand/ apparent consumption

51. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the PUC in India as the sum of domestic sales of the domestic industry and other Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below:

Table - 4

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Imports from China PR (Subject Country)	MT	1,137	1,418	2,123	2,025
Trend	Indexed	100	125	187	178
Imports from Other Countries	MT	585	309	252	384
Trend	Indexed	100	53	43	66
Total Imports into the Country	MT	1,722	1,727	2,375	2,409
Trend	Indexed	100	100	138	140
Domestic Sales of Petitioner	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	73	152	154
Domestic Sales of Supporters	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	146	127	150
Domestic Sales of Other Producers	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	172	201
Demand	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	110	149	166

52. It is seen that the demand for the product increased significantly between the base year and the POI by 66%.

b. Import volumes from subject country

53. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of the injury analysis, the Authority has relied upon the import as per DGCI&S. The import volumes of the subject goods and share of the same in total imports into India during the injury investigation period are as follows:

Table - 5

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Total Imports into the Country	MT	1,722	1,727	2,375	2,409
Imports from China PR (Subject Country)	MT	1,137	1,418	2,123	2,025
Imports from Other Countries	MT	585	309	252	384
Share of Subject Country in total Imports	%	66	82	89	84
Share of Other Countries in total imports	%	34	18	11	16
Total	%	100	100	100	100

54. It is seen that dumped imports of the subject goods from the subject country has increased from 1,137 MT in the base year to 2,025 MT in the POI showing an increase in imports in absolute terms. In terms of percentage, the share of dumped imports from subject country in overall imports into India which was 66% in the base year increased to 84% in the POI while the share of imports from other countries decreased from 34% in the base year to 16% by the POI. Above information also shows subject country continues to be the main source of imports of Sodium Citrate into India.

c. Subject country imports in relative terms

Table - 6

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
-------------	------	---------	---------	---------	-----

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Imports from China PR (Subject Country)	MT	1,137	1,418	2,123	2,025
Demand	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	110	149	166
Production of the domestic industry	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	144	191	265
Imports from subject country relative to Indian consumption	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	113	125	107
Imports from subject county relative to production of domestic industry	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	71	98	67

55. It is noted that the share of dumped imports in relative terms to consumption has increased by 7% between the POI and the base year. However, dumped imports in relation to production in India has declined between the POI and the base year by 33% which in line with the increase in production of the domestic industry in the same period.

ii. Price effect of the imports on the domestic industry

56. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject country has been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realisation (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with landed price of imports of the subject goods from the subject country.

a) Price undercutting

57. For the purpose of price undercutting analysis, the net selling price of the domestic industry has been compared with the landed value of imports from the subject country. While computing the net selling price of the domestic industry all taxes, rebates, discounts and commissions have been deducted and sales realisation at ex works level has been determined for comparison with the landed value of the dumped imports. Accordingly, the undercutting effects of the dumped imports from the subject country works out as follows:

Table - 7

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Net Sales Realization	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	300	188	118
Landed Price (LV)	₹/MT	57,319	96,155	1,29,945	91,014
Trend	Indexed	100	168	227	159
Price Undercutting	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	949	-2	-82
Price Undercutting	% of LV	***	***	***	***
Price Undercutting	Range	15-25	110-120	Negative	Negative

58. It is noted from the aforesaid table that imports of the subject goods from the subject country have been entering Indian market at a price higher than the net sales realisation of the domestic industry, resulting in negative price undercutting during the POI. It has been contended by the domestic industry that negative price undercutting does not suggest absence of injury as held in many investigations and the real concern of the domestic industry is that the landed price of imports is even below the cost of sales of the domestic industry which has prevented any increase in prices which would have taken place in the absence of dumped imports.
59. It has been further stated by the domestic industry that even though the price undercutting has been negative at average price of imports, price undercutting would be positive considering the imports made by beverage producers like PepsiCo India/Coco Cola India who have claimed to be imported at higher prices. In this regard, the Authority has also examined the price undercutting separately for PepsiCo India/Coco Cola India and other

importers, based on information from DG System data and it is noted that price undercutting has been positive in case of imports made by parties other than PepsiCo India & Coca Cola India.

Table - 8

Particulars	MT	Landed value	NSR	Under-cutting	Under-cutting (%)	Range
PepsiCo India & Coca Cola India	***	***	***	***	***	Negative
Others	***	***	***	***	***	15-25
Total	***	***	***	***	***	Negative

60. The information as above show that price undercutting has been positive in case of imports made by parties other than PepsiCo India & Coca Cola India.

b) Price suppression/depression

61. In order to determine whether the effect of imports depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the Authority has examined the changes in the costs and prices of the domestic industry over the injury period in light of the landed price of dumped imports as below:

Table - 9

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Cost of Sales	₹/MT	***	***	***	***
	Indexed	100	191	233	157
Domestic Selling Price	₹/MT	***	***	***	***
	Indexed	100	300	188	118
Landed Value (Subject Country)	₹/MT	57,319	96,155	1,29,945	91,014
	Indexed	100	168	227	159

62. The information as per the above table shows that while the cost of sales of the domestic industry increased by 57% during the injury period, selling price of the domestic industry increased by only 18% in the same period showing price suppression.

iii. Economic Parameters of the domestic industry

63. Annexure-II to the Anti-dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Anti-dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilisation of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.
64. While disclosing the essential facts on injury and causal link, the Authority has also examined the injury parameters objectively taking into account various submissions made by all the interested parties so far in this investigation so as to address all such submissions as well on their merits.

a) Production, capacity, sales and capacity utilisation

65. The performance of the domestic industry with regard to production, domestic sales, capacity and capacity utilisation was as follows:

Table - 10

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Installed Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	100	100
Production	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	176	191	265
Capacity Utilisation	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	176	191	265
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	73	152	154

66. It is noted that while the capacity available with the domestic industry to produce the subject goods remained the same over the injury period. Production, capacity utilisation and sales of the domestic industry increased between the base year and the POI.

b) Inventories

67. Inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Table - 11

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Opening Inventories	MT	***	***	***	***
Closing Inventories	MT	***	***	***	***
Average Inventories	MT	***	***	***	***
Trend	MT	100	571	1,335	1,719

68. It is noted that inventory with the domestic industry increased by the POI. The inventory at the closing of the POI has been higher than the opening inventory level for the period showing an increase in inventory during the POI. Inventory level during the POI have been substantial in comparison to the volume of domestic sales.

c) Market share in demand

69. Market share of the imports and domestic industry have been examined as below:

Table - 12

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Imports from China PR (Subject Country)	MT	1,137	1,418	2,123	2,025
Trend	Indexed	100	125	187	178
Imports from Other Countries	MT	585	309	252	384
Trend	Indexed	100	53	43	66
Total Imports into the Country	MT	1,722	1,727	2,375	2,409
Trend	Indexed	100	100	138	140
Domestic Sales of Petitioner	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	73	152	154
Domestic Sales of Supporters	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	146	127	150
Domestic Sales of Other Producers	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	172	201
Demand	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	110	149	166
Share in Indian Demand that of:					
Imports from China PR (Subject Country)	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	113	125	107
Total Imports from Other Countries	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	48	29	40
Total Imports into the Country	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	91	93	84
Domestic Sales of Petitioner	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	66	102	92
Domestic Sales of Supporters	%	***	***	***	***

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Trend	Indexed	100	132	85	90
Domestic Sales of Other Producers	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	98	116	121
Domestic sales of Indian producers	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	101	103

70. It is noted from the above table that while the market share of dumped imports in demand for the subject goods in India increased by 7% between the base year and the POI, market share of the domestic industry in the Indian demand declined by 8% in the same period. The market share of imports from other sources in Indian demand, however, declined by 60% between base year and the POI. It is evident that the market share of dumped imports continued to increase in the injury period and POI.

d) Profitability, return on investment and cash profits

71. Profits, cash profits and return on capital employed of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Table - 13

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Profit/Loss (PBT)	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	-100	3,619	-1,800	-1,513
Profit/(Loss) before Interest & Tax (PBIT)	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	-100	4,828	-2,336	-1,989
Cash Profit	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	-100	5,139	-2,139	-1,957
Average Capital Employed	₹ Lakh	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	297	492	791
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	-100	1,194	-721	-387

72. It is noted from the above table that the key profitability parameters of the domestic industry showed positive growth between the years 2020-21 and 2021-22 and the profitability thereafter significantly declined during the period 2022-23 and the POI. Resultantly, the profitability in terms of all key parameters such as profit before tax per unit, profit before interest and tax and return on capital employed have been in the negative during the POI. It has been stated by the domestic industry that the dumped imports at prices lower than the cost of sales of the domestic industry has been the cause of such losses and the losses will increase in the absence of present anti-dumping duties.

e) Employment, productivity and wages

73. Employment, productivity and wages of domestic industry over the injury period are given in the table below:

Table - 14

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Employment	Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	170	198	273
Wages	₹ Lakh	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	131	166	267
Productivity per employee	MT/Person	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	104	96	97
Wages	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	75	87	101

74. It is noted that there has been positive growth in level of employment. Also, wages per unit of production increased only marginally by the POI.

f) Magnitude of dumping margin

75. Magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the imports are being dumped in India. The investigation has shown that dumping margin is positive and significant in the investigation period.

g) Growth

76. The Authority notes that while the growth of the domestic industry with regard to key volume parameters have been positive during the POI except inventory level, profitability parameters show negative growth as can be seen from the table below:

Table - 15

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	POI
Production	%	75.90	8.45	38.90
Sales Volume Domestic	%	-26.63	106.86	1.16
Capacity Utilisation	%	75.90	8.45	38.90
Inventory	%	471.03	133.76	28.79
Employment	%	69.91	16.67	37.50
Selling Price Per Kg	%	199.89	-37.29	-37.23
Cost of Sales Per Kg	%	90.56	-22.29	-32.65
Return on Capital Employed	%	1,293.54	-160.44	-46.42
Profit per Unit	%	3,713.37	-149.74	-15.94
PBIT Per Unit	%	4,930.17	-148.38	-14.84

77. The domestic industry claimed that the negative growth in the profitability parameters is the fall out of dumped imports at prices lower than the cost of the domestic industry.

h) Ability to raise capital investments

78. The Authority notes that the domestic industry has made further capital investments through the year 2022-23 and 2023-24 to upgrade the existing plant to produce the subject goods so as to be compatible with the new Schedule M requirements under the Drug Rule, 1945 as amended and as implemented with effect from 28th December, 2023. It is also noted that the ROCE from such investments already made to produce the subject goods remained negative except one year in the entire injury period including the POI. Continuation of losses may have negative influence on the ability to raise further capital investments.

i) Factors affecting domestic prices

79. The examination of the import prices from the subject country, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market, etc. shows that the landed value of imported material from the subject country is below the cost of sales of the domestic industry, causing price suppression effects. It is also noted that the demand for the subject goods was showing significant increase during the injury period and therefore it could not have been a factor affecting domestic prices. Thus, it can be noted that the principal factor affecting the domestic prices is the dumped imports of the subject goods from the subject country.

H. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

80. As per the AD Rules, the Authority, *inter alia*, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, *inter alia*, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry.
81. While the present investigation is a sunset review and causal link has already been examined in original investigation, the Authority examined whether other known listed factors have caused or are likely to cause injury to the domestic industry. In particular, the Authority has also examined if the removal of duties is likely to result in the continuation/recurrence of injury to the domestic industry at appropriate section in this notification.

a) Volume and price of imports from third countries

82. The Authority notes that imports from countries other than subject country are insignificant or the imports have been at high prices. Therefore, imports from third countries cannot be the reason for the injury suffered by the domestic industry. Being a sunset review, imports from subject country alone is relevant for this investigation.

b) Export performance

83. The Authority has considered the data for domestic operations only for its injury analysis. In any case, there have been an increase in exports made by the domestic industry during the POI which is provided in the table below:

Table - 16

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Export Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	276	211	439

c) Contraction in demand Changes in pattern of consumption

84. It is noted that the demand of the subject goods has increased over the injury period. Thus, it can be noted that the injury to the domestic industry was not due to contraction in demand to any significant level.

d) Trade restrictive practices of and conditions of competition

85. The import of the subject goods is not restricted in any manner and the same are freely importable in the country. No evidence has been submitted by any interested parties to suggest that the conditions of competition between the foreign and the domestic producers have undergone any change.

e) Developments in technology

86. None of the interested parties have furnished any evidence to demonstrate significant changes in the technology that could have caused injury to the domestic industry. The domestic industry has significantly invested recently to adopt good manufacturing practices and requirements of premises, plant and equipment for pharmaceutical products.

f) Changes in pattern of consumption

87. The subject goods produced by the domestic industry and that imported into India are comparable and the end users find these goods interchangeable. Possible changes in pattern of consumption are not a factor that could have caused claimed injury to the domestic industry.

g) Performance of the domestic industry with respect to other products

88. The Authority notes that the performance of other products being produced and sold by the domestic industry has not affected the assessment made by the Authority of the domestic industry's performances concerning the subject goods. The information considered by the Authority is with respect to the PUC only.

h) Productivity of the domestic industry

89. Productivity per employee as assessed has not shown any significant changes during the injury period. Thus, the Authority notes that deterioration in productivity as such has not been any cause of injury to the domestic industry.

I. Magnitude of Injury Margin/Price Underselling

90. The Authority has determined Non-Injurious Price (NIP) for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the

raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed.

91. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject country, the Authority has determined the landed price based on facts available.
92. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority.

Table - 17

Injury Margin Table

Sl. No	Country	Producer	NIP US\$/MT	Landed Value US\$/MT	Injury Margin US\$/MT	Injury Margin (%)	Injury Margin (Range %)
1.	China PR	M/s Shandong Ensign Industry Co., Ltd.	***	***	***	***	Negative
2.	China PR	M/s Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd.	***	***	***	***	40-50
3.	China PR	Any other producer	***	***	***	***	60-70

J. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY**J.1. SUBMISSIONS BY OTHER INTERESTED PARTIES**

93. The submissions made by the other interested parties have been as follows:
 - i. Termination of anti-dumping duty after a period of 5 years is the norm. Continuation of duty is an exception to the norm. There do not exist any circumstances calling for invoking the exception under Rule 23(1B) to continue the anti-dumping duty in the present review.
 - ii. In the present case, Anti-dumping duty has been in force for close to ten years. The economic situation of the domestic industry has significantly improved since then. Also, the petitioner has increased its capacity utilisation astonishingly (100 to 265 indexed points). This alone clearly shows that anti-dumping duty imposed on the subject imports has served its purpose.
 - iii. The petition filed by the domestic industry in the present case failed to show any positive evidence to support the initiation of the present sunset review. The instant petition does not substantiate the need for initiation of review since the domestic industry has already recovered from the past injury on account of duties that have been in force.
 - iv. The application has been filed based on the facts that there is continuing injury. There is no injury currently faced by the domestic industry. Consequently, the basis of filing the application is itself bad and the investigation must be terminated.
 - v. The petitioner has not provided sufficient evidence to prove likelihood of dumping and injury. Mere increase in import volume post imposition of anti-dumping duty is insufficient to establish the likelihood of dumping and injury post cessation of the anti -dumping duty especially when the increase in imports is accompanied by a corresponding increase in domestic demand alongside limited capacity of the applicant.

- vi. The petitioner is required to provide positive evidence to show that there is likelihood of continuance or recurrence of dumping and injury. Reference may be placed on WTO Appellate Body's decision in the matter of United States - Sunset Review of Anti-Dumping Duties on Corrosion-Resistant Carbon Steel Flat Products from Japan (WT/DS244/AB/R) and WTO Appellate Body's decision of United States - Anti-Dumping Measures on Oil Country Tubular Goods from Mexico (WT/DS282/AB/R).
- vii. The laid down procedures in the 'Manual of Operating Practices for Trade Remedy Investigations' issued by the Director General of Trade Remedies should be taken into account to determine the likelihood of continuance or recurrence of dumping and injury, based on positive evidence submitted by the domestic industry.
- viii. The Authority is further requested to review the data of volume and value of imports during the period post the POI in terms of Paragraph 17.30 of the Trade Remedies Manual of Operating Practices.
- ix. In case of the 2nd SSR for PVC Flex Film, the CESTAT held that the burden was on the petitioner to place on record sufficient and reliable evidence during the course of investigation to justify the likelihood of continuation of dumping and injury upon cessation of ADD. The CESTAT held that the determination cannot be based on guess work or on mere assumption or presumption but should be based on some tangible and positive evidence.
- x. Merely because the subject country has high export potential does not necessarily mean that these countries have any excess or idle capacity available for utilisation and export of the PUC, particularly to India.
- xi. The petitioner has not provided any evidence whether by way of market intelligence or other sources to suggest that once Anti-dumping duty ceases to exist, producers from subject country will immediately start exporting PUC to India at dumped prices.
- xii. The Authority may verify the capacities available with the producers based on the data submitted in this investigation to establish that there is no likelihood of exports from the subject country to India and thus, no likelihood of recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
- xiii. Regarding the cases cited by the petitioner pertaining to the ADD investigations by the USA and the EU, the scope of the PUC in those cases was very wide and included the PUC in the subject investigation. As a result, the capacities quoted in those cases comprise the capacities of not only the PUC but a large family of other citrates as well. So, the capacities quoted in those investigations are not relevant for the subject investigation.
- xiv. Mere existence of surplus capacities is not sufficient to establish the likelihood of recurrence of injury.
- xv. There is no incentive to shift exports to India and it is denied that Indian market remains attractive. Since the Anti-dumping duty has been in force for about ten years, the petitioner has already consolidated and strengthened its market position in the absence of effective competition from imports.
- xvi. Given the limited demand in India in the range of 20,000-22,000 MT, and a well-settled domestic industry coupled, the Indian market does not appear to be any attractive. Even if the producers from China PR divert their production to India, it will barely make a dent in their capacity utilisation.

J.2. SUBMISSIONS BY THE DOMESTIC INDUSTRY

94. The domestic industry made the following submissions:
- i. PUC continues to be exported to India at dumped prices from subject country and there are enough grounds which suggest such dumping will continue in the event of expiry of present duties.
 - ii. While volume parameters of injury such as production, sales and capacity utilisation developed positivity in the injury period and by the POI, there has been increase in inventory level and the capacity remained stagnant and underutilized. Market share of dumped imports increased between base year and the POI which shows the possibility of such market share registering spurt in case of expiry of present duties.

- iii. Price parameters such as profits, ROI and cash profits has been negative during the POI and price suppression and cost undercutting is very evident. Thus, the domestic industry continued to suffer injury and the cause of such injury has been persistence of dumped import at price suppressing levels and at lower than the cost and NIP of the domestic industry. Situation will get aggravated in the event of expiry of present ADD.
- iv. Dumping and consequent injury as evident in the present investigation is very likely to intensify from the subject country and there is likelihood of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of existing anti-dumping duty.
- v. Exports of subject goods from China PR are attracting anti-dumping and countervailing duties in other major markets like EU (ADD) and USA (ADD and CVD) after 2nd sunset review and it is very probable that expiry of present ADD in India in such a situation will auger well only for the exporters from China PR. ADDs have been levied also by Brazil, Thailand, Russia etc. Authority took cognizance of such duties at the time of first SSR also. The scope of PUC in jurisdictions like EU and USA covers Sodium Citrate though they have a wider product scope.
- vi. Available information shows that the producers in China PR has sufficient freely disposable capacity to the tune of 6-7 Lakhs MT which is 30-35 times of the total Indian demand. Such excess material will be diverted to India in case the ADD is expired. There is no information submitted by any parties to disprove the claims on excess capacity in China PR as presented by the applicant and the claims of the applicant on excess capacity etc. are backed by evidences.
- vii. Expiry of the ADD at this juncture will amount to handing over the robust Indian market with about 19,000-20,000 MT demand to the producers from China PR who are actually grappling for market opportunities in view of the excess and unutilized capacities and also hefty ADD/CVD in EU, USA etc. along with other tariff barriers in USA. ADD/CVD in such market are still in force since last extension with effect from January (USA) and April 2021 (EU) for another five years.
- viii. The anti-dumping duty is required to be extended further for a period of five years on China PR with due enhancement in quantum of duties. Current quantum is not sufficient to effectively counteract dumping. Responding producers must not get any nil duty even if they show negative margins as long as there is likelihood of dumping and injury and the focus should be on likelihood analysis for China PR as a whole which is a settled position of law and practices by the Authority.
- ix. Information for the post POI period also shows continued dumping and injury margin at significantly positive levels which is an indicator of likely situation in case of expiry of present duties. The fall in price of import during the post POI period have been much higher than the fall in key raw material price which is a strong indicator of dumping still being practiced in the export of subject goods to India by producers from China PR.
- x. Application filed by M/s Daffodil Pharmachem Private Limited demonstrates the need for continuation of anti-dumping duties on imports of subject goods from China PR for another 5 years as likelihood of dumping and injury from such imports in the event of expiry of existing anti-dumping duties is very evident.
- xi. The requirements of Section 9A (5) of the CTA, 1975 read with rules governing review under Rule 23 (1B) have been interpreted by the Hon'ble CESTAT in the matter of Borax Morarji Limited vs Designated Authority wherein it was observed that the expression "likely to lead to recurrence" would take within its fold situation where the dumping and injury may not exist at the time of review due to the imposition and continuance of anti-dumping duty which, if allowed to cease to have effect on the expiry of five years, is likely to lead to recurrence of dumping and injury. Thus, ADD is liable to be continued even if there is no current dumping and injury and the requirement is factors showing likelihood of dumping and injury.
- xii. In matters like third-sunset review investigation of anti-dumping duty imposed on import of "Flat Base Steel Wheels" originating in or exported from China PR and final finding dated 12th June 2023, duties were continued where there have been no imports from the subject country and there has been no injury to the domestic industry due to dumped imports.
- xiii. Citric acid is the main raw material to produce the subject goods. As of now, India imports citric acid as the production of citric acid faced shutdown in India after apparently failing to get ADD imposed on dumped

- imports of citric acid into India in the year 2005. The 2005 finding shows the Authority did not recommend ADD by citing improvements in performance by the POI of the said investigation even though the industry was in losses. India is now net importer of citric acid and it is our apprehension that similar thing can happen to producer of subject goods if the ADD has to expire given the excess capacity in China PR is concerned.
- xiv. Likelihood of dumping and injury needs to be seen *qua* the subject country and not *qua* the responding exporters alone. Thus, even if the responding exporters show absence of likelihood of dumping and injury concerning their exports, a country wide determination of likelihood alone is relevant.
- xv. The responding exporters have not shown absence of likelihood of dumping and injury and the response is deficient in terms of relevant information essential to determine likelihood concerning exports of subject goods from China PR to India. The responding exporters have left the information sought on crucial aspects in the EQR relevant for likelihood analysis blank by stating such information is not applicable.
- xvi. Any negative margin in the POI is not a factor to discontinue the ADD in an SSR and what is relevant is examination of likelihood. Thus, as long as there is likelihood of dumping and injury from exports of subject goods to India, the ADD on responding producer namely M/s Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd. is also liable to be continued. Such is the view taken by the Authority in the past in matters like SSR concerning Clear Float Glass.
- xvii. The dumping margin determined in respect of the subject country in the original investigation and in the first sunset review and also in the present application indicates that the dumping found earlier still continues and the producers/exporters of the subject goods from China PR have not stopped the practice of dumping of subject goods in the Indian market.
- xviii. The capacities for subject goods in China PR are evidently setup for export purposes as the domestic demand in China PR is not even 24% of the total available capacity in China PR, as found by EU authority. This indicates the fact that export of subject goods shall continue from China PR in the event of expiry of present duties and there is likelihood of enhanced exports at dumped rates should the ADD in force expire. Export orientation is evident.
- xix. Allowing the expiry of existing ADD by India when there are such measures put in place by other countries still force, shall lead to further increase in exports to India at dumped rates which also shows likelihood of dumping in all probability in the event of expiry of present duties.
- xx. The response by the responding exporters shows that they expect their exports to go up in the coming period and the projection as per Attachment III to the response shows exports to India by them is expected to move from 100 indexed points in the year 2021 to 300 points in the year 2025 in case of M/s Shandong Ensign Industry Co., Ltd. In case of M/s Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd. the projection is 100 indexed points to 69 points in the POI and it is projected as 90 indexed points till 2025. Thus, the exporters are focused on exporting more to India and any expiry of the ADD will be a windfall opportunity for them.
- xxi. The dumped imports of subject goods from China PR continued throughout the injury period and during the POI and the imports in fact almost doubled by the POI over the base year. The share of such dumped imports in Indian demand also has increased by the POI which suggests that such imports will increase substantially if the ADD has to expire.
- xxii. The inventories of subject goods in subject country have been found at very significant levels in the first sunset review based on the information shared by cooperating exporter itself and China PR has large readily available inventories for the product which can be easily diverted to India in the event of expiry of present duties. It is estimated that China PR has a minimum of 5-10% equivalent of its production as running inventory which would be in the range of 70,000 MT to 1,40,000 MT in absolute terms.

J.3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

95. The present review is a sunset review of anti-dumping duties imposed on the imports of the PUC from China PR. Under the AD Rules, the Authority is required to determine whether cessation of existing duty is likely to lead to continuance or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
96. The Authority has examined the likelihood of continuation or recurrence of injury considering the requirement laid down under Section 9A (5), Rule 23 and parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure - II (vii) of the Rule, and other relevant factors brought on record by the interested parties.
97. There are no specific methodologies available to conduct such a likelihood analysis. However, Clause (vii) of Annexure II of the Rules provides, *inter alia*, for factors which are required to be taken into consideration, viz.,
- A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation.
 - Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports.
 - Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices and would likely increase demand for further imports; and
 - Inventories of the article are being investigated.
98. The Authority has, *inter alia*, considered the above requirements and following parameters in order to determine whether dumping is likely to recur in the event of cessation of anti-dumping duty, and if so, whether the same is likely to cause injury to the domestic industry. Additionally, the Authority has examined all the relevant information brought on record by the domestic industry and the other interested parties.

a) Significant rate of increase of dumped imports

99. The Authority notes that there has been an increase in the imports of the subject goods from subject country by the POI compared to the base year. The imports of the subject goods from the subject country as noted in this investigation are provided in the table below:

Table - 18

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Imports from China PR (Subject Country)	MT	1,137	1,418	2,123	2,025
Trend	Indexed	100	125	187	178

100. The Authority notes that imports have continued even after imposition of anti-dumping duty and the imports have been on an increasing trajectory. Consequently, if these duties are permitted to lapse, there is a likelihood of increased imports from the subject country.

b) Continued dumping and injury

101. The Authority notes that the imports of the PUC in the current period of investigation are at dumped prices despite anti-dumping duties in existence. It is also noted that the performance of the domestic industry has significantly deteriorated in respect of the profits, cash profits and the return on capital employed.
102. Based on the information made available by the applicant and other interested parties, the Authority notes that there are substantial excess and idle capacities to produce the PUC in the subject country. The domestic industry submitted that the total installed capacities in China PR are in excess of 6-7 lakh MT, whereas the total demand for the subject goods in the country is estimated to be only 19,000-20,000 MT. The details submitted by the domestic industry is noted as follows:

Table - 19

Particulars	Volume
Capacity for the subject goods in China PR as per the USITC/USDOC ³ and EU/EC ⁴ finding.	19.40 lakh MT to 21.88 lakh MT.
Domestic Demand for subject goods in China PR as per EC finding	4.65 lakh MT
Capacity available for export (Capacity minus Domestic demand in China PR)	14.75 lakh MT to 17.23 lakh MT
Exports from China PR (Difference between production @68.75% utilisation minus domestic demand)	8.69 lakh MT to 10.39 lakh MT
Excess/unutilised capacity (Capacity minus Domestic plus export sales)	6.06 lakh MT to 6.84 lakh MT

103. It has been contended by the other interested parties that there is a difference in the scope of PUC between Indian investigation and the definition of the PUC in the EU and USA anti-dumping duty/countervailing duty finding relied upon by the applicant. It is noted in this regard that similar contentions were raised by the other interested parties in the first sunset review investigation also. It is noted that definition of the PUC in such jurisdiction covers the subject goods as defined in the investigation by India and it is evident in the finding by such foreign authorities that such authorities also took cognizance of the investigation by India while examining the likelihood aspect in the conduct of their ADD/CVD sunset review investigation covering Sodium Citrate. It is not shown by contending exporters that how such findings on capacity in China PR is not applicable to Sodium Citrate as defined in the Indian anti-dumping investigation nor there is any information submitted to show that such basis is not fit in the factual matrix of the case.

104. Further, the analysis of the questionnaire response filed by the responding exporters from the subject country shows as follows:

Table – 20

Particulars	Unit	Shandong Ensign	Jiangsu Guoxin	Total of cooperative exporters
Installed Capacity	MT	***	***	***
Production	MT	***	***	***
Capacity Utilisation	%	***	***	***
Domestic Sales	MT	***	***	***
Export Sales to India	MT	***	***	***
Export Sales to Other Countries	MT	***	***	***
Total Exports (India + Others)	MT	***	***	***
Total Sales (Domestic + Exports)	MT	***	***	***
Surplus/Unutilised capacities	MT	***	***	***
Export Orientation – Ratio of export sales to total sales	%	***	***	***
Export Orientation – Ratio of export sales to total sales	% Range	50-60	45-55	45-55
Inventory	MT	***	***	***
Unutilised Capacity in %	%	***	***	***
Inventory as % of Production	%	***	***	***

³ USITC Finding Covers- All grades and granulation sizes of citric acid, sodium citrate, and potassium citrate in their unblended forms, whether dry or in solution, and regardless of packaging type- Investigation Nos. 701-TA-456 and 731-TA-1152 (Second Review) with effect from January 4, 20201.

⁴ EU Finding Covers- Citric acid and trisodium citrate dihydrate- Commission Implementing Regulation (EU) 2021/607 of 14 April 2021.

105. It is noted from the above information that the responding exporters also have significant unutilised capacities and material available in the inventory with them. Export orientation of such producers is also evident with more than half of the total sales to the export markets.

c) Imposition of duties by various countries

106. The domestic industry has submitted that exports of subject goods from China PR continued to attract Anti-dumping measures in EU after the second sunset review and similarly, exports of subject goods from China PR to USA attracts both anti-dumping and countervailing measures and such duties have been also continued after second sunset review. It is also stated in the response by the responding exporters that the PUC has been subjected to anti-dumping duty in European Union, the USA, Brazil, and also special tariff in the USA.
107. The details of such duties are noted as below based on the information on record:

Table - 21

Country/ Measure	Effective date of Last Levy/Extension for 5 years	Description of Product	Duty Quantum
EU/ADD	14 th April, 2021- Commission Implementing Regulation (EU) 2021/607 of 14 April 2021	Citric acid and trisodium citrate dihydrate	15.3% to 42.7%
USA/CVD	January 4, 2021- [A-570-937, C-570-938] Citric Acid and Certain Citrate Salts From the People's Republic of China: Continuation of Antidumping Duty and Countervailing Duty Orders-Federal Register/ Vol. 86, No. 1/ Monday, January 4, 2021	All grades and granulation sizes of citric acid, sodium citrate, and potassium citrate in their unblended forms, whether dry or in solution, and regardless of packaging type	52.22% to 166.34%
USA/ADD	January 4, 2021- [A-570-937, C-570-938] Citric Acid and Certain Citrate Salts From the People's Republic of China: Continuation of Antidumping Duty and Countervailing Duty Orders- Federal Register / Vol. 86, No. 1/ Monday, January 4, 2021	All grades and granulation sizes of citric acid, sodium citrate, and potassium citrate in their unblended forms, whether dry or in solution, and regardless of packaging type.	156.87%

108. The Authority notes that the exporters and producers from the subject country is dumping the PUC into India despite anti-dumping duty in force. The domestic industry has claimed that the dumping behaviors clearly establishes that in the event of cessation of the antidumping duty, the producers/exporters from the subject country will continue to dump the product into India at increased volume levels. It is further noted that the scope of PUC in the other jurisdiction like EU and USA covers the subject goods in the present review.

d) Post POI information

109. Present investigation being a sunset review, it has been intimated to all the interested parties that the Authority may consider post POI information also in this investigation and the interested parties were directed to submit post POI information, if any, in view of the likelihood analysis to be conducted, to which the domestic industry has submitted the following information:

i. Imports of subject goods post POI (As per DGCI&S)

Table - 22

Volume (in MT)					
Country	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	April to Sept. (2024-25)
China PR	1,137	1,418	2,123	2,025	483
Total	1,722	1,727	2,375	2,409	572

Table - 23

Price CIF (₹/KG)					
Country	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	April to Sept. (2024-25)
China PR	53	89	120	84	58
Total	164	132	163	140	148

ii. **Imports of Citric Acid post POI - (As per DGCI&S) (key raw material to produce the subject goods)**

Table - 24

Volume (in MT)					
Country	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	April to Sept. (2024-25)
China PR	92,387	98,703	1,30,156	1,12,096	61,428
Total	94,966	1,00,029	1,31,440	1,17,653	66,302

Table - 25

Price CIF (₹/KG)					
Country	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	April to Sept. (2024-25)
China PR	48.37	100.08	106.38	61.75	60.49
Total	50.07	100.66	107.05	67.83	65.40

110. It is claimed by the applicant based on post POI data that there has been a further reduction in the price of import of subject goods from China PR in the post POI period and the fall in price is about 31% viz., the POI. Also, while the import price of subject goods decreased by 31% in the post POI period comparison to the POI, the fall in price of key raw material that is citric acid has been only about 4%. Domestic industry claimed that such disproportionate fall in price shows dumping still being followed by China PR.

iii. **Dumping and injury margin in the post POI**

111. The applicant claimed positive dumping and injury margin in the post POI period to indicate the likely situation in the absence of existing anti-dumping duties.

e) Attractiveness of the Indian market

112. The applicants have claimed that the Indian market is attractive since there have been continuous increase in demand for the subject goods in India. The demand for the product grew by 66% between the base year and POI which makes India an attractive market for Chinese produce.
113. The applicant has also submitted that India is also a price-attractive market for a significant volume of exports from China.
114. In this regard, the matter has been examined based on the responses of the cooperating producers/exporters from China PR. The Chinese producers are likely to get a better price in India and, the Chinese producers are likely to divert their third countries' exports to the Indian market on account of higher export prices to India in comparison to other countries. The examination of the information on record shows as under:

Table - 26

Particulars	Shandong Ensign	Jiangsu Guoxin
Exports from China to rest of the world at prices below Indian prices - based on responses.	***	***
Indian demand	***	***
Low priced third countries exports in relation to Indian demand	***	***
Low priced third countries exports in relation to Indian demand -% Range	290-300	25-35

f) Imports entering at prices that are likely to suppress or depress the prices of the domestic industry to a significant degree

115. The subject imports are already entering at a price that is below the cost of sales of the domestic industry. It has also been contended in the application that while a drop in price of subject goods from China PR by about ₹28/- per KG was attributable to drop in price of Citric Acid, the actual drop in the price of subject goods from China PR has been ₹36/Kg which shows a higher fall in price by about ₹8/Kg disproportionate to the fall in raw material price. As noted hereinabove, the selling price of the domestic industry did not increase at the same rate as the increase in cost of sales, showing price suppression during the injury period. It is further noted that the landed price of imports has been lower than the cost of sales of the domestic industry during the entire injury period. Such price effects from subject imports are likely to continue in the absence of anti-dumping duties.
116. With regard to the contention that termination of anti-dumping duty after a period of 5 years is the norm and continuation of duty is an exception to the norm, it is noted that the Rule 23(1B) says “*notwithstanding anything contained in sub-rule (1) or 1(A), any definitive anti-dumping duty levied under the Act shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the designated authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead the continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.*” Thus, the duty in force reaches its finality on attaining 5 years period in a situation where no review as envisaged under the Rule is initiated and no conclusion is reached within a reasonable period of time prior to the expiry of that period. In the present matter, a review as envisaged under the Rule 23 (1B) has been timely initiated and there is time available under the Rule to issue any final findings.
117. With regard to the contention that Anti-dumping duty has been in force for close to ten years and the Anti-dumping duty imposed on the subject imports has served its purpose, the Authority notes that the mandate is to continue the duty as long as there is likelihood of dumping and injury and the merits of the present case is addressed at appropriate places in this notification.
118. With regard to the contention that the petition filed by the domestic industry in the present case failed to show any positive evidence to support the initiation of the present sunset review, the Authority notes that the present investigation was initiated based on *prima facie* satisfaction of the evidences relevant to determine likelihood and thereafter it was open for all interested parties to adduce evidences for and against the claims of likelihood. The claims supported by evidences alone are considered relevant in this notification.
119. With regard to the contention that the Authority must review the data of volume and value of imports during the period post the POI in terms of Paragraph 17.30 of the Trade Remedies Manual of Operating Practices, it is noted that interested parties have been directed to provide the post POI information and the information received for this period from the interested parties is part of this notification and such information may form part of conclusions in this matter.
120. With regard to the contention that given the limited demand in India in the range of 20,000-22,000 MT, the Indian market does not appear to be any attractive for the exporters from China PR, the Authority notes that the exporters from China PR held about 10-15% market share in such small overall demand even when the anti-dumping duty was in force which shows attractiveness of the Indian market.

K. INDIAN INDUSTRY’S INTERESTS AND OTHER ISSUES

K.1. SUBMISSIONS BY OTHER INTERESTED PARTIES

121. The following submissions have been made by the other interested parties during the course of the investigation:
- i. Any continuation of duty shall disrupt the existing supply chains from subject country and the domestic users shall have to rely on the mercy of the petitioners who essentially are focused on expanding their export market to the detriment of the domestic market.

K.2. SUBMISSIONS BY THE DOMESTIC INDUSTRY

122. The following submissions have been made by the domestic industry during the course of the investigation:

- i. There is no significant adverse impact on the extension of anti-dumping duties either on the downstream users or on the ultimate end-users and continuation of ADD shall be in the best interest of the producers, downstream users, and public at large.
- ii. The quantum of ADD which was US\$ 367.59/MT in the original investigation is US\$ 96.05 to 152.78/MT currently. Though the subject product is used in wide range of pharma and food/ beverage application etc., the share of the subject goods in the cost of such products are very negligible. The impact of the ADD as sought shall be less than 0.50% on such users which is negligible. Also, there are no users/importers responding in this matter which also shows there are no impact of ADD on subject goods to any bothering levels to such parties.
- iii. The subject goods have one of its major uses in Oral Rehydration Solution (ORS) and it is also used in food items. Some of the examples as below would show that the ADD quantum as sought in the application will not have any major impact on the cost of the users:

Table – 27

Particulars	Units	Value
Retail Price of 21 Gram ORS Sachet	₹/Pc	21.82
Content of Sodium Citrate in 1 Sachet	Gram	2.90
ADD as sought (Injury Margin)	₹/KG	***
Impact of ADD per Sachet	₹/KG	***
Impact of ADD per Sachet	%	***
Trend	Range	0.25-0.35%

Table – 28

Particulars	Units	Value
Retail Price of 100 Gram Amul Cheese	₹/Pc	80.00
Content of Sodium Citrate in 1 Packet	Gram	4.00
ADD as sought (Injury Margin)	₹/KG	***
Impact of ADD per packet	₹/KG	***
Impact of ADD per packet	%	***
Trend	Range	0.10-0.20%

- iv. Indian producers can meet the entire Indian demand and the country is self-reliant for the product. There are no demand and supply gap for the product in India. Also, the product has huge export potential and to take up the export opportunities, a robust and fair domestic market free from dumped imports is essential to ensure the existence of the domestic industry.
- v. India had 6 producers at the time of original investigation which is 11 during the 1st SSR and the present review. Sodium Citrate has the potential to grow even bigger in the years to come and can take up exports also and such growth of the industry shall be in the public interest of the country.
- vi. Citric acid is the main raw material to produce the subject goods. As of now, India imports citric acid as the producers had to close down on account of dumping. Citric acid constitutes about 45-55% of the overall cost of the subject goods and about 620-650 grams of citric acid (SION BP/USP is 0.67 to 0.74) is required while producing 1Kg of Sodium Citrate. After imports of citric acid, producers undertake substantial value addition to the tune of 45-55% and the companies have made substantial investments in the plant and machinery to produce the subject goods. Thus, the country has a substantial manufacturing base and this is not any mere converting industry which must not be allowed to succumb to the pressure of continued dumping.
- vii. Applicant took up substantial investments in the existing plant during the year 2022-23 and also through POI so as to meet the statutory requirements/ guidelines including plant/ process improvisation so that the company can ensure good manufacturing practices as envisaged in the new Schedule M guidelines which is clearly intended for Indian market. Original investments and also additional investments made from time to time including during the injury period will all get vitiated if dumping and injury has to recur on account of expiry of present ADD.

K.3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

123. The Authority has considered whether extension of the present anti-dumping duties on imports of subject goods from China PR shall have any adverse public interest. For the same, the Authority examined whether the extension of the anti-dumping duty on imports of the product under investigation would be against the larger public interest. This determination is based on consideration of information on record and interests of various parties, including domestic industry, importers, and consumers of the product.
124. The Authority issued gazette notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers, and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the consumers to provide relevant information with respect to the present investigation, including the possible effects of the anti-dumping duties on their operations. The Authority sought information on, *inter-alia*, the interchangeability of the product supplied by various suppliers from different countries, ability of the consumers to switch sources, the effect of anti-dumping duties on the consumers, factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by the imposition of the antidumping duties.
125. It is noted that the purpose of anti-dumping measures, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re- establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. The Authority recognizes that the continuation of the anti- dumping duties might affect the price levels of the PUC as well as other downstream products manufactured by using the subject goods in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, the continuation of anti-dumping measures would prevent the decline of the domestic industry that may ensue as a consequence of low-priced imports from the subject county and help maintain competitive market for the consumers of the PUC.
126. It is noted at the outset that none of the users/ importers/ consumers have participated in the present investigation and no submissions have been made by any party to demonstrate that the any continuation of present anti-dumping duties will have any adverse effects on such users and larger public interest of the country.
127. It is evident in the factual matrix of the present case that the country has capacity sufficient to meet its domestic demand and in fact the country has more capacity than demand. The Indian producers also undertook substantial exports during the POI. The Authority notes that the anti-dumping duties are not imposed to block imports, but to create a level playing field in the domestic market. The user industry of the PUC can continue to import at fair prices. The Authority notes that existence of a fair market is necessary for the user industry to avoid being excessively dependent on a single source leading to high chances of future supply chain disruptions.
128. The Authority also notes that the interested parties have not demonstrated how the prices of subject goods have adversely impacted the consumers. On the other hand, the domestic industry has submitted quantified information showing that the impact of the anti-dumping duties as sought on the user industry would be insignificant and less than 0.50% even in major application like pharma and food.

L. POST DISCLOSURE SUBMISSIONS**L.1 SUBMISSIONS MADE BY THE OTHER INTERESTED PARTIES**

129. The following post disclosure comments have been submitted by the other interested parties apart from reiterating their previous submissions:
- i. The Authority should terminate this investigation without again recommending any imposition of anti-dumping duties. If the Authority decides to continue regardless, then the Authority may re-verify the NIP computed for the domestic industry which seems way off the charts compared to the 1st SSR.
 - ii. With regard to scope of the domestic industry and standing, we do not dispute it and request seeking examination of reasons of non-participation by the other producers is to verify profitability of such other producers. If other non-participating producers are in profits, the losses to the petitioner are due to reasons other than dumping.

- iii. The petitioner has not till date provided with a proper NCV of the support letter of any of its supporters i.e., India Phosphate and Sunil Chemicals nor indexed number of supporters is provided.
- iv. Disclosure shows that the petitioner is not suffering injury and is exhibiting favourable outcomes basis various parameters which must be duly considered by the Authority before concluding injury or continuation or likelihood of recurrence.
- v. Disclosure says that the CAPEX in compliance with Schedule M were not specific to domestic sales only but pursuant to entire facility. While, the Authority has excluded certain investments that pertain solely to export performance, we request the Authority that the remaining NFA must be allocated between exports and domestic sales in a logical manner to give due consideration to the fact that export sales have increased 4x in quantitative terms and 9x in value terms.
- vi. The NIP computed has been unreasonably high in the present investigation which we believe is due to the petitioner's misleading reporting of NFA and allocating entire NFA towards domestic sales only.
- vii. The Authority's practice of awarding 22% pre-tax ROI which we believe is not only arbitrary but also excessive in our industry by any stretch of imagination. We request the Authority to rationalize the ROI as per each industry's specific set of circumstances rather than applying a blanket rate of 22%.
- viii. The principle of progressive liberalization under Article 11.1 of the WTO Anti-dumping Agreement requires that anti-dumping duties remain in force only as long as necessary to counteract injurious dumping. The extensive protection already received by the domestic industry runs counter to this principle.
- ix. While the Authority has concluded that imports are on an increased trend, it has erred in not considering that over 60% of those imports are to those specific entities who are buying at non-injurious prices. If such imports are excluded as was done by the Authority in Price Undercutting analysis, the trend is most likely to be downwards or increasing minimally.
- x. Regarding the capacity availability and export orientation, the Authority in Paragraph 103 has acknowledged that the scope of the investigations by EU and USA are wide. However, the Authority erred in casting the onus on the exporters for showing how such findings on capacity in China PR is not applicable to Sodium Citrate as defined in the Indian anti-dumping investigation. This is against the view of CESTAT in case of 2nd SSR on PVC Flex Film wherein it was said the burden was on the petitioner to place on record sufficient and reliable evidence to justify the likelihood of continuation of dumping and injury upon cessation of ADD.
- xi. As regards the unutilized capacities and export orientation, the Authority has not considered the fact that substantial part of such exports by the respondents are to such entities like PepsiCo and Coca Cola which do not cause any injury to the domestic industry.
- xii. If the Authority nonetheless decides to continue imposition of duty, M/s Shandong Ensign Industry Co., Ltd must be awarded duty rates as per the margins determined in the subject SSR investigation. The Authority has in the 1st SSR on the subject goods awarded fresh margins to the participating entities and the Authority has followed similar practice in anti-dumping investigations like Glass Fibre and Articles thereof from China PR, Aluminium Foil from China PR.

L.2 SUBMISSIONS MADE BY THE DOMESTIC INDUSTRY

130. The following post disclosure comments have been submitted by the domestic industry apart from reiterating their previous submissions:
- i. Negative injury margin for M/s Shandong Ensign Industry Co., Ltd during the POI as per Disclosure should not lead to any nil duty for the said producer as the present investigation is a sunset review investigation. Shandong in any case shows positive injury margin in the post POI period.
 - ii. Negative injury margin during the POI of a sunset review cannot be any ground to fix nil duty for the exporter like in a fresh investigation since there are evidences in the Disclosure which demonstrates likelihood of dumping and injury in case of exports of subject goods by the said exporter and also from China PR as a whole.

- iii. Views taken by the Hon'ble CESTAT in the matter of Thai Acrylic Fibre Ltd. vs. Designated Authority is applicable in the facts of the present matter. Hon'ble CESTAT observed as follows in the said matter:

"14. Sunset review entails a likelihood determination in which present levels of dumping is obviously not so relevant as is the likelihood of continuance or recurrence of dumping. Moreover, during the investigation period, the anti-dumping duty would be in force and hence, the current level of dumping may be non-existent or minimal. The exporters under investigation may also sell at a non-dumped price during this period knowing fully well that a sunset review would be in progress. Hence, the criteria under Section 9A (1) that the anti-dumping duty should not exceed the dumping margin would have no practical application for continuance of the duty under Section 9A (5). There is also no such warrant in law under the said Section 9A (5) to do so."
(Emphasis added)

- iv. M/s Shandong Ensign Industry Co., Ltd did not cooperate in the original investigation nor the exporter filed for any new shipper status and as it stands, the ADD applicable on Shandong currently is the residual duty and the exporter should not be suddenly considered for any individual margin in this SSR.
- v. The export price from Shandong has been apparently high during the POI due to supplies to 2 MNC customers and even such prices dropped in the post POI period and nothing stops Shandong from supplying the subject goods at lower prices to other users also in the absence of ADD nor the product sold to such MNCs are any different products.
- vi. Shandong managed its export price to India during the POI to show higher price during the review since the upcoming sunset review was in the knowledge of the exporters. NCV-EQR of Shandong shows that the exporter only increased its price to India by 27% between base year and POI and for the other countries, prices were reduced by 16%. Even in the domestic market of China PR, the said exporter reduced its price by 28%. This shows the price increases to Indian market alone is very doubtful and apparently done to show a high price to influence the export price during the present review.
- vii. It is evident from the import data that while the price from Shandong was about ₹ 98/Kg between April, 2023 and the first week of February, 2024, the price from the said exporter is only ₹ 74/Kg during second part of February, 2024 and till July, 2024. Thus, there is already a fall in price by 24% in the post POI period and this alone shows the fact that the high price apparently claimed by the exporter for the POI is totally unreliable and no individual margin should be determined based on such an inflated and unreliable export price.
- viii. The facts as disclosed shows high export orientation, excess capacity, and available inventory with Shandong apart from fall in price during the post POI period. Such facts show strong likelihood.
- ix. Nil duty to M/s Shandong Ensign Industry Co., Ltd when its price has already tumbled by 24% at an average level for the end part of POI and post POI period shall render any continuation of ADD in this matter totally redundant and the whole Indian market will be bestowed to M/s Shandong Ensign Industry Co., Ltd.
- x. It is essential to continue the ADD on M/s Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd, who got an individual margin earlier, on ground of likelihood now. Facts also shows high export orientation, excess capacity, high inventory levels etc., for Jiangsu also.
- xi. Disclosure clearly shows attractiveness of the Indian market and substantial volume of third country exports which are made at prices lower than prices to Indian market. Such lower priced exports will be immediately diverted to India in case of expiry of present duties or in case of nil duty to one exporter.
- xii. Situation of exporters in China PR demonstrates very strong likelihood of dumping and injury in the event of expiry of present duties. Apart from the country wide excess capacity and export orientation coupled with ADD/CVD in other jurisdiction against the exports of subject goods from China PR, the responding exporters also have significant unutilized capacity and export orientation is more than 50% and attractiveness of Indian market in case of such responding exporters itself is extremely high in the range of 25-300%.

- xiii. NIP determined for the domestic industry needs some reconsideration especially for the fact that majority amounts from working capital claims have been disallowed while determining NIP. Disallowance of majority of working capital as claimed has drastically reduced the NIP which is not justified in the overall facts of the present matter. There are other expenses also disallowed which must be reconsidered.
- xiv. The Authority may confirm the views taken in the disclosure statement regarding PUC, Like Article and Domestic Industry and standing while issuing final finding in this matter. The facts clearly show that the applicant has the required standing under Rule 2(b).
- xv. Product under consideration continues to be exported to India at dumped prices from subject country and the facts as disclosed suggests such dumping will continue in the event of expiry of present duties.
- xvi. Injury to the domestic industry both in terms of volume and price parameters is very apparent and the Authority may conclude that the domestic industry suffered material injury in this matter. There is price suppression and it is also evident that even price undercutting has been positive in case of imports by importers other than 2 MNC beverage makers.
- xvii. Such dumping and consequent injury is very likely to intensify from the subject country and there is likelihood of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of existing anti-dumping duty.
- xviii. There is no significant adverse impact on the extension of anti-dumping duties either on the downstream users or on the ultimate end-users and continuation of ADD shall be in the best interest of the producers, downstream users, and public at large. Indian producers can meet the entire Indian demand and the country is self-reliant for the product. There are no demand and supply gap for the product in India.
- xix. The supporting producers also reiterated their views earlier submitted and requested continuation of anti-dumping duties on subject goods from China PR.

L.3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY

131. The Authority notes that post-disclosure comments/submission made by the interested parties are mostly reiterations of their earlier submissions, which have already been examined suitably and adequately and properly addressed in the disclosure statement or in relevant paras of the present finding. The Authority further considers as follows with regard to the new comments/ issues raised by the interested parties:
- i. As regards the argument that if the Authority decides to continue the antidumping duties regardless, then the Authority may re-verify the NIP computed for the domestic industry which seems way off the charts compared to the 1st SSR, the Authority notes that determination of NIP is undertaken in the facts of each investigation as per the principles enshrined in Annexure III of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping duty on Dumped Articles and for determination of Injury) Rules, 1995.
 - ii. As regards the argument that the other Indian producers have not submitted the injury data, the Authority notes that determination of eligibility of the applicant as domestic industry is carried out as per Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules and determination of injury to the domestic industry are determined based on the principles enshrined in Annexure II to Rule 11 of the Anti-dumping Rules. Having determined that the applicant satisfies the requirements of “domestic industry”, the requirement thereafter is to determine injury concerning the “domestic industry” which has been done in the present investigation.
 - iii. As regards the argument that the petitioner has not till date provided with a proper NCV of the support letter of any of its supporters, the Authority notes that the support letters have been provided by other 3 supporting producers in the context of determination of standing and the details of production as per such letters have been considered by the Authority for calculation of total Indian production. It is further noted that the disclosure contained adequate summarised information on share of petitioner and other parties in total Indian production and it is further noted that such details have been provided in the application also.
 - iv. As regards the argument that disclosure shows that the petitioner is not suffering injury and is exhibiting favourable outcomes based on various parameters, which must be duly considered by the Authority before concluding injury or continuation or likelihood of recurrence, the Authority notes that the final views taken in this finding *ipso-facto* addresses the comments of the opposing parties on dumping and consequent injury

to the domestic industry.

- v. As regards the argument that while the Authority has excluded certain investments that pertain solely to export performance for the purpose of calculation of capital employed, and the remaining NFA must be allocated between exports and domestic sales in a logical manner, the Authority notes that as recorded at the time of disclosure itself, detailed examination of capital employed claimed by the domestic industry has been carried out and the capital employed considered for the purpose of NIP calculation has been done as per the requirements of Annexure III to the Rules.
- vi. As regards the argument that the NIP computed has been unreasonably high in the present investigation which could be due to the petitioner's misleading reporting of NFA and allocating entire NFA towards domestic sales only, the Authority notes that the contention has no merit since the NIP has been determined in accordance with Annexure-III of the AD Rules, 1995 and the consistent practices of the Authority.
- vii. As regards the argument that the Authority's practice of awarding 22% pre-tax ROI is not only arbitrary but also excessive, the Authority notes that the return of 22% on capital employed is applied in all cases as per the consistent practice of the Authority including the original and first sunset review concerning imports of the subject product.
- viii. As regards the argument that the principle of progressive liberalisation under Article 11.1 of the WTO Anti-dumping Agreement requires that anti-dumping duties remain in force only as long as necessary to counteract injurious dumping, the Authority notes that the conclusions reached in this final finding is self-explanatory on such issues and explains the need for further continuation of the existing anti-dumping duties.
- ix. As regards the argument that while the Authority has concluded that imports are on an increased trend, and it has erred in not considering that over 60% of those imports are to those specific entities who are buying at NIP, the Authority notes that for the purpose of examination of trend of imports of subject goods into India, total imports of subject goods into India is relevant and the injury margin from such imports are noted as positive during the POI.
- x. As regards the argument that the Authority has acknowledged that the scope of the investigations by EU and USA are wide, and it has erred in casting the onus on the exporters for showing how such findings on capacity in China PR is not applicable to Sodium Citrate as defined in the Indian anti-dumping investigation, the Authority notes that the observation of casting any onus on exporters is not correct. In this regard, it is noted that the exporters have objected to consideration of facts available in the findings by EU/USA, which included the subject goods, without substantiating the basis of such objections. It is further noted that consideration of such findings enables access to information pertaining to narrowest group or range of products including the subject goods which is permissible in light of Para (vi) of Annexure II to the Rules which is in line with Article 3.6 of the Anti-dumping Agreement.
- xi. As regards the argument that substantial part of exports by the respondents are to such entities like PepsiCo and Coca Cola which do not cause any injury to the domestic industry, the Authority notes that the dumping and injury examination has been conducted based on the total imports of the subject goods to India and the outcomes are discussed at appropriate places in this finding which does not support the observations of the opposing parties here.
- xii. As regards the argument that if the Authority nonetheless decides to continue imposition of duty, M/s Shandong Ensign Industry Co., Ltd must be awarded duty rates as per the margins determined in the subject SSR investigation, it is noted that the claim has been addressed at appropriate section in this finding.
- xiii. As regards the arguments of domestic industry concerning determination of NIP, it is noted after due examination of the comments that no revision in NIP determine is essential since the NIP disclosed has been determined in accordance with Annexure-III of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 and as per the consistent practice of the Authority. There are no new facts brought on record to reconsider such determination either.

M. CONCLUSIONS

132. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority, as recorded in the above findings, and on the basis of above analysis of the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, the Authority concludes as follows:
- a) The product under consideration is “Sodium Citrate” originating in or exported from China PR. It is a chemical compound that comes in the form of monosodium citrate, disodium citrate and tri-sodium citrate. The product under consideration can also be transacted by the following alternate names:- a. Sodium Citrate b. Tri Sodium Citrate c. Tri Sodium Citrate dihydrate d. Sodium Citrate dihydrate e. Tribasic Sodium Citrate f. Sodium Citrate Tribasic Dihydrate g. Sodium Citrate Dibasic Sesquihydrate h. Sodium Citrate Monobasic Bioxtra.
 - b) The product produced by the domestic industry is like article to the product imported from China PR.
 - c) The applicant namely M/s Daffodil Pharmachem Private Limited constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b). Further, the request for extension of anti-dumping duty was supported by three other producers namely M/s India Phosphate, M/s Sunil Chemicals and M/s Wang Pharmaceuticals & Chemicals.
 - d) The application contained all the information relevant for the purpose of initiation of the sunset review. Further, the applicant provided all information considered relevant and necessary by the Authority for the purpose of the present investigation.
 - e) Based on the information on record, the normal value, export price and the dumping margin for the subject goods have been determined. The dumping margin determined for exports of subject goods from the subject country remains above *de-minimis* level.
 - f) The volume of dumped imports has increased in absolute terms and in relation to consumption.
 - g) Price undercutting from overall imports is noted as negative. However, it is noted that price undercutting has been positive in case of imports made by parties other than PepsiCo India & Coca Cola India.
 - h) While various volume parameters of the domestic industry improved in the injury period, the price parameters continued to decline during the POI after some positive growths between the base year and the year 2021-22. Also, though there has been an overall positivity in terms of volume parameters, inventory level of the domestic industry increased significantly during the POI. It is also noted that there has been decline in market share of the domestic industry while market share of dumped imports increased during the same period.
 - i) After analysing volume and price effect of dumped imports from subject country, and its impact on the domestic industry, it is noted that the domestic industry has suffered material injury during the present period of investigation.
 - j) There is a likelihood of recurrence of dumping and injury in the event of cessation of anti-dumping duty, as established by the following factors:
 - i. The dumping of the subject goods has continued despite the anti-dumping duties in force.
 - ii. The volume of imports has also remained significant and in fact has increased, in absolute and relative to consumption.
 - iii. The market share of the subject imports has increased and that of the domestic industry declined.
 - iv. There exist significant surplus capacities for the subject goods in China PR, and the surplus unutilised capacities are far in excess of the Indian domestic demand. Such excess capacity is evident even in case of responding exporters.
 - v. The responding producers/exporters in the subject country are holding significant inventories.

- vi. The producers in the subject country are not only dumping in India, but are also exporting the subject goods to third countries at prices that are dumped and injurious, compared to the normal value and non-injurious price based on the information submitted by the responding exporters.
- vii. India is a price attractive lucrative market for the producers from China PR.
- viii. Exports of subject goods attracts anti-dumping duties in EU following the second sunset review and such exports also attracts anti-dumping and countervailing duties in USA following second sunset review. The excess capacities as noted coupled with trade barriers in other countries are likely to increase exports at dumped prices in the event of expiry of present duties.

k) In view of the foregoing, it can be concluded that in the event of expiry of the existing anti-dumping duty, there is every likelihood that the imports of the subject goods from China PR would increase at dumped and injurious prices.

l) The investigation had not brought to light any considerations demonstrating that continuation of anti-dumping duty would not be in the public interest. As noted, India has the capacity to meet the entire demand for the product in India and the existing anti-dumping duties alone is being recommended to be continued on imports of the subject goods from China PR.

133. In view of the above the Authority concludes that there is a clear likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury in the event of cessation of the existing anti-dumping duties, and therefore, the Authority recommends continuation of anti-dumping duties on imports of subject goods from China PR for a further period of five years.

N. RECOMMENDATIONS

134. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all the interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, the exporters, the importers, the users and the other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and the causal link and also on likelihood of dumping and injury to the domestic industry.

135. Having concluded that there is positive evidence of likelihood of dumping and injury if the existing antidumping duties are allowed to cease, the Authority is of the view that the anti-dumping duty in force on the imports of the product under consideration from the subject country is required to be continued further. Considering the facts and circumstances of the case, as established hereinabove, the Designated Authority considers it appropriate to recommend continuation of the existing anti-dumping duties on the imports of the subject goods from the subject country. Accordingly, the anti-dumping duty for producers from China PR are recommended as per duty table below.

136. Having determined that there is likelihood of dumping and injury in the present matter if the existing anti-dumping duty is withdrawn, it is noted appropriate to continue the existing anti-dumping duty on import of subject goods from China PR without any modification in the current quantum of duties keeping in view the factual matrix of the present investigation. However, the Authority also notes that an exporter namely M/s Shandong Ensign Industry Co., Ltd has participated in the present sunset review investigation who did not participate at the time of original investigation or the first sunset review. The exporter has cooperated during the present sunset review and the data submitted by the exporter was also verified by the Authority through desk verification. The Authority has examined the volume and price of exports of the said exporter and it is noted that volume and price of export is representative in nature. In such facts and circumstances, the Authority deems it appropriate to determine individual anti-dumping duty rate for M/s Shandong Ensign Industry Co., Ltd. However, keeping in view the fact that there is a likelihood of dumping and injury in the event of expiry of existing anti-dumping duty in the present investigation, quantum of anti-dumping duty for the said producer/exporter cannot be determined solely based on the principle of anti-dumping duty equal to the margin of dumping or less like in a fresh investigation as provided under Rule 4(1) (d) (i). The current anti-dumping duties applicable on imports of subject goods from China PR covers anti-dumping duty that was determined by the Authority for the cooperating producer/exporter who participated in the first sunset review investigation and also the duties applicable for the non-cooperative producers/exporters. Since the existing anti-dumping duties is being recommended to be continued on the imports of subject goods from subject country in the present sunset review, the Authority deems it appropriate to recommend the existing anti-dumping duty rate applicable for the cooperating exporter for M/s Shandong Ensign Industry Co., Ltd also.

137. Thus, in terms of the provision contained in Rule 17(1)(b) read with Rule 23 (1B) and Rule 23 (3) of the Anti-dumping Rules, the Authority recommends the continued imposition of the existing anti-dumping duties, so as to

remove the likelihood of dumping and injury to the domestic industry. Accordingly, definitive anti-dumping duty equal to the amount mentioned in column (vii) of the duty table below is recommended for the imposition for five (5) years from the date of the Notification to be issued by the Central Government, on all imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.

Duty Table

Sl. No.	HS Code	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Duty (\$/MT)
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
1.	29181520 [#]	Sodium Citrate*	China PR	Any country including China PR	M/s Shandong Ensign Industry Co., Ltd.	96.05
2.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	M/s Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd.	96.05
3.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any other producer other than at Sl. No. 1 & 2.	152.78
4.	-do-	-do-	Any country other than China PR	China PR	Any	152.78

[#] - The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.

* - The description of the goods in the Duty Table above includes the following alternate names as well:- (a). Tri Sodium Citrate; (b). Tri Sodium Citrate dihydrate; (c). Sodium Citrate dihydrate; (d). Tribasic Sodium Citrate; (e). Sodium Citrate Tribasic Dihydrate; (f). Sodium Citrate Dibasic Sesquihydrate; (g). Sodium Citrate Monobasic Bioextra.

138. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the customs under Customs Tariff Act, 1962 and applicable custom duties, except duties levied under Section 3, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time.

O. FURTHER PROCEDURE

139. An appeal against the order of the Designated Authority arising out of this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975.

DARPAN JAIN, Designated Authority